



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219988
CG-DL-E-17062020-219988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942

No. 149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 जून, 2020

प्रकरण संख्या: एडीडी- (ओ आई) 07/2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय – यूरोपियन यूनियन, जापान, यू एस ए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/ प्लेटेड टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 6/9/2019 – डी जी टी आर.— क. मामले की भूमिका

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में।

1. मैसर्स जे एस डब्ल्यू वल्लभ टिन प्लेट प्रा. लिमि. (इसके पश्चात "जे एस डब्ल्यू वल्लभ" के रूप में भी संदर्भित) और मैसर्स द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. (इसके पश्चात "टी सी आई एल" के रूप में भी संदर्भित) (इसके पश्चात "घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक" के रूप में भी सामूहिक रूप से संदर्भित) ने यूरोपीय यूनियन, जापान, यू एस ए और कोरिया गणराज्य (इसके पश्चात "संबद्ध देशों" के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोटेड/ प्लेटेड टिन मिल फ्लेट रोलड इस्पात उत्पादों" (इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" अथवा पी यू सी अथवा संबद्ध वस्तुओं के रूप में संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
2. प्राधिकारी ने इन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक **28 जून, 2019** की अधिसूचना संख्या **6/9/2019** – डी जी टी आर के माध्यम से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लगाया गया तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच आरंभ करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. इसमें नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया है :
 - क) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच आरंभ करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ख) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत में राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2019 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
 - ग) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग एवं अन्य घरेलू उत्पादकों को इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें।
 - घ) प्राधिकारी ने, उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों तथा ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - ङ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
 - च) प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी :

यूरोपियन यूनियन

1. आरसिलर मित्तल बेल्जियम
2. आरसिलर मित्तल फ्रांस
3. थिसेनकूप रासेलस्टेइन

4. आरसिलर मित्तल स्पेन
5. निकोमेट टिनप्लेट

यू एस ए

1. ओहिओ कोटिंग कंपनी
2. यू एस स्टील
3. अरसेलर मित्तल बेरटेन
4. यू एस एस पोस्को

जापान

1. जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन
2. निप्पोन स्टील कोरपोरेशन
3. टोक्यो कोहन कं. लिमि.

कोरिया

1. डोंगबू स्टील कं. लिमि.
2. पोस्को
3. टी सी सी स्टील

छ) इसके प्रतिउत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली को प्रति उत्तर प्रस्तुत किया :

1. जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन, जापान
2. जे एफ ई शोजी ट्रेड कोरपोरेशन, जापान
3. मेटल वन कोरपोरेशन, जापान
4. मारुबेनी इटोचू स्टील (एम आई स्टील), जापान
5. निप्पोन स्टील कोरपोरेशन, जापान
6. निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कोरपोरेशन, जापान
7. आहमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान
8. टेकसूशो क्याबा कोरपोरेशन, जापान
9. टोक्यो टसूशो कोरपोरेशन, जापान
10. अमेरिकन इंटरनेशनल कोरपोरेशन, यू एस ए
11. फेरम एन वी, बेल्जियम (ई यू)

ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक की/ प्रयोक्ता की प्रश्नावलियां भेजीं :

1. मैसर्स श्री राम इम्पेक्स (इंडिया) प्रा. लिमि.

2. जरहक स्टील्स प्रा. लिमि.
 3. शेड्रॉन लिमि.
 4. जी पी ग्लोबल एनर्जी प्रा. लिमि.
 5. मैसर्स न्यू गुजरात टिन सर्किल डिपो प्रा. लिमि.
 6. ओरियंटल कोटेंनर्स लिमि.
 7. मॉर्डन पैकेजिंग
 8. हाई-केन इंड. प्रा. लिमि.
 9. हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमि.
 10. कार्टर कोटेंनर्स कं. प्रा. लिमि.
 11. भारत कोटेंनर्स प्रा. लिमि.
 12. एशियन कोटेंनर्स
 13. स्टैंडर्ड रिटेल प्रा. लिमि.
 14. केरा केन कं. लिमि.
 15. कॉन्स मेनिफेक्चरिंग क.
 16. श्रीनिवास टिन इंडस्ट्रीज
 17. जेन्थ टिन प्रा. लिमि.
 18. पेट्रॉक्स पैकेजिंग (इं) प्रा. लिमि.
 19. मेमरम लिमि.
- झ. प्रतिउत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने जवाब दिया है और आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :
1. हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमि.
 2. आरिक्कॉन इंटरप्राइजीज लिमि.
 3. एशियन कोटेंनर्स
 4. कैरा कैन कं. लिमि.
 5. मरकरी इंडस्ट्रीज लिमि.
- ज. द एसोसिएशन ऑफ टिनप्लेट यूजर्स ने भी जांच की प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किया जिन्हें इस अंतिम जांच परिणाम में शामिल कर लिया गया है और उसका विधिवत समाधान कर लिया गया है।
- ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा जांच के लिए सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- ठ. पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों का लेनदेन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को अनुरोध किया गया था। उसे डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए डी जी सी आई एंड एस के लेनदेन वार आंकड़ों तथा अन्य संगत विश्लेषण पर विश्वास किया है।
- ड. क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों

(जी ए ए पी) तथा इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने के लिए लागत तथा उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ड. इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का आवश्यक मानी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन के माध्यम से भौतिक निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर जहां भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन के साथ वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से विचार किया गया है।
- ण. इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उस सीमा तक जिस सीमा तक आवश्यक माना गया सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से इस पर विश्वास किया गया है।
- त. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 (12 महीने) है। हालांकि क्षति संबंधी जांच की अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और जांच की अवधि को माना गया है।
- थ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 11 अक्टूबर, 2019 को सम्पन्न सुनवाई में अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराये। तदंतर एक अन्य मौखिक सुनवाई निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलाव के कारण 6 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रतिउत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- द. इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/ प्रतिउत्तरों में दिये गये तर्कों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों पर विचार किया गया है।
- ध. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये अनुरोधों को जहां भी संगत पाया गया है, उनका समाधान प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।
- न. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- प. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना दिये जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।
- फ. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 08 मई, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उस प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का समाधान अंतिम जांच परिणाम में किया गया

है। प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए मूल समय सीमा 15 मई, 2020 थी जिसे इन हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर बढ़ाकर 23 मई, 2020 कर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किये गये अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में किया जा रहा है।

ब. इस अंतिम जांच परिणाम में *** इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डॉलर = 69.02 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. इस वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ("पी यू सी") टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद है जिस पर या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ, चाहे रोगन लगाया हुआ हो और/ अथवा प्रिंट किया हुआ हो या नहीं। क्रोमियम/ क्रोमियम ऑक्साइड अथवा टिन की परत चढ़ायी हुई है अथवा मुल्लमा किया हुआ है। टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद में टिन प्लेट तथा टिन मुक्त इस्पात शामिल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ई टी पी) अथवा टिन मुक्त इस्पात (टी एफ एस) अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम की परत चढ़ाया हुआ इस्पात (ई सी सी एस) के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति क्वाइल के रूप में अथवा सीट / स्क्रोल के रूप में किया गया जा सकता है। सीट / स्क्रोल की आपूर्ति बेलेकिंग के साथ अथवा उसके बिना वर्ग, आयात, वृत्त अथवा किसी अन्य आकार सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं, विभिन्न रूपों में की जा सकती है।
5. विचाराधीन उत्पाद का आमतौर पर उपयोग खाद्य पैकेजिंग अर्थात् खाद्य तेल, प्रोसेस किया गया हुआ खाना, फल, सब्जियां, पेय पदार्थ आदि सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं तथा अखाद्य पैकेजिंग अर्थात् रंग, रसायन पदार्थ, अखाद्य तेल, जयामिटि/ कम्पास बॉक्स, जूते की पॉलिश, एसोसोल स्प्रे, बैट्रीरियों आदि के लिए उपयोग किये जाने वाले तरह तरह की पैकेजिंग सॉल्यूशन के लिये किया जाता है।

ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किया गया अनुरोध तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

क) इस वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पी यू सी टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद है जिस पर या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ, चाहे रोगन लगाया हुआ हो और/ अथवा प्रिंट किया हुआ हो या नहीं। क्रोमियम/ क्रोमियम ऑक्साइड अथवा टिन की परत चढ़ायी हुई है अथवा मुल्लमा किया हुआ है। टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद में टिन प्लेट तथा टिन मुक्त इस्पात शामिल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ई टी पी) अथवा टिन मुक्त इस्पात (टी एफ एस) अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम की परत चढ़ाया हुआ इस्पात (ई सी सी एस) के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति क्वाइल के रूप में अथवा सीट / स्क्रोल के रूप में किया गया जा सकता है। सीट / स्क्रोल की आपूर्ति बेलेकिंग के साथ अथवा उसके बिना वर्ग, आयात, वृत्त अथवा किसी अन्य आकार सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं, विभिन्न रूपों में की जा सकती" है।

ख) विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090,

72125020, 72125090 और 72259900 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि विचाराधीन उत्पाद के आयात को इस अधिनियम की कुछ अन्य एच एस कोड अर्थात् 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 में भी देखा गया है।

- ग) यह प्राधिकारी की सतत कार्यपद्धति रही है कि वह विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र में विशेषकर इस्पात उत्पादों को शामिल करते हुए जांचों में प्राथमिक और गौण दोनों वस्तुओं को शामिल करें और उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनके बीच कोई अंतर नहीं करें।
- घ) प्राधिकारी के अनेक जांच परिणाम हैं जिनमें प्राथमिक और गौण दोनों उत्पादों को पी यू सी के विषय क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है। निम्नलिखित जांचों में, प्राथमिक और गौण दोनों गुणवत्ता वाली वस्तुओं को पी यू सी के विषय क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है।

| जांच | जांच की अवधि |
|---|---|
| चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एलॉय अथवा बिना एलॉय के इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पाद" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में। | परिभाषित पी यू सी "इस पी यू सी में फिल्ट क्वाइल में अथवा शीट, ब्लैंक, चाहे उस पर पानी चढ़ाया हुआ हो अथवा नहीं या पानी चढ़ाया हुआ बॉक्स अथवा पानी चढ़ाया हुआ अथवा लगातार पानी चढ़ाया हुआ अथवा किसी अन्य पानी चढ़ाने की प्रक्रिया अथवा पूर्ण रूप से कड़े अथवा आंशिक रूप से कड़े ब्लैंस में कोल्ड रॉड/ कोल्ड कम किया हुआ फ्लैट इस्पात उत्पाद शामिल है। संबंधित उत्पाद में प्राथमिक अथवा गौण गुणवत्ता के अनुरूप कोल्ड रॉड / कोल्ड कम किया हुआ फ्लैट इस्पात उत्पाद चाहे वह रोल्ड किया गया हुआ हो अथवा नहीं शामिल है [..]" |
| चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एलॉय अथवा बिना एलॉय वाले इस्पात का वायर रॉड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में। | वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बार्स एंड रॉड्स, हॉट रोल्ड, लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात अथवा एलॉय इस्पात "सामान्य रूप से वायर राइस" के रूप में ज्ञात स्टील अथवा एलॉय स्टील, अनियमित रूप से लच्छा बनाया हुआ क्वाइल है। ये उत्पाद इलेक्ट्रोड, फ्री कटिंग, फोरजिंग, कोल्ड हैडिंग, निम्न/ मध्यम/ उच्च कार्बन स्टील, ड्राइंग, बाल बेयरिंग स्टील, केस हार्डनिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, जंगरोधी स्टील, विदरिंग स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील और कई अन्य गुण वाले स्टील सहित परंतु वहीं तक सीमित नहीं, इस्पातों की विभिन्न गुणवत्तों के अनुरूप है। [..]" |
| चीन जन. गण. राज्य, कोरिया गणराज्य और मलेशिया के स्टेनलैश स्टील 304 सीरिज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच। | "हॉट रोल्ड आस्टीनेटिक स्टेनलैस स्टील प्रॉडक्स, चाहे वह आयाताकार आकार के प्लेट, शीट अथवा क्वाइल (हॉट रोल्ड पानी चढ़ाया हुआ और पिकल किया हुआ अथवा काला) हो अथवा नहीं, या तो 304 अथवा 304एच अथवा 304एल अथवा 304एन अथवा 304एलएन अथवा ई एन 1.4301, ईएन आई.4307 अथवा एक्स5सीआरएनआई1810 अथवा एक्स04सीआर19एनआई9 अथवा किसी अन्य मानकों में उसका समतुल्य जैसे यू एन एस, डी आई एन, जे आई एस, बी आई एस, इन एन आदि श्रेणी का हो अथवा नहीं; नंबर एक अथवा ब्लैक फिनिश का हो अथवा नहीं; चाहे वह 1650 मिमी. तक की सभी |

| | |
|--|--|
| | चौड़ाई के (मिल ऐज के लिए + 20 मिमी. और ट्रिम ऐज के लिए 5 मिमी. सहनशीलता) तक की चौड़ाई वाले क्वाइल में 1.2 मिमी. से 10.5 मिमी. और प्लेट और शीट में 3 मिमी. से 105 मिमी. की मोटाई वाले मिल ऐज अथवा ट्रिम ऐज के साथ ऐज की स्थिति वाला हो, अथवा नहीं)” |
|--|--|

- ड) वास्तव में, चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और मलेशिया से स्टेनलैस स्टील 304 सीरिज के हॉट रॉलड फ्लैट उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की :
- “इन हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि गौण सामग्रियों को पी यू सी से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद की प्रक्रिया में प्राथमिक और गौण दोनों सामग्रियों को उत्पादन वैश्विक स्तर पर किया जाता है और इस कारण से उनकी बिक्री की जाती है। उनका उपयोग प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग के अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्थापनीय के रूप में किया जाता है। प्राथमिक और गौण वस्तुओं के उत्पादन की लागत अलग अलग नहीं है यद्यपि गौण सामग्री की बिक्री अलग कीमत पर की जा सकती है। रक्षोपाय जांच सहित किये गये पूर्व के सभी जांच इन उत्पादों की प्राथमिक और गौण प्रकृति के आधार पर उत्पाद में अंतर स्थापित नहीं किये। इस कारण से प्राधिकारी को इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों में कोई दम नजर नहीं आता है।”
- च) “यूरोपीय यूनियन और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाएलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट)” और यूरोपीय यूनियन (ई यू) और मैक्सिको के पी वी सी सस्पेंशन रेसिन” के संबंध में पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी ने यह माना कि सेकण्ड ग्रेड/ ऑफ ग्रेड के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे भौतिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया, कच्ची सामग्री, कार्य, उपयोग, उत्पादन की लागत और प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में अलग अलग नहीं हैं।
- छ) भारत में आयात किये गये गौण उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्राथमिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राथमिक उत्पादों का स्थान ले रहा है। एसोशियन ऑफ टिन प्लेट यूजर द्वारा अपने एक अनुरोध में यह मान लिया गया है कि प्राथमिक और गौण दोनों उत्पाद एक ही अंतिम उपयोग के लिए प्रतिस्थापनीय है।
- ज) गौण उत्पाद केवल वे उत्पाद हैं जो निर्माण की प्रक्रिया में ग्राहकों की अपेक्षा पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं और इस कारण से उनका वर्गीकरण विभिन्न नामों जैसे अपशिष्ट, सेकेण्ड, दोषपूर्ण, गौण आदि में किया गया है। गौण टिन प्लेट में प्राथमिक ओवर रन भी है। वास्तव में, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों में यह माना गया है कि आयात की गई गौण सामग्री समान रूप से उतने ही अच्छे हैं, जितना की घरेलू स्तर पर आपूर्ति की गई प्राथमिक सामग्री है।
- झ) संबद्ध वस्तुओं के प्राथमिक और गौण उत्पादों के बीच भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, कार्य, उपयोग, उत्पादन की लागत और प्रशुल्क वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। गौण सामानों को बाहर करने से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की सही स्थिति सामने नहीं आयेगी।
- ञ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में खाद्य पैकेजिंग के लिए गुणवत्ता के अनुकूल होने का अधिदेश दिया है। आईएस 1993:2018 और आईएस 12591:2018 का खंड 7.5.1 सतही कमियों के साथ सामग्री की आपूर्ति की अनुमति देता है और साथ ही इसे नुकसान पहुंचता है जो इस सामग्री को प्रयोक्ता और

उत्पादकों के बीच एक विशेष करार के अध्यक्षीन अभीष्ट उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। इस अपवाद को देखते हुए, गौण पी यू सी का भी उपयोग खाद्य पैकेजिंग अनुप्रयोगों में किया जा रहा है।

- ट) गौण आयातित उत्पादों का उपयोग करने वाले आयातक/ प्रयोक्ता भी घरेलू उद्योग से प्राथमिक उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। यह आगे इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्राथमिक और गौण उत्पादों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है और ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- ठ) इस आधार पर पी यू सी के विषय क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को बाहर किये जाने का भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास इस प्रकार के ग्रेडों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है और इस कारण से उसे बाहर किया जाना चाहिए।
- ड) पी यू सी के विषय क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर किये जाने का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकारी को निम्नलिखित बातों का सत्यापन करने की आवश्यकता है :
- I. क्या वह उत्पाद/ श्रेणी जिसके लिए बाहर किये जाने की मांग की जा रही है का आयात बाहर किये जाने की मांग करने वाले पक्षकारों द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में भारत में किया गया है;
 - II. क्या उस उत्पाद/ श्रेणी जिसके लिए बाहर किये जाने की मांग की जा रही है अथवा बाहर किये जाने की मांग केवल भविष्य में बच निकलने के लिए रास्ता बनाने हेतु किया जा रहा है, का कोई वास्तविक अंतिम उपयोग है और
 - III. क्या हितबद्ध पक्षकारों ने उन उत्पादों/ ग्रेडों जिसके लिए बाहर निकाले जाने की मांग की जा रही है, के लिए घरेलू उद्योग को कोई आदेश दिया है और क्या घरेलू उद्योग ने उसकी आपूर्ति करने में असमर्थता दर्शायी है।
- ढ) हितबद्ध पक्षकार जो पी यू सी के विषय क्षेत्र से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, ने तीन में से किसी भी मानक को पूरा नहीं किया है और अपने किसी भी दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ण) इस आवेदन में प्रस्तुत किये गये उत्पाद विषय क्षेत्र में केवल वे उत्पाद शामिल हैं, जिनका या तो आवेदकों द्वारा उत्पादन किया जाता है अथवा जो एक समान उत्पाद के रूप में अपने उत्पाद श्रेणी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पी यू सी से जिन उत्पादों को बाहर निकाले जाने का अनुरोध किया गया है उनका या तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया है अथवा केवल इस कारण से उत्पादन नहीं किया गया है कि भारतीय बाजार में मांग में कमी के कारण कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं।

| वे उत्पाद/ श्रेणी जिन्हें बाहर किये जाने का अनुरोध किया गया | श्रेणी के उत्पादन पर घरेलू उद्योग की स्थिति |
|--|---|
| 0.15 मिमी. से कम और 0.21 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला डबल रिड्यूज टिन प्लेट | घरेलू उद्योग उन श्रेणियों को उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| 0.18 मिमी. से कम और 0.23 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला सॉफ्ट डबल रिड्यूज टिन प्लेट | घरेलू उद्योग उन श्रेणियों को उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| चमकदार सतह वाला टिन प्लेट | घरेलू उद्योग इस श्रेणियों का उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| 11.2 ग्राम/ वर्ग मी. से अधिक कोटिंग वाला टिन प्लेट | घरेलू उद्योग इस श्रेणियों का उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| 1020 से अधिक चौड़ाई वाला टिन प्लेट | घरेलू उद्योग इस श्रेणियों का उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| 700 मिमी. से कम चौड़ाई वाला टिन प्लेट | घरेलू उद्योग इस श्रेणियों का उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |
| टिन मुक्त इस्पात/ इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट | घरेलू उद्योग इस श्रेणियों का उत्पादन करता है। संबंधित दस्तावेज प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। |

| | |
|--|--|
| पोलिमर से लेमिनेट किया गया टिन प्लेट जो बाफिनोल-ए/ बी पी ए मुक्त हैं | न तो कोई आर्डर उसके लिए घरेलू उद्योग को दिया गया है और न ही उसका कोई आयात किया गया है। भारत में उसकी कोई मांग नहीं है। |
| क्रोमियम मुक्त टिन प्लेट | न तो कोई आर्डर उसके लिए घरेलू उद्योग को दिया गया है और न ही उसका कोई आयात किया गया है। भारत में उसकी कोई मांग नहीं है। |

- त) जापान के उत्पादकों ने गोपनीय पाठ में तकनीकी विनिर्देश दिये हैं। इस प्रकार के विनिर्देशों को अगोपनीय पाठ में नहीं दिया गया है, जिससे की घरेलू उद्योग उस पर टिप्पणी कर सके।
- थ) प्राधिकारी को इन श्रेणियों को बाहर करना नहीं चाहिए जो आयातकों को भविष्य में शुल्कों से बचने में सक्षम बना सके।
- द) प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति रही है कि वह तब तक विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर किये जाने की अनुमति न दे जब तक यह नहीं दर्शाया गया हो कि वह उत्पाद जिसके लिए बाहर किये जाने की मांग की गई है, का वास्तव में बाहर किये जाने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा आयात किया गया है। यह दृष्टिकोण "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्यूमिनियम फॉयल" के संबंध में पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में दिया गया है। आगे इसकी पुष्टि माननीय सेस्टेट द्वारा जी. एम. एलॉय प्रा. लिमि. और अन्य बनाम भारतीय संघ के मामले में की गई जहां माननीय सेस्टेट को इस प्राधिकारी के जांच परिणामों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।
- ध) सामग्रियों जिसके लिए आयातकों द्वारा बाहर किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, के किसी वास्तविक आयात के बिन, यह अनुरोध किया गया है कि उक्त हितबद्ध पक्षकारों का पी यू सी के विषय क्षेत्र से किसी दिये हुए श्रेणी को बाहर किये जाने के लिए अनुरोध करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

ग. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और सामान्य वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध और इस प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :
- क) जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना द्वारा पहचान किये गये विषय क्षेत्र या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ चाहे रोगन लगाया हुआ हो और/ अथवा प्रिंट किया हुआ हो अथवा नहीं टिन अथवा क्रोमियम ऑक्साइड से परत चढ़ाया गया हुआ अथवा मुल्लमा किया हुआ टिन मिल फ्लेट रोलड इस्पात उत्पाद" है
- ख) यह एक स्वीकार किया हुआ तथ्य है कि विचाराधीन उत्पाद की प्राथमिक और गौण वाणिज्यिक रूप से अलग अलग उत्पाद हैं जिनका अलग अलग लागत, बिक्री कीमत और अनुप्रयोग हैं। इस कारण से, प्राथमिक और गौण उत्पाद की तुलना संभव नहीं है।
- ग) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को इस तथ्य को छुपाकर भ्रमित करने की कोशिश की है कि भारत में हो रहे अधिकांश आयात गौण अपशिष्ट श्रेणी हैं जिन्हें नियमित श्रेणी के संबंधित वस्तुओं की तुलना में सस्ता होना माना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात प्रमुख रूप से गौण/ अपशिष्ट सामग्री का होता है। ऐसे परिदृश्य में, कीमत की तुलना और तदंतर क्षति के संबंध में सूचना पर विचार भारत में सही बाजार की स्थिति के द्योतक के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- घ) यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादों की दो मोटी श्रेणियां

हैं (i) मानक विनिर्देशों के अनुसार निर्मित उत्पाद और (ii) ग्राहक विशिष्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये गये टेलर मेड उत्पाद। भारत में निर्यात किये गये उत्पाद दूसरी श्रेणी अर्थात् टेलर मेड उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुछ निर्माता विशिष्ट रूप से निर्यात उन्मुख निर्माण के लिए उक्त टेलर मेड उत्पादों का उपयोग करते हैं। घरेलू उद्योग का उत्पाद प्रथम श्रेणी अर्थात् सामान्य उद्योग के मानदंडों के अनुसार बनाये गये उत्पादों के अंतर्गत आते हैं। घरेलू और आयात किये गये उत्पादों के संबंध में तकनीकी और वाणिज्यिक मापदंडों की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान जांच में कुछ श्रेणियों को बाहर किये जाने का मामला बनता है।

- ड) टिन प्लेट को विशिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए बनाने की प्रक्रिया में, अनेक बार उत्पाद ग्राहकों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि, यह सामग्री अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है और उसकी बिक्री "गौण" उत्पादों के रूप में की जाती है। इस प्रकार की सामग्री मिले जुले विनिर्देशों में हैं और उन्हें उपयोगों के अनुरूप बनाया जाना है। गौण उत्पाद प्रयोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करते हैं जो इस उत्पाद के विनिर्देशों के साथ अधिक लचीले हो सकते हैं और अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर अंतिम उत्पादों का सर्जन कर सकते हैं।
- च) इन मिलों द्वारा नियमित रूप से निविदाओं अथवा नीलामियों के माध्यम से बेचे जाने के लिए इस प्रकार की गौण सामग्री हेतु एक सही बाजार है। इस प्रकार की सामग्री के क्रेता सामान्य रूप से कम मात्रा वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये सामान्य तौर पर कम उपयोग वाला कम परिष्कृत उत्पाद हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं तथा कई अन्य लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार के निर्माता श्रम सघन होते हैं और गौण टिन प्लेट का उपयोग करते हुए इन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कुशल उपयुक्त लोगों को रोजगार देते हैं।
- छ) गौण सामग्री का उपयोग केलेंडर स्ट्रीप्स, जेमेट्री बॉक्स, शू पॉलिस बॉक्स, काजल बॉक्स, लालटेन, हेयर क्लिप्स, स्टाम्प पेड, परदे के रिंग, फाइलन क्लिप्स, मेडल केन्स और केन संघटकों, ऑटो एनसिलेरी पार्ट्स, पेपर क्लिप्स, अगरबत्ती स्टेन, पूजा के सामानों, स्टेनशिल, इमीटेशन ज्वेलरी, विभिन्न उपयोगों के लिए वाटर आदि जैसे कम उपयोग वाले उत्पादों का निर्माण करने के लिये किया जाता है।
- ज) यह नोट किया जा सकता है कि भारत में टिन प्लेट की खपत का लगभग आधा गैर महत्वपूर्ण उपयोग का है जो किसी अन्य इस्पात उत्पादों के मामले में नहीं है। इस प्रकार के गैर महत्वपूर्ण उत्पाद जिनका प्रमुख रूप से उत्पादन लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा किया जाता है, पूरे भारत में पाये जाते हैं और उनके लिए इच्छित अंतिम उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए प्राथमिक टिन प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है।
- झ) ये उद्योग गौण श्रेणी के टिन मिल प्लेट रॉलड इस्पात का उपयोग करते हैं जिसका उत्पादन प्राथमिक श्रेणी के टिन मिल प्लेट रोलड इस्पात के निर्माण के दौरान किया जाता है। चूंकि यह इस्पात ऑफ श्रेणी का होता है और यह बोली के माध्यम से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को उक्त देशों में उपलब्ध है। ये आपूर्तिकर्ता इन लघु उद्यमों को इसकी आपूर्ति करते हैं जिसे आगे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लघु उद्योगों को आपूर्ति की जाती है।
- ञ) आवेदक यह स्वीकार करते हैं कि इस उत्पाद के दो खंड अर्थात् प्राथमिक और गौण होते हैं। टी सी आई एल स्पष्ट रूप से वर्ष 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करता है कि इसका घरेलू बाजार के हिस्से में 68 प्रतिशत प्राथमिक टिन प्लेट है। यदि प्राथमिक और गौण उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं होता तब उनके वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रकार का अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

- ट) इस संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित अनुरोधों के अनुबंध-11 के अनुसार उपलब्ध कराया गया चार्ट घरेलू प्रयोक्ता उद्योग का केवल संक्षिप्त विवरण है। हालांकि, उसे आवेदकों द्वारा इस आशय से गलत तरीके से पढ़ा गया है कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पाद दोनों का उपयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किया जाता है और उसके कारण दोनों का आयात किया जाता है। आवेदकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि खरीद “अधिकांशतः स्वदेशी” है अर्थात् इसकी खरीद घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है और यह आयातों द्वारा प्रभावित नहीं होता है।
- ठ) यूरोप और यू एस ए से गौण उत्पादों की बिक्री संबद्ध देशों में इन उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है। उसकी बिक्री बाजार में नीलामी/ निविदा आधार पर की जाती है। निर्यातक वेयरहाउस में इन मिलों से विनिंग प्राप्त करते हैं और उसे घरेलू बाजारों सहित विभिन्न बाजारों में बेचते हैं। इस कारण से निर्यातक आपूर्ति की जा रही सामग्री के लिए अलग अलग खरीद के आंकड़े उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। वे भार विभाजन हैं (जैसे थोक विक्रेता खुदरा व्यापारी को बेचते समय करते हैं)। समेकित सामग्री नीलामी ककी अवधि के दौरान ली जाती है और उसे अधिकतम कीमत का भुगतान करने वाले क्रेता/ बाजार को बेची जाती है। यह कीमत प्राथमिक उत्पाद की तुलना में कम होती है क्योंकि इनके विनिर्देश अलग अलग होते हैं। क्रेता सामान्य तौर पर लघु इकाइयों होती हैं और उन्हें आकार, मोटाई, विनिर्देश, फिनिश के मामले में समझौता करना पड़ता है और उनका सीमित उपयोग होता है।
- ड) चीन इस पाटनरोधी जांच में उपस्थित नहीं है। ऐसा इसलिए है कि चीन शायद ही गौण उत्पादों का निर्यात करता है क्योंकि उसका उपयोग चीन के भीतर विशेषकर कम विकसित प्रांतों में किया जाता है।
- ढ) आवेदक के उत्पादों और जापान के अधिकांश निर्यातों के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है जो आरंभ में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए कि जापानी मिलों द्वारा निर्यात किये गये उत्पादों से आवेदकों को क्षति नहीं हो सकती है अथवा क्षति होने का कोई खतरा नहीं हो सकता है।
- ण) प्राथमिक और गौण उत्पाद पूर्ण रूप से अलग अलग हैं और इसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक टिन प्लेट जब उसके लिए आर्डर 2018 की आई एस 1993 के खंड 6 और आई एस ओ 11949: 2016 के अनुसार दिया जाता है तब क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होता है। यह मानक इसे अंतिम उपयोग उपलब्ध कराने के लिए 6.2(जी) के अंतर्गत अनिवार्य बनाता है। खंड 6.2 के नोट में इस बात का उल्लेख है कि उपयुक्त इस्पात चयन आकार बनाने संबंधी प्रचालनों जैसे स्टाम्पिंग, ड्राइंग, फोल्डिंग, बीडिंग और बैंडिंग तथा ऐसेम्बली कार्य जैसे ज्वाइंट फार्मिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग पर निर्भर है। खंड 6.3 के अंतर्गत, निर्माता को सूचना उपलब्ध करानी होती है जो आर्डर संबंधी आवश्यकता को इस उत्पाद के अंतिम प्रयोग अनुकूल बनाता है। फेबरिकेशन प्रचालन को महत्व दिया जाता है क्योंकि ये परिष्कृत निर्माण प्रचालनों के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं।
- त) पी यू सी के आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक गौण टिन प्लेट और टिन रहित इस्पात से बनता है। यू एस ए और ई यू से प्रायः सभी आयात गौण हैं। इसलिए घरेलू मिलों के प्राथमिक उत्पादों और आयातित गौण कीमतों के बीच एक गलत तुलना की जा रही है।
- थ) प्राथमिक टिन प्लेट खाद्य अनुप्रयोगों के लिए तथा उच्च गति के उत्पादन लाइनों में उपयोग के लिए है।
- द) भारत गौण टिन प्लेट का एक स्वाभाविक विकल्प है।
- ध) उत्कृष्ट टिन केन और इसके संघटकों के विनिर्माता जापान में निप्पोन स्टील से अपना कच्चा माल

प्राथमिक टिन प्लेट का 50 प्रतिशत आयात करते हैं। निम्नोपनिर्दिष्ट टिन प्लेट की घरेलू कीमतों की तुलना में उच्चतर कीमतों के बावजूद, टिन प्लेट का आयात जापान से किया जाता है और इसकी खरीद घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट गुणवत्ता तथा समय पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने के कारण नहीं की जाती है।

- न) टिन प्लेट यूजर एसोसिएशन स्पष्ट रूप से खाद्य, खाद्य एडिटिव्स और औषधीय उपयोगों के लिए प्रयुक्त टिन प्लेट से संबंधित एफ एस एस ए आई और बी आई एस मानकों का समर्थन करते हैं।
- प) व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन संबंधी कार्य पद्धतियों के डी जी टी आर मैनुअल में इस बात को नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में वे उत्पाद शामिल होने चाहिए जिनका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जाता है और व्यापारिक रूप से बिक्री की जाती है। जापानी मिल यह अनुरोध करता है कि वर्तमान उत्पाद विषय क्षेत्र में वे उत्पाद शामिल हैं जिनका आवेदकों द्वारा व्यापारिक रूप से उत्पादन और निर्माण नहीं किया जा रहा है। तदनुसार, आवेदक द्वारा उत्पादन न की गई और व्यापारिक रूप से न बेचे गए उक्त उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए।
- फ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व की जांचों में सतत रूप से कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों पर संबद्ध देशों से आयात किये गये उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद के बीच समानता का निर्धारण करते समय विश्वास किया है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मानदंड भौतिक और रसायनिक विशेषताएं; उत्पाद विनिर्देश, निर्माण की प्रक्रिया और संयंत्र एवं उपकरण सहित उत्पादन प्रौद्योगिकी; कार्य और अंतिम उपयोग; अंतिम उपयोग आवश्यकता; अंतिम उपयोग धारणा; वितरण और विपणन; तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता हैं।
- ब) विशेषकर, पिछली जांचों में से एक जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वास्तव में विशिष्ट रूप से जांच के विषय क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को बाहर कर दिया है क्योंकि घरेलू उद्योग में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दर्शाया था कि उन्होंने जांच की अवधि में ऐसी श्रेणियों की आपूर्ति की और उन श्रेणियों जिन्हें उनमें निर्यातकों द्वारा बाहर किये जाने की मांग की गई थी, के साथ इसकी श्रेणियों की समदक्षता को नहीं दर्शाया है। इसके अलावा, अन्य जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पी यू सी के विषय क्षेत्र से कुछ उत्पादों को बाहर कर दिया है क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया था।
- भ) टिन रहित इस्पात को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
- म) जापान के उत्पादों की विशेषताएं उन्हें तकनीकी आधारों पर अलग रखती है :
- I. उदाहरण के लिए, जापानी मिलों में से एक मिल द्वारा निर्यात किये गये श्रेणियों में से एक श्रेणी पोलिमर लेमिनेटिड उत्पाद इस्पात है – यह उत्पाद बाफिनोल-ए / बी पी ए मुक्त है जो खाद्य पैकेजिंग के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। यह नोट करना संगत है कि खाद्य पैकेजिंग में बी पी ए की मात्रा पर पूरे विश्व में अनेक देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ भारतीय ग्राहक विशिष्ट रूप से जापानी उत्पादों का उपयोग करते हैं जो उनके निर्यात निर्माण के लिए बी पी ए मुक्त है।
 - II. जापानी मिलों में से एक मिल भारत में अपने ग्राहकों को क्रोमियम मुक्त उत्पाद भी उपलब्ध कराती है जिसे समान सुरक्षा चिंताएं होती हैं क्योंकि पूरे विश्व में प्राधिकारी इन उत्पादों में क्रोमियम की मात्रा को विनियमित करना/ प्रतिबंध लगाना शुरू कर रहे हैं।
 - III. आवेदक बी पी ए मुक्त अथवा क्रोमियम मुक्त उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकते हैं अथवा अन्य जापानी उत्पादों के तकनीकी रूप से/ व्यापारिक रूप से व्यवहार्य प्रतिस्थानापन उपलब्ध नहीं करा

सकते हैं। वास्तव में, किसी कारण से भारतीय क्रेता जापानी उत्पादों के लिए उच्चतर कीमत का भुगतान करने के लिए इच्छुक हैं और यह एक ऐसा तथ्य है जो स्पष्ट रूप से आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पहुंच कीमत संबंधी गणना में स्पष्ट है।

IV. कई अन्य ग्राहक अनुकूल उत्पाद हैं जो इसके समान हैं जिसके मामले में जापान की मिलें प्रीमियम वसूलती हैं। जापानी मिलों ने इस प्रकार के उत्पादों विशेष रूप से 21 सितंबर, 2019 को दायर अपनी प्रश्नावली के उत्तर के द्वारा बाहर किये जाने की मांग की है।

य) घरेलू उद्योग स्वीकार्य रूप से जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद के अन्य अनेक श्रेणियों अथवा आकारों का उत्पादन नहीं कर रहा है और इसने न ही बेचा है। यह अनुरोध किया जाता है कि उसे प्राधिकारी की कार्यपद्धति के अनुसार जांच के विषय क्षेत्र से बाहर किये जाने की आवश्यकता है।

I. 0.15 मिमी. से कम और 0.21 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला डबल रिड्यूज टिन प्लेट

II. 0.18 मिमी. से कम और 0.23 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला सॉफ्ट डबल रिड्यूज टिन प्लेट

III. चमकदार सतह वाला टिन प्लेट

IV. 11.2 ग्राम/ वर्ग मी. से अधिक कोटिंग वाला टिन प्लेट

V. 1020 से अधिक चौड़ाई वाला टिन

VI. 700 मिमी. से कम चौड़ाई वाला टिन प्लेट

कक) इन उत्पादों का उत्पादन घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है और इस कारण से प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद की परिधि से उन्हें अवश्य बाहर करना चाहिए।

ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. इस वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पी यू सी टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद है जिस पर या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ, चाहे रोगन लगाया हुआ हो और/ अथवा प्रिंट किया हुआ हो या नहीं। क्रोमियम/ क्रोमियम ऑक्साइड अथवा टिन का परत चढ़ाया हुआ है अथवा मुल्लमा किया हुआ है। टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद में टिन प्लेट तथा टिन मुक्त इस्पात शामिल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ई टी पी) अथवा टिन मुक्त इस्पात (टी एफ एस) अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम का परत चढ़ाया हुआ इस्पात (ई सी सी एस) के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति क्वाइल के रूप में अथवा सीट / स्क्रोल के रूप में किया गया जा सकता है। सीट / स्क्रोल की आपूर्ति बेलेकिंग के साथ अथवा उसके बिना वर्ग, आयात, वृत्त अथवा किसी अन्य आकार सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं, विभिन्न रूपों में की जा सकती है।

9. भारत में आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद या तो प्राथमिक उत्पाद के रूप में अथवा गौण उत्पाद के रूप में आया है। यह समझा गया है कि टिन प्लेट में ग्राहक की आवश्यकता/ मांग के अनुसार अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, यदि ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो जैसे सतह की फिनिशिंग, प्रिंटिंग, मोटाई, कोटिंग आदि न हो तब इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री कम कीमत पर गौण उत्पादों के रूप में की जाती है क्योंकि वे मूल रूप से अभीष्ट ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। अन्य शब्दों में, गौण उत्पाद केवल वे उत्पाद हैं जो निर्माण की प्रक्रिया में ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और इस कारण से उनका वर्गीकरण विभिन्न नामों जैसे अपशिष्ट, सेकण्ड, दोषपूर्ण, मिसप्रिंट गौण आदि में किया गया जाता है। गौण टिन प्लेट में प्राइम ओवर रन होता है।

10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि गौण उत्पादों को निम्नलिखित मोटे कारणों से पी यू सी के विषय क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए :

- क) आयात किये गये गौण और घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राथमिक उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं
- ख) प्राथमिक वस्तुओं को निम्न गुणवत्ता और सस्ती कीमत के कारण गौण वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। गौण उत्पादों का उपयोग निम्न अंतिम मर्दों के लिए किया जाता है।
- ग) प्राथमिक और गौण वस्तुओं का उपयोग अलग अलग उद्योगों में और अलग अलग अंतिम उपयोग के लिए किया जाता है।
- घ) प्राथमिक और गौण उत्पादों के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है।
11. समान वस्तु के संबंध में, इस नियमावली का नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :
- “समान वस्तु” का आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सदृश्य अथवा उसी के जैसा हर प्रकार से हो और इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से एक जैसा नहीं हो, फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तुओं से बिल्कुल मिलती जुलती विशेषताएं हों;*
12. प्राधिकारी के सतत कार्यपद्धति के अनुसार, गौण उत्पादों पर विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में किया जाता है जहां तक वे विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस तथ्य को देखते हुए अलग आधारों पर उन्हें रखने का कोई कारण नहीं है कि आयात किये गये उत्पाद की मूलभूत निर्माण प्रक्रिया, अनुप्रयोगों और उपयोगों (प्राथमिक और गौण दोनों श्रेणियों में) तथा वे उत्पाद जिनका आवेदक द्वारा निर्माण किया गया है, एक जैसे हैं। निर्माण की लागत भी वही रहती है जो प्राथमिक और गौण उत्पादों के लिए है तथा यह निर्मित परिणामी प्रकार के साथ नहीं बदलता है।
13. रिकार्ड पर सूचना के संबंध में विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात किये गये उत्पाद और उस उत्पाद जिसका आवेदक द्वारा निर्माण किया गया है (प्राथमिक और गौण दोनों श्रेणियों के लिए) के निर्माण की मूलभूत निर्माण प्रक्रिया, अनुप्रयोगों, उपयोग और लागत एक जैसे हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई ठोस भौतिक गुण अथवा तकनीकी अंतर नहीं है जो संबद्ध वस्तुओं के गौण अथवा द्वितीय गुणों से प्राथमिक सामग्री में अंतर कर सकें। ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से बाहर करने के फलस्वरूप निर्यातकों और विदेशी उत्पादकों द्वारा बच निकलने की संभावना बढ़ेगी। इस कारण से प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत प्राथमिक और गौण दोनों को शामिल करते हैं और उनके गुणवत्ता के आधार पर उनके बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।
14. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विशिष्ट तकनीकी मानदंडों के साथ कुछ विशिष्ट ग्रेडों/ श्रेणियों को विचाराधीन उत्पाद के विचार क्षेत्र से बाहर करने की मांग की है :
- 0.15 मिमी. से कम और 0.21 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला डबल रिड्यूज टिन प्लेट
 - 0.18 मिमी. से कम और 0.23 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला सॉफ्ट डबल रिड्यूज टिन प्लेट
 - चमकदार सतह वाला टिन प्लेट
 - 11.2 ग्राम/ वर्ग मी. से अधिक कोटिंग वाला टिन प्लेट
 - 1020 से अधिक चौड़ाई वाला टिन प्लेट
 - 700 मिमी. से कम चौड़ाई वाला टिन प्लेट
 - टिन मुक्त इस्पात/ इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट
 - पोलिमेर से लेमिनेट किया गया टिन प्लेट जो बाफिनोल-ए/ बी पी ए मुक्त हैं
 - क्रोमियम मुक्त टिन प्लेट
15. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये

तकनीकी ब्यौरों की जांच की गई है। घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि वह 0.15 मिमी. से कम और 0.21 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला डबल रिड्यूज टिन प्लेट। 0.18 मिमी. से कम और 0.23 मिमी. से अधिक की मोटाई वाला सॉफ्ट डबल रिड्यूज टिन प्लेट। चमकदार सतह वाला टिन प्लेट। 11.2 ग्राम/ वर्ग मी. से अधिक कोटिंग वाला टिन प्लेट। 1020 मिमी. से अधिक चौड़ाई वाला टिन प्लेट। 700 मिमी. से कम चौड़ाई वाला टिन प्लेट। टिन मुक्त इस्पात का उत्पादन करता है। इस कारण से इन उत्पादों के लिए किसी उत्पाद को बाहर करना अपेक्षित नहीं है। पोलिमर लेमिनेटिड टिन प्लेट जो बाफिनोल-ए/ बी पी ए मुक्त और क्रोमियम मुक्त टिन प्लेट हैं, के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित अनुसार नोट करते हैं।

- क) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत में इन दो प्रकार के उत्पादों का कोई आयात नहीं किया है और भारत में इन दो प्रकार के उत्पादों की कोई मांग नहीं है। जांच की प्रक्रिया के दौरान की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों से सहमत हैं।
- ख) इन दो प्रकार के उत्पादों को बाहर किये जाने के लिए अनुरोध जापान के निर्यातकों द्वारा और न कि किसी भारतीय प्रयोक्ता द्वारा किया गया। किसी भारतीय द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन दो प्रकार के उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग को आर्डर दिये गये हैं और घरेलू उद्योग ने इन दो प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने और उसकी आपूर्ति करने के लिए अपनी असमर्थता दर्शायी है।
16. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पोलिमर लेमिनेटिड टिन प्लेट जो बाईफिनोल-ए/ बी पी ए मुक्त और क्रोमियम मुक्त टिन प्लेट है, को विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाये। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विषय क्षेत्र से अनपेक्षित रूप से बाहर किये जाने के फलस्वरूप शुल्कों से बचा जा सकता है।
17. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और रिकार्ड पर सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख नीचे दिये गये अनुसार किया जाये :
- ‘टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद है जिस पर या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ, चाहे रोगन लगाया हुआ हो और/ अथवा प्रिंट किया हुआ हो या नहीं। क्रोमियम/ क्रोमियम ऑक्साइड अथवा टिन का परत चढ़ाया हुआ है अथवा मुल्लमा किया हुआ है। टिन मिल फ्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद में टिन प्लेट तथा टिन मुक्त इस्पात शामिल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ई टी पी) अथवा टिन मुक्त इस्पात (टी एफ एस) अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम का परत चढ़ाया हुआ इस्पात (ई सी सी एस) के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति क्वाइल के रूप में अथवा सीट / स्क्रोल के रूप में किया गया जा सकता है। सीट / स्क्रोल की आपूर्ति बेलेकिंग के साथ अथवा उसके बिना वर्ग, आयात, वृत अथवा किसी अन्य आकार सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं, विभिन्न रूपों में की जा सकती है।’*
18. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090 और 72259900 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि विचाराधीन उत्पाद के आयात को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की कुछ अन्य एच एस कोड अर्थात् 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 में भी देखा गया है। हालांकि, यह वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और बाध्यकारी नहीं है।
19. समान वस्तु के संबंध में, इस नियमावली का नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है “समान वस्तु” का आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सदृश्य अथवा उसी के जैसा हर प्रकार से हो और इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से एक जैसा नहीं हो, फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तुओं से बिलकुल मिलती जुलती विशेषताएं हों।

रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में संबद्ध देशों से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय हैं और यह कि ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का विषय क्षेत्र एवं स्थिति

घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

20. घरेलू उद्योग का विषय क्षेत्र और स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

क) भारत में विचाराधीन के उत्पाद के केवल चार ज्ञात उत्पादक हैं। जांच की अवधि के दौरान इन चार ज्ञात उत्पादकों की स्थिति नीचे दी गई है :

| | |
|---|------------------------------------|
| जे एस डब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट प्रा. लिमि. | आवेदक (सक्रिय) |
| द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. (टी सी आई एल) | आवेदक (सक्रिय) |
| स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. (सेल) | जांच की अवधि में उत्पादन नहीं किया |
| जी पी टी लिमि. | जांच की अवधि में उत्पादन नहीं किया |

ख) टिन प्लेट कं. ऑफ इण्डिया लिमि. (टी सी आई एल) टाटा स्टील लिमि. की एक संबंधित कंपनी है। जून 2017 तक, टाटा स्टील लिमि. ने टी सी आई एल को हॉट रोल्ड क्वायल और टिन की आपूर्ति की जिसे टी सी आई एल द्वारा टाटा स्टील लिमि. के लिए जॉब वर्क आधार पर टिन प्लेट में प्रॉसेस किया गया था। इसके लिए टाटा स्टील लिमि. ने टी सी आई एल को प्रॉसेसिंग/ जॉब वर्क शुल्क का भुगतान किया। टिन प्लेट का उत्पादन तथा बिक्री को टाटा स्टील लिमि. के बुक्स में शामिल किया गया था।

ग) 1 जुलाई, 2017 से, टी सी आई एल ने हॉट रोल्ड क्वायल की खरीद टाटा स्टील लिमि. से करना शुरू किया है और अपने खाते से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करना शुरू किया है। तदनुसार, टाटा स्टील लिमि. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नहीं लगा हुआ है।

घ) इस आवेदन में, टी सी आई एल की सूचना 1 जुलाई, 2017 से आगे की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। 9 महीने (1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018) की अवधि के लिए आंकड़े/ सूचना अन्य वर्षों के साथ उपर्युक्त तुलना किये जाने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए जहां भी आवश्यक हुआ वार्षिकीकृत किया गया है।

ङ) जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक थे जो वास्तव में पी यू सी का उत्पादन कर रहे थे और दोनों प्राधिकारी के समक्ष हैं। पी यू सी के कुल पात्र भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत है। तदनुसार, आवेदक स्पष्ट रूप से स्थिति की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इस नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के संबंध में संबंधित उत्पाद के लिए भारत में “घरेलू उद्योग” हैं और वे पूर्ण रूप से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए इस याचिका को लाने के लिए सक्षम हैं।

च) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिलकुल सही तरीके से यह पाया है कि आवेदकों का इस नियमावली के नियम

5(3)(क) के साथ पठित नियम 2(ख) के अंतर्गत आधार है। हालांकि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि आवेदकों ने मैसर्स टाटा स्टील लिमि. से संबंधित सूचना की आपूर्ति नहीं की है। अतः यह जांच विद्वेषपूर्ण है। घरेलू उद्योग इन तर्कों से पूर्ण रूप से इंकार करता है और उनके संबंध में आपूर्ति करता है।

- छ) इस नियमावली के अंतर्गत किसी पक्षकार जो जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है बल्कि विगत में विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक था, से सूचना उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग को कुल घरेलू उत्पादन मानदंड के 'मुख्य अनुपात' को ही पूरा करना चाहिए। सार्थक विश्लेषण के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस नियमावली के नियम 2(ख) का संदर्भ लिया जाये जिसे संगत भाग में उद्धृत किया गया है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

21. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के विषय क्षेत्र और आधार के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है :

- क) यह स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमि. टी सी आई एल के साथ साथ क्षति की अधिकांश अवधि (अर्थात् जून 2017 तक) में पी यू सी के उत्पादन में शामिल रहा है।
- ख) जून 2017 से पहले, विचाराधीन उत्पाद के लिये उत्पादन क्रियाकलाप टाटा और टी सी आई एल के बीच बंटा हुआ था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन को टाटा के बुक्स में रिकार्ड किया गया है, फिर भी दोनों विचाराधीन उत्पाद के “उत्पादक” संयुक्त रूप से थे। इसकी पुष्टि आगे टी सी आई एल की वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में की गई है जिसमें टी सी आई एल का उल्लेख इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट के निर्माता के रूप में किया गया है।
- ग) टाटा स्टील लिमि. की लागत एवं वित्तीय संबंधी आंकड़े टाटा और टी सी आई एल के संबंधित प्रतिष्ठानों के होने के बावजूद जुलाई 2017 से पहले की अवधि के लिए इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- घ) आवेदकों ने सार्थक टिप्पणियां करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से टाटा और टी सी आई एल के बीच के जॉब वर्क संबंध की पुष्टि करने के लिए अगोपनीय रूप में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ङ) चूंकि टी सी आई एल और टाटा स्टील लिमि. द्वारा क्षति की समग्र अवधि के लिए आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराने से जांच की शुरुआत और क्षति के निर्धारण पर प्रभाव पड़ेगा तथा टी सी आई एल और टाटा स्टील लिमि. को असहयोगी बना देगा, अतः वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- च) टी सी आई एल और टाटा को असहयोगी बनाने के अनुसरण में, जे एस डब्ल्यू वल्लभ के पास वर्तमान जांच के उद्देश्यों से अपेक्षित आधार नहीं रहेगा। इस कारण से, सभी उद्देश्यों से, वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- छ) विचाराधीन उत्पाद में एच आर की लागत पी यू सी की लागत का कम से कम 60 प्रतिशत है (ग्रेड और फिनिश के आधार पर) वह कीमत जिस पर कच्चे माल को टाटा से टी सी आई एल में अंतरित

किया गया है, का आंकलन अवश्य किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के लिए विचार की गई एच आर लागत संबंधित अवधि के दौरान बाजार कीमत का द्योतक है और यह कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा टी सी आई एल के रिकार्ड में अपेक्षाकृत अधिक क्षति दर्शाने के उद्देश्य से टाटा पर नहीं डाला जाये।

- ज) इन पक्षकारों के बीच अंतरण कीमत निर्धारण करार से संभवतः न्यूनतम कीमत के लिए आरंभिक सीमा तय होगी जिसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतरण कीमत का ध्यानपूर्वक आंकलन करें और इन दो प्रतिस्थानों के बीच एच आर अंतरण लागत बहुत अधिक नहीं होने दें।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए आवेदन मैसर्स जे एस डब्ल्यू वल्लभ टिन प्लेट प्रा. लिमि. और मै. टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन में, यह उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के दो और ज्ञात घरेलू उत्पादक अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. और जी पी टी लिमि. हैं। हालांकि, इन दो कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है। वास्तव में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. ने क्षति के समग्र अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं किया है।
23. जून 2017 तक मैसर्स टाटा स्टील लिमि. ने मै. टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. को एच आर क्वायल की आपूर्ति की जिसे मैसर्स टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. द्वारा जॉब वर्क आधार पर मैसर्स टाटा स्टील लिमि. को प्रांसेस किया गया था। इसके लिए टाटा स्टील लिमि. ने टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. को प्रांसेसिंग/ जॉब वर्क शुल्क का भुगतान किया। टिन प्लेट का उत्पादन तथा बिक्री टाटा स्टील लिमि. के बुक्स में शामिल किया गया था। जुलाई 2017 से, मैसर्स टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. ने टाटा स्टील लिमि. से हॉट रोल्ड क्वायल की खरीद तथा विचाराधीन उत्पाद का अपने लेखा से उत्पादन और बिक्री करना शुरू किया।
24. जांच की अवधि के दौरान केवल दो कंपनियां अर्थात् जे एस डब्ल्यू वल्लभ टिन प्लेट प्रा. लिमि. और मैसर्स टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. थी जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करती थी और इस कारण से दोनों आवेदकों का भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत था। इस नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है :
“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।
25. उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस कारण से इस जांच के उद्देश्य से उनका एक स्पष्ट आधार है। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और आयातकों और निर्यातकों में से किसी से भी संबंधित नहीं होने का दावा किया है।
26. तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों का समान उत्पाद का कुल भारतीय उत्पादन का ‘एक बड़ा हिस्सा है’ और यह कि आवेदक इस नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत ‘आधार’ की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इस नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में ‘घरेलू उद्योग’ हैं।
27. इस अनुरोध के संबंध में कि एक सुव्यवस्थित क्षति आंकलन टाटा स्टील लिमि. की सूचना के बिना नहीं किया जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे की जांच इस अंतिम जांच परिणाम के ‘क्षति और कारणात्मक संबंध’ भाग के अंतर्गत विस्तारपूर्वक की गई है। उसी प्रकार से, क्या हॉट रोल्ड क्वायल मैसर्स जे एस डब्ल्यू वल्लभ टिन प्लेट प्रा. लिमि. और मैसर्स टिन प्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. को उनके संबंधित पक्षकारों द्वारा अलग कीमत पर अंतरित किया गया है अथवा नहीं, के मुद्दे का भी समाधान इस अंतिम जांच

परिणाम के 'क्षति और कारणात्मक संबंध' भाग के अंतर्गत किया गया है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क) विस्तृत अनुरोध प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिउत्तरों में खामियों को उजागर किया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इन प्रतिउत्तरों का अगोपनीय पाठ गोपनीयता के नाम पर न्यूनतम सूचना भी प्रकट नहीं करता है।
- ख) यह अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के द्वारा गोपनीयता की अपेक्षाओं के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन किया है।
- ग) प्राधिकारी आवेदकों ने इस नियमावली के नियम 7 और दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ में सभी आवश्यक सूचना प्रकट की है।

ड. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क) इन हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध व्यापार नोटिस सं. 10/2018 से मेल नहीं खाता है।
- ख) आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि अनेक जापानी मिलों ने भारत को बिक्री का रास्ता उपलब्ध नहीं कराया है और इसे अत्यधिक गोपनीयता की एक घटना के रूप में उल्लेख किया है। हालांकि, व्यापार सूचना 10/2018 में इन पक्षकारों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे सर्वप्रथम अगोपनीय रूप में व्यापार के माध्यम उपलब्ध कराये क्योंकि यह संवेदनशील व्यापारिक सूचना है।
- ग) उक्त नोटिस के अनुबंध 1 में विशेष रूप से उदाहरण देते हुए यह समझाया गया है कि किस प्रकार से इस सूचना को घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन/ प्रतिउत्तर के अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- घ) आवेदकों ने इस व्यापार सूचना का पालन नहीं किया है और इसमें अपने हित की रक्षा करने के लिए प्रतिवादी की क्षमता को नुकसान पहुंचाया है।
- ङ) टाटा स्टील और जे एस डब्ल्यू दोनों से हॉट रोल्ड क्वायल की अंतरण कीमत से संबंधित सूचना अपनी एसोसियेट कंपनियों से गोपनीय के रूप में छुपाई गई है। टाटा स्टील के संलग्न लेखापरीक्षित तुलन पत्र से यह देखा गया है कि उनका 29 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन है जो असामान्य रूप से बहुत अधिक मार्जिन है।
- च) आवेदकों ने कुछ आर्थिक मानदंडों को गोपनीय रखा है और इस प्रकार की सूचना के बिना घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी मानदंडों की सार्थक जांच किया जाना संभव नहीं है।
- छ) आवेदकों द्वारा गोपनीयता के दावे निम्नलिखित कारकों के संबंध में अत्यधिक हैं :
 - I. दोनों आवेदकों का अलग अलग उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना
 - II. प्रपत्र- ठ में सूचना
 - III. प्रपत्र- ज में बिक्री में संबंधित प्राप्ति
- ज) उच्चतम न्यायालय का *सुटरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में निर्णय वर्तमान मामले के लिए संगत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुटरलाइट इंडस्ट्रीज मामले में यह माना है कि नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता को "स्वतः माना" नहीं जा सकता है। नियम 7 के अंतर्गत, निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामग्री की गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट किया जाना है। यदि यह

सामग्री गोपनीय भी हो तब निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए कहना है। नियम 7(3) के अंतर्गत, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि गोपनीयता आवश्यक नहीं है और यह कुछ मामलों में उस सूचना की उपेक्षा भी कर सकते हैं।

- झ) उससे संबंधित कारणों की विवरणी प्रस्तुत की जानी है। केवल विवरणी जो “कानूनी दस्तावेजों का सारांश संभव नहीं है” का उल्लेख करता हो, कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है।
- ञ) व्यापार सूचना और इस नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि आवेदक के अगोपनीय पाठ में सूचीबद्ध और सारांश रूप में गोपनीय आंकड़े होना अपेक्षित है।
- ट) अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए। व्यापार सूचना के पैरा (vi) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि गोपनीय पाठ का अगोपनीय सार्थक पाठ के बिना किये गये किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जायेगा।

ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

- 31. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- 32. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उसका समाधान किया गया था। प्राधिकारी ने स्ट्रलाइट इंडस्ट्रीज के मामले में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए और इस बात पर बल देते हुए कि इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीयता को स्वतः नहीं माना जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को भी विधिवत नोट किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गोपनीय आधार इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय

पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क) प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से आवेदकों के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी और यह जनहित में नहीं होगा। आवेदक भारत में किसी प्रकार का एकाधिकार बनाया जाना नहीं चाहते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उद्योग को बने रहने की अनुमति मिलेगी जो अंततः भारतीय प्रयोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि उन्हें आयात पर छोड़ा नहीं जायेगा। भारत में एक स्वस्थ और विकासशील घरेलू उद्योग हर किसी के हित में होगा। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।
- ख) 31 मई, 2019 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रशुल्क आयोग ने अपने घरेलू उद्योग पाटित आयातों से संरक्षित करने के लिए चीन, यूरोपिय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका और यू एस ए से टिन प्लेट के आयातों पर एक निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया है।
- ग) इंडोनेशिया के प्राधिकारियों ने भी चीन, चीनी ताइपेई और कोरिया गणराज्य से टिन प्लेट क्वायल/शीट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया है।
- घ) यू एस वाणिज्यिक विभाग ने वर्ष 2000 में जापान से कुछ टिन मिल उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया तथा वह 2017 में हाल में यू एस वाणिज्य विभाग द्वारा की गई तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच के बाद भी जारी है।
- ङ) यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश निर्यात उन्मुख हैं और वे भारत सहित अनेक देशों में अपने उत्पादों का पाटन करते हैं।

च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क) पूरे भारत में 7000 से अधिक इकाईयां हैं जो गौण टिन प्लेट का उपयोग करते हैं। ये इकाईयां लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। ऐसे भी ग्राहक हैं जो दैनिक आधार पर/साप्ताहिक आधार पर इन उत्पादों की खरीद करते हैं और कुछ ऐसे ही ग्राहक हैं जिनका व्यापार गौण टिन प्लेट उत्पादों की सुगम्यता के कारण चल रहा है।
- ख) एफ एस एस ए आई के दिशानिर्देश 15 लीटर के खाद्य तेल के केन का फिर से उपयोग किये जाने से रोकता है। प्रभावी प्रवर्तन से लगभग 200,000 मी. टन के टिन प्लेट की आवश्यकता में वृद्धि होगी।
- ग) प्लास्टिक के स्थान पर टिन प्लेट का उपयोग किया जा रहा है। ल्यूब ऑयल और इनेमल पेंट निर्माता इस एसोसिएशन के साथ प्लास्टिक के स्थान पर टिन प्लेट का उपयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। यह आवश्यकता लगभग 100,000 मी. टन की होगी। मौजूदा क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत खपत में स्वाभाविक वृद्धि होगी जो लगभग 75,000 मी. टन प्रतिवर्ष है। फूड केन, ग्लास बोतल के लिए क्राउन्स, क्लोजर्स और ऐरोसाल केन में बढ़ते हुए उपयोग के लिए बाजार है जिसका लाभ नहीं उठाया गया है। तदनुसार, पी यू सी के लिए मांग आने वाले वर्षों में बहुत अधिक बढ़ने जा रही है। घरेलू उद्योग के पास मांग में इस वृद्धि को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
- घ) टिन प्लेट पेंट, कीटनाशक पदार्थों और कई अन्य उत्पादों के लिए एक प्रमुख पैकेजिंग सामग्री है, जिसका भंडारण नहीं किया जा सकता है और उसे तत्काल पैक किया जाना चाहिए और बाजार भेजा जाना चाहिए। किसी पाटनरोधी शुल्क के कारण आपूर्ति की यह श्रृंखला टूट जायेगी।

- ड) पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से अनुचित अनुपात में लघु और सूक्ष्म क्षेत्र में नियोजित अधिकांश व्यक्तियों को नुकसान पहुंचेगा जिनके पास रोजगार के वैकल्पिक अवसर नहीं होंगे।
- च) टिन प्लेट प्रयोक्ता उद्योग को टिन प्लेट की अधिक कीमतों के कारण हानि हुई है और वह प्रतिस्थानापन सामग्रियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसके फलस्वरूप पोयशा, मेट बॉक्स जैसे अग्रणी कंपनियों को अपना प्रचालन बंद करना पड़ा है।
- छ) टिन प्लेट प्रयोक्ता उद्योग को क्षमता का उपयोग, लाभप्रदता के मामले में हानि हो रही है और वे बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीमा शुल्कों को कम किया जाना चाहिए ताकि टिन प्लेट अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध हो और यह प्रभावी तथा पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री हो।
- ज) शुल्क लगाये जाने से आवेदकों का एकाधिकार स्थापित होगा और यह जनहित में नहीं होगा।
- झ) यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब, यह इनपुट और उत्पादों की अंतिम लागत में वृद्धि करेगा जिससे वे चीन, बंगलादेश, एशियाई देशों जैसे अन्य देशों की तुलना में गैर अर्थक्षम और अप्रतिस्पर्धी हो जायेंगे। इसके फलस्वरूप भारत में गौण सामग्री का उपयोग करने वाले उत्पादों का निर्माण करने वाली हजारों लघु इकाइयां बंद हो जायेंगी।
- ञ) इसके अलावा, इससे चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि से अंतिम उत्पादों के सीधे आयात में वृद्धि होगी।
- ट) यूरोप और यू एस ए को संबद्ध देशों के विषय क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए। यूरोप का 12.5 प्रतिशत आयात शुल्क और उपकर, बैंक शुल्क, क्लेयरिंग शुल्क, बैंक वित्त, अंतर्देशीय लागत है। इसी प्रकार से, यू एस ए का 27.5 प्रतिशत से अधिक उपकर, बैंक शुल्क, क्लेयरिंग शुल्क, बैंक फाइनेंस, अंतर्देशीय लागत का दण्डात्मक आयात शुल्क है। इसके साथ ही आयातों के आंकड़ों में जांच के वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस कारण से यू एस ए और यूरोप का बाहर किया जाना चाहिए।
- ठ) भारतीय मिलों को पहले से ही 12.5 प्रतिशत और उपकर तथा क्लेयरिंग शुल्क, स्थानीय पोर्ट शुल्क तथा घरेलू अंतर्देशीय परिवहन के साथ आयात शुल्क के द्वारा संरक्षण दिया गया है। 25 प्रतिशत की न्यूनतम अतिरिक्त लागत है। अनेक देशों का स्थानीय उत्पादन के साथ शून्य प्रतिशत आयात शुल्क है क्योंकि टिन प्लेट को पैकेजिंग सामग्री माना जाता है और इसे नियमित स्टील नहीं माना जाता है। टिन प्लेट पूरे विश्व में सीमित उत्पादन के साथ गौण उत्पाद है।
- ड) वह शुल्क जिसे यू एस ए ने जापानी टिन मिल उत्पादों पर लगाया है करीब वर्ष 2000 से अस्तित्व में रहा है। हालांकि पाटनरोधी शुल्कों के मौजूद रहने के बावजूद यू एस ए को टिन मिल के उत्पादों के जापानी निर्यात की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तदनुसार, तर्कसंगत तरीके से यह भी अनुमान निकाला जा सकता है कि जापान पर यू एस ए ने शुल्कों के मौजूद रहने के कारण भारत में जापानी निर्यात का कोई व्यापार विपथन नहीं हो सकता है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 35. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में की पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन का अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है।
- 36. भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर इन पाटनरोधी शुल्कों से प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे

अधिक स्रोतों को बनाये रख सकते हैं। एकाधिकार नहीं बन सकता है क्योंकि इस देश में विचाराधीन उत्पाद के दो उत्पादक पहले से हैं।

37. यू एस ए और यूरोपीय यूनियन को इस जांच से बाहर करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि क्या पाटित कीमतों पर भारत में आयात हो रहे हैं और क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योगों को क्षति हो रही है। केवल इस कारण से कि यू एस ए और यूरोपीय यूनियन के आयात अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुल्क के अधीन हैं, यह जांच के विषय क्षेत्र से यू एस ए और यूरोपीय यूनियन को बाहर करने के लिए आधार नहीं हो सकता है।
38. प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों के कारण कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रूक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ता को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।
39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से अंतिम प्रयोक्ता को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम प्रयोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाये रख सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं होगा। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन का अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटनमार्जिन का निर्धारण

40. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :
 - i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

41. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क) चूंकि कोरिया गणराज्य, यू एस ए और यूरोपीय यूनियन से कोई उत्पादक/ निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः यह स्पष्ट है कि कोरिया गणराज्य, यू एस ए और यूरोपीय यूनियन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/ निर्यातक ने यह स्वीकार किया है कि वे भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं।
- ख) यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कोरिया गणराज्य, यू एस ए और यूरोपीय यूनियन के लिए पाटन मार्जिन की गणना करनी चाहिए।
- ग) पर्याप्त पाटन मार्जिन प्रत्येक संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पादक के आयातों के संबंध में मौजूद है।
- घ) जापान से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर की जानी चाहिए बशर्ते उनका प्रतिउत्तर पूर्ण हो और प्राधिकारी की आवश्यकता को पूरा करता हो।
- ङ) प्राथमिक और गौण उत्पादों का उत्पादन करने के लिए लागत वही है और यह सामान्य मूल्य और/ अथवा पाटन मार्जिन की गणना को प्रभावित नहीं करता है।

छ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क) किसी उत्पादक/ निर्यातक का भाग लेना पूर्णरूप से वाणिज्यिक निर्णय है और उसका उपयोग उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यह अनुरोध कि भाग न लेना पाटन के बराबर है त्रुटिपूर्ण है।
- ख) जापान की मिलें यह अनुरोध करती हैं कि जापान के कुछ प्रमुख उत्पादकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना करने के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। तदनुसार, आवेदकों के इस कथन का पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ग) पाटन तब होता है जब भारत में आयात किये गये वस्तुओं की निर्यात कीमत निर्यातक के घरेलू बाजार में बेची गई वस्तुओं के सामान्य मूल्य से कम होता है। आवेदकों ने विदेश में घरेलू बाजार में बेची गई सामग्री घरेलू कीमत का उल्लेख नहीं किया है। यह आशाजनक है क्योंकि टाटा स्टील यूरोप में अपनी संबद्ध कंपनी है।
- घ) सस्ती अथवा कम कीमत पर आयात अपने आप में पाटन को नहीं दर्शाता है। आयात की गई सामग्री 'अपशिष्ट' उत्पाद हैं क्योंकि वे ग्राहक की इच्छित विनिर्देश अनुरूप नहीं हैं। आयात की गई गौण सामग्री को सभी प्रकार विनिर्देश में उपलब्ध सामग्री से समझौता करना पड़ता है जो लघु और सूक्ष्म उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- ङ) उत्पादक/ निर्यातक इन उत्पादों का निर्यात कम कीमतों पर नहीं कर रहे हैं। वे नीलामियों के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री करते हैं। सामान्य बोली प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इन उत्पादों को "सामान्य मूल्यों" पर बेचा जाता है। ये उत्पाद घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध हैं।
- च) हितबद्ध पक्षकार "सामान्य मूल्य" की गणना से सहमत नहीं हैं। इन वस्तुओं को खुली नीलामियों और निविदाओं में बेचा जाता है और वे निर्यात करने वाले देश के घरेलू ग्राहकों को उसकी कीमत पर उपलब्ध हैं। इस पद्धति जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा किया जाता है, के फलस्वरूप प्राथमिक टिन प्लेट की कीमत में वृद्धि होगी। हालांकि, भारत द्वारा उपयोग की गई सामग्री का 95 प्रतिशत गौण उत्पाद है जिसकी तुलना प्राथमिक टिन प्लेट के साथ नहीं की जा सकती है।

- छ) यह अनुरोध किया जाता है कि टी सी आई एल के लिए यूरोप में प्रचलित कीमतों तक पहुंच होना तब संभव नहीं है जब टाटा ग्रुप यूरोप में भी टिन प्लेट का उत्पादन कर रहा हो। आवेदकों ने संबद्ध देशों में प्राथमिक एच आर सी की कीमत निर्धारित कर तथा यूटिलिटी और परिवर्तन लागत एवं मार्जिन के अच्छे लाभ को अपनी आरंभिक याचिका के अनुसार जोड़कर इन वस्तुओं के सामान्य मूल्य की गणना की है। इस तथ्य की कोई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है कि किस प्रकार से इन आवेदकों ने सामान्य मूल्य की गणना की है।
- ज) गौण उत्पादों को नीलामी और निविदा के आधार पर बेचा जाता है और उनमें भाग लेने वाली कंपनियां घरेलू सेवा केंद्र और स्थानीय केन कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शामिल होते हैं। नीलामी अथवा निविदा की विजेता कंपनियां अपने घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। नीलामी और निविदाएं बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं और उत्पादों की बिक्री सबसे अधिक कीमत पर की जाती है। गौण सामग्री जिसे अन्य देशों को बेचा जाता है की कीमतें वही होती हैं जो भारत में कीमत होती है।
- झ) यूरोपीय यूनियन, यू एस ए, कोरिया और जापान की प्राथमिक कीमतें आवेदकों की घरेलू प्राथमिक कीमतों से अधिक होती हैं।

छ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को उन्हें निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी। हालांकि, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़कर, संबद्ध देशों के किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग नहीं किया :

- I. जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन, जापान
- II. जे एफ ई शोजी ट्रेड कोरपोरेशन, जापान
- III. मेटल वन कोरपोरेशन, जापान
- IV. मारुबेनी इटोचू स्टील (एम आई स्टील), जापान
- V. निप्पोन स्टील कोरपोरेशन, जापान
- VI. निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कोरपोरेशन, जापान
- VII. आहमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान
- VIII. टेत्सूशो क्वाबा कोरपोरेशन, जापान
- IX. टोक्यो ट्सूशो कोरपोरेशन, जापान
- X. अमेरिकन इंटरनेशनल कोरपोरेशन, यू एस ए
- XI. फेरम एन वी, बेल्जियम (ई यू)

छ. 3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण और यूरोपीय यूनियन में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि यूरोपीय यूनियन में किसी उत्पादक और निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पाटन मार्जिन को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

छ. 3.2. सामान्य मूल्य का निर्धारण और कोरिया गणराज्य में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात

कीमत

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि कोरिया गणराज्य में किसी उत्पादक और निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पाटन मार्जिन को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

छ. 3.3. सामान्य मूल्य का निर्धारण और यू एस ए में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यू एस ए के विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि यू एस ए में किसी उत्पादक और निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पाटन मार्जिन को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और यू एस ए में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पद्धति

47. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के विश्वसनीय कीमत और लागत ब्यौरे के न रहने की स्थिति में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रत्येक संबद्ध देश में प्रचलित एच आर कीमतों पर विचार करते हुए तथा घरेलू उद्योग की खपत मानदंड, अन्य कच्चा माल लागत, परिवर्तन लागत, प्राथमिक पैकिंग लागत, बिक्री, सबसे अधिक कार्यक्षम घटक की सामान्य एवं प्रशासनिक लागत को अपनाकर यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और यू एस ए के लिए सामान्य मूल्य तय किया है। सामान्य मूल्य तय करने के लिए उचित लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है। तदनुसार, संबद्ध वस्तुओं के लिए यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और यू एस ए से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दिये गये पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और यू एस ए ने उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु पद्धति

48. यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और यू एस ए के किसी उत्पादक द्वारा सहयोग न किये जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ने समुद्री भाड़े, बीमा, अतर्देशीय भाड़े, बैंक शुल्क और कमीशन के लिए उपयुक्त समायोजन करने के बाद आधिकारिक लेनदेन वार डी जी सी आई एंड एस संबंधी आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ. 3.4. जापान में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन, जापान**

49. जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन ने दिनांक 21 सितंबर, 2019 को अपने निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और उसका अध्ययन करने के बाद यह पाया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिउत्तर निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र के अनुरूप नहीं था। प्राधिकारी ने जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिउत्तर में खामियों का उल्लेख करते हुए एक खामी संबंधी पत्र भी जारी किया। हालांकि, जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन ने प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये खामी संबंधी पत्र का उत्तर नहीं दिया और पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई। वास्तव में उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की अपनी लागत से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
50. उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना न दिये जाने की स्थिति में प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं होगा कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या घरेलू बिक्री कीमत जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हैं अथवा नहीं।

51. इस कारण से, जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन से पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यात की प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार किया जाना प्रस्तावित है और कोई अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन के लिए कोई अलग अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को निर्धारित नहीं किये जाने का प्रस्ताव है।

निपपोन स्टील कोरपोरेशन ("एन एस सी")

सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान एन एस सी ने घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित पक्षकारों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री भारत को किये गये निर्यात से तुलना किये जाने पर पर्याप्त मात्रा में है।
53. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री संबंधी लेनदेन करते हुए लाभ निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया को पूरा किया। चूंकि लाभ अर्जित करने संबंधी लेनदेन 80 प्रतिशत से अधिक था, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है।
54. एन एस सी ने अंतर्देशीय भाड़े, बीमा, ऋण लागत, भंडारण और अन्य खर्च के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। एन एस सी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण तदनुसार किया गया है और उसे नीचे दिये गये पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

55. एन एस सी ने अपनी संबंधित और असंबंधित व्यापार कंपनियों अर्थात् निपपोन स्टील ट्रेनिंग कोरपोरेशन ("एन एस टी सी"), एम आई स्टील मेटल वन कोरपोरेशन ("मेटल वन"), टोयटा शूशो कोरपोरेशन ("टी टी सी") और टेशूशो कायबा कोरपोरेशन ("टी के सी") के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक संबंधित व्यापारी, एन एस टी सी ने भारतीय ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से और अन्य असंबंधित व्यापारियों अर्थात् टी के सी और कोआ कंपनी लिमि. ("कोआ"), के माध्यम से भी निर्यात किया है। एन एस सी ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान इसमें उपर्युक्त संबंधित/ असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत को *** मी. ट. निर्यात किया है। व्यापारियों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. ट. (समय के अंतर के कारण यह अंतर है) निर्यात किया है। व्यापारियों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए एन एस सी द्वारा भारत को निर्यात के रूप में अपनाया गया है।
56. भारत को निर्यात के विभिन्न माध्यमों और इन माध्यमों के द्वारा निर्यात की गई मात्रा नीचे तालिका में दर्शायी गई है :

| निर्यात माध्यम | भारत को निर्यात (मी. ट.) | मात्रा % | सहयोग कर रहा है (हां/ नहीं) |
|--|---------------------------|----------|-----------------------------|
| एन एस सी – एस एन टी सी-इंडिया | *** | *** | हां |
| एन एस सी – एस एन टी सी - टी के सी इंडिया | *** | *** | हां |
| एन एस सी – मेटल वन-इंडिया | *** | *** | हां |
| एस एस सी – एम आई स्टील – इंडिया | *** | *** | हां |
| एन एस सी – टी टी सी – इंडिया | *** | *** | हां |

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| एन एस सी – एन एस टी सी – कोवा – इंडिया | *** | *** | नहीं |
| कुल | *** | *** | |

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक व्यापारी अर्थात् कोआ ने भारत को निर्यात की गई उक्त *** मी. ट. मात्रा के लिए अपेक्षित सूचना वाली निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
58. प्राधिकारी ने इस उत्पादक के लिए निर्यात कीमत की गणना करते समय एन एस सी द्वारा भारत को भेजी गई मात्रा (*** मी. ट.) की *** के लिए उत्पादक एन एस सी जिसके लिए प्रतिउत्तर का संपूर्ण चेन प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है, के सत्यापित वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया है। एन एस सी ने शीपिंग, भंडार, ऋण लागत और बीमा के कारण समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ व्यापारियों ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात उस कीमत पर किया है जिसमें व्यापारी का खर्च शामिल नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी ने व्यापारियों के खर्च के आधार पर भी उपयुक्त समायोजन किया है।
59. निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में, प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (6क) की व्याख्या (ख) में निहित प्रावधानों को नोट करते हैं जिसे नीचे दिये गये अनुसार पढ़ा जाये।

“(1) व्याख्या (ख) “किसी वस्तु के संबंध में “निर्यात कीमत” का अभिप्राय निर्यात देश अथवा प्रक्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत से है और उन मामलों में जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहां निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक अथवा तृतीय पक्षकार के बीच एसोसिएशन अथवा प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है, निर्यात कीमत को उस कीमत के आधार पर तय किया जा सकता है जिस पर आयात की गई वस्तु को सर्वप्रथम एक स्वतंत्र क्रेता को फिर से बेचा गया हो अथवा यदि उस वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को फिर से नहीं बेचा गया हो अथवा ऐसे उचित आधार पर देश का निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमावली के अनुसार किया जा सकता है, पर आयात किये गये अनुसार इस शर्त पर नहीं बेचा गया हो।

(6क) उपधारा (6) के अंतर्गत जांच के अधीन किसी निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा निर्यात की गई किसी वस्तु के संबंध में पाटन के मार्जिन का निर्धारण कायम रखा गया सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत तथा ऐसे उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में रिकार्डों के आधार पर किया जायेगा :

बशर्ते की जहां कोई निर्यातक अथवा उत्पादक इस प्रकार का रिकार्ड अथवा सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता है, वहां ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए पाटन के मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जायेगा।”

60. इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 6(8) में इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है :

“(8) उस मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना दिये जाने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिशें कर सकते हैं जिसे यह ऐसी परिस्थितियों में उचित समझता हो।”

61. उपर्युक्त प्रावधानों को देखते हुए, निर्यात की मात्रा (*** मी. ट.) की *** के लिए निर्यात कीमत जिसके लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना वाला प्रतिउत्तर संपूर्ण चेन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में इस मात्रा की निर्यात कीमत की गणना इस नियमावली के नियम 6(8) तथा इस अधिनियम की धारा 9क

(6क) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक एन एस सी द्वारा भारत को निर्यात की गई मात्रा (***) के संबंध में निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के निर्धारण के लिए उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों का उपयोग किया है।

62. तदनुसार एनएससी, जापानी उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातों की भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूर्ण सूचना दी गई है और भारत को निर्यात जिसके लिए सूचना की पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार से, एन एस सी उत्पादक के लिए निर्धारित निर्यात कीमत को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ. 3.5 पाटन मार्जिन तालिका

63. अलग अलग संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है :

| मूल देश और/ अथवा निर्यात | उत्पादक | सामान्य मूल्य/ सी एन वी (यू एस डी) | निवल निर्यात कीमत | पाटन मार्जिन (यू एस डी) | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन % रेंज |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| जापान | निप्पोन स्टील कोरपोरेशन, जापान | *** | *** | *** | *** | 30-50 |
| जापान | निप्पोन स्टील कोरपोरेशन को छोड़कर | *** | *** | *** | *** | 80-100 |
| यू एस ए | कोई भी | *** | *** | *** | *** | 140-160 |
| यू ई | कोई भी | *** | *** | *** | *** | 110-130 |
| कोरिया जन. गण. | कोई भी | *** | *** | *** | *** | 40-60 |

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि सभी संबद्ध देशों के लिए अधिक भी है।

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध :

65. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

- (क) अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली के नियम 11 पाटरोधी जांच के दौरान क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित हैं। अनुबंध-II का पैरा (i) और (ii) निम्नानुसार पढ़ा जाए :
- (i) नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मात्रा और कीमत दोनों के परीक्षण द्वारा क्षति की जांच करें। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होती है।

- (ii) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय, उक्त अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। "जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक हास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"
- ख) घरेलू उद्योग ने पाटन, क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी संगत आंकड़ों/सूचना पहले ही उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने दिनांक 28 जून, 2019 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विधिवत यह नोट किया है कि पाटन, क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए है।
- ग) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि इन आवेदकों की घरेलू बिक्री आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध अंक से बढ़कर जांच की अवधि में 512 सूचीबद्ध अंक हो गया है, क्योंकि टीसीआईएल ने जुलाई, 2017 से ही बिक्री आरंभ की है। बिक्री का क्षति विश्लेषण करने के लिए, सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की प्रवृत्ति पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इसे उस संदर्भ में देखा जाए तब जांच की अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि आधार वर्ष से केवल 6 सूचीबद्ध अंक तक हुई है।
- घ) कानून के अंतर्गत मांग में वृद्धि की तुलना में आयातों में वृद्धि की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में आयातों की जांच अपेक्षित है जिसे इस मामले में स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। संबद्ध आयातों में स्वतंत्र रूप में 13 सूचीबद्ध अंक और खपत की तुलना में 6 सूचीबद्ध अंक तक वृद्धि हुई है।
- ड.) यद्यपि घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है फिर भी घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में अपरिवर्तित रहा जबकि आयातों के हिस्से में 2016-17 और 2017-18 में 12 अंक की वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 6 सूचीबद्ध अंक तक वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि से घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिला है क्योंकि अतिरिक्त मांग पर कम कीमत वाले पाटित आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- च) आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि संबद्ध देशों से बहुत अधिक मात्रा में हो रहा पाटित आयात उनके द्वारा उठाई जा रही क्षति का एकमात्र कारण है और भारत में कम कीमत पर हो रहे पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है।
- छ) घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि भारत में सभी संबद्ध देशों से हो रहे आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं। यूएसए, ईयू और कोरिया के उत्पादकों ने उक्त जांच में भाग नहीं लिया है और न ही उन्होंने इन आवेदकों द्वारा किए गए दावे का खंडन किया है। जापान द्वारा अलग-अलग आंकलन के लिए किया गया दावा निम्नलिखित कारणों से अवैध है:
- जापान ने भारत में अपने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटन का खंडन नहीं किया है। आवेदकों ने जापानी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए जा रहे पाटन, जो न्यूनतम सीमा से ऊपर है, के संबंध में विस्तृत अनुरोध किए हैं।
 - आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के साथ समान व्यापारिक स्थितियों में तूलनीय बिक्री चैनल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करता है। विचाराधीन उत्पाद का जापान का आयात घरेलू उद्योग तथा अन्य आयातित वस्तुओं के समान वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वास्तव में जापान के आयातों का बहुत बड़ा हिस्सा गौण वस्तु से बना होता है।

ज. आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए समान वस्तु के साथ समान व्यापारिक परिस्थितियों में तुलनीय बिक्री चैनल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करता है।

ज..2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए अनुसार हैं:
 - क) आवेदकों ने इस बात की पुष्टि की है कि आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन नियमावली के अनुबंध II (iii) के साथ पठित नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार उपयुक्त है।
 - ख) आवेदकों ने पूर्ण रूप से इस तथ्य की उपेक्षा की है कि डीजीटीआर मैनुअल तथा पाटनरोधी करार यह उल्लेख करता है कि आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति के बीच इस बात का निर्धारण करते समय कि क्या संचयन उपयुक्त है, पर विचार किया जाना चाहिए।
 - ग) आवेदक इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए हैं कि यह उपयुक्त है कि संबद्ध देशों के बीच आयात संबंधी व्यवहार और उत्पाद श्रेणीकरण के बीच अंतरों के बावजूद संबद्ध आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन करना उपयुक्त है।
 - घ) वर्तमान मामले का वास्तविक मैट्रिक्स जापान से आयातों के लिए क्षति का एक अपसंचयी आंकलन को न्यायोचित ठहराता है। कीमत में उतार-चढ़ाव जापानी आयातों के संबंध में पूर्ण रूप से अलग-अलग है। अन्य संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में, जापान की कीमत में गिरावट आई जबकि अन्य संबद्ध देशों से कीमत में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2017-18 में, अन्य संबद्ध देशों से कीमत में गिरावट आई जबकि जापान से कीमत में वृद्धि हुई। जांच की अवधि में अन्य संबद्ध देशों से कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि जापान से कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
 - ड.) इस नियमावली के अनुबंध II (iii) के साथ पठित नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने पर आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन कर सकते हैं:
 - i. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन न्यूनतम से अधिक है;
 - ii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है; और
 - iii. आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा समान घरेलू वस्तु और आयातित वस्तुओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।
 - च) यह अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त प्रावधान में “और” शब्द होने के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि उपर्युक्त सभी कारक घरेलू उद्योग पर संबद्ध आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन के निर्धारण को न्यायोचित ठहराने के लिए एक साथ मौजूद रहें।
 - छ) इसके अलावा, व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धति के मैनुअल के अनुसार, विभिन्न अन्य मानदंड इस बात का निर्धारित करने के लिए संगत हैं कि क्या प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आंकलन करना उपयुक्त है।
 - ज) जापानी मिलों का यह अनुरोध है कि वर्तमान जांच में आयातों में या तो स्वतंत्र से अथवा सापेक्ष रूप में वृद्धि नहीं हुई है। विशेष रूप से यह अनुरोध किया गया है संबद्ध देशों से आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में कथित रूप से वृद्धि हुई है, आवेदक के कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक सुधार हुआ था। यह सुधार आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है। आयातों में वृद्धि का कारण मांग में वृद्धि हो सकता है।

- झ) आवेदक यह कह सकते हैं कि टाटा स्टील लिमिटेड के आंकड़े उनके क्षति संबंधी विवरण में नहीं होने के कारण बिक्री में वृद्धि हुई है – हालांकि जापानी मिलों का यह अनुरोध है कि आवेदकों को दोनों तरीके से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। या तो टाटा स्टील लिमिटेड के आंकड़ों को क्षति की अवधि के प्रथम दो वर्षों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा इन आंकड़ों के न होने का उपयोग आवेदकों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए एक बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- य.) आवेदकों द्वारा किया गया विश्लेषण प्रत्येक मापदंड के अनुरूप नहीं है। आवेदकों ने क्षति को दर्शाने के लिए जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच प्रवृत्ति पर विचार किया है जबकि अन्य मामलों में, उन्होंने क्षति को दर्शाने के लिए जांच की अवधि और पिछले वर्ष के बीच प्रवृत्ति का सुविधाजनक ढंग से आंकलन किया है। आदरपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि इन आवेदकों द्वारा क्षति को अपने तरीके से अधिकतम दर्शाने के लिए आंकड़ों में हेर-फेर करने के वास्ते एक पारदर्शी प्रयास है।
- ट) लाभ में उतार-चढ़ाव होता रहा है यद्यपि कीमत में कटौती क्षति की अधिकांश अवधि में स्थिर नहीं है। आवेदक इन वर्षों में लाभ कमाते आ रहे हैं जहां यह दर्शाते हुए कीमत में कथित कटौती हुई थी कि आवेदकों की कीमतों अथवा कार्य-निष्पादन तथा कथित आयातों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- ठ) कटौती और लाभप्रदता के बीच असमानता जापान के मामले में और अधिक हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों की लाभप्रदता में गलत तरीके से और जापान से आयातों के पूर्ण असमानता में वृद्धि हुई है।
- ड) इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री की वसूली पर अथवा आवेदकों की कीमतों पर प्रभाव नहीं डाला है और इस प्रकार से वर्तमान जांच में कीमत न्यूनीकरण/अवमूल्यन नहीं हुआ है।
- ढ) यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति-रहित कीमत का निर्धारण निश्चित रूप से इस नियमावली और सतत-कार्य पद्धति के अनुसार होना चाहिए।
- ण) आवेदक संबद्ध देशों, विशेषकर जापान से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे को साबित नहीं कर पाए हैं।
- त) इन आवेदकों द्वारा यथा-दर्शाए गए आयात भारत में बढ़ती हुई खपत के अनुरूप प्रवृत्ति में मामूली बदलाव के साथ मात्रा में स्थिर रहे हैं। आयातकों का जांच की अवधि में आयातों की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- थ) आवेदक जांच की अवधि के दौरान अपनी कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहे हैं और न्यूनीकरण/अवमूल्यन का कोई लक्षण नहीं है। टीसीआईएल की वार्षिक विवरणी में, उन्होंने कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बारे में उल्लेख किया है और वे अपेक्षाकृत अधिक लागत को अपने ग्राहकों पर थोपने में सफल रहे हैं। आयातित वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- द) गौण उत्पादों के आयातों का इन मिलों की घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि गौण उत्पादों का एक अलग बाजार हिस्सा है। प्राथमिक उत्पादों का आयात मामूली है और यह घरेलू उत्पादकों की तुलना में अधिक कीमत पर हुआ है।
- ध) भारतीय उत्पादकों के लिए उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है। इसके प्रतिकूल टीसीआईएल के लिए सबसे अधिक उत्पादन आंकड़े प्राप्त किए गए हैं।
- न) घरेलू उत्पादकों के लिए बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष में 100 से बहुत अधिक बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 512 हो गया है। इस प्रकार से, संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हो रही है।
- प) आवेदकों की क्षमता में भी क्षति की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। आवेदक 100% से अधिक क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू बाजार में बिक्री में

- भी आधार वर्ष से जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और उसी प्रकार से बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक सुधार हुआ है। कर्मचारियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शाया गया है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है।
- फ) बाजार हिस्से में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। टीसीआईएल भारत में खपत की जाने वाली प्राथमिक टिनप्लेट का 68% बिक्री करता है।
- ब) इन उत्पादकों के नकद लाभ में बहुत मामूली गिरावट आई है। कर-पश्चात लाभ में गिरावट मुख्य रूप से हास-शुल्क में वृद्धि के कारण हुई है। टीसीआईएल ने 2018-2019 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्वयं यह उल्लेख किया है कि कंपनी की लाभप्रदता में कच्चे माल की अपेक्षाकृत अधिक लागत के कारण गिरावट आई है। टाटा स्टील जो टीसीआईएल को कच्चे माल की आपूर्ति करता है तथा टीसीआईएल में उसका अधिकांश शेयर है, 2018-2019 में 29% के सकल लाभ मार्जिन का लाभ उठा रहा है। आवेदकों ने लाभों में कमी के लिए एक कारण के रूप में आयातों को दोषी बताकर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश की है।
- भ) उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं आई है। जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, दोनों आवेदक प्रायः हर चीज की बिक्री कर रहे हैं जिसका वे अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। टीसीआईएल ने *** मी.टन की क्षमता के साथ 2018-2019 में *** मी.टन का उत्पादन किया। जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट कंपनी प्रा. लिमिटेड ने *** मी.टन की क्षमता के साथ 2018-2019 में *** मी.टन का उत्पादन किया।
- म) दोनों उत्पादक भारत में प्राथमिक टिनप्लेट की खपत में वृद्धि कर रहे हैं। वास्तव में 15 लीटर ऑयल केन का फिर से उपयोग नहीं किए जाने के कारण नए एफएसएसआई प्रवर्तन की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राथमिक टिनप्लेट का एक अन्य 200,000 मी.टन खाद्य तेल कंपनियों द्वारा अपेक्षित होगा। दोनों आवेदकों, टीसीआईएल और जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट प्रा. लिमिटेड (अपनी मूल कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के माध्यम से) का विस्तार किया जा रहा है और क्षमता का विस्तार हो रहा है।
- य) आवेदकों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को बहुत अधिक संचित माल भंडार का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकारी को कंपनी की राजस्व की तुलना में माल भंडार की राशि पर विचार करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। 2017-2018 में प्रचालन से टीसीआईएल का राजस्व 1918.69 करोड़ रु. था जबकि उनका तैयार माल भंडार 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार केवल 45.28 करोड़ रु. का था जिसमें पारगमन में सामान शामिल है। यह उनके समग्र बिक्री का मात्र 2.35 % है। इसके साथ ही यह नोट किया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान, बिक्री 2584.50 करोड़ रु. थी और तैयार सामान के लिए माल भंडार 33.96 करोड़ रु. है जिसमें पारगमन में वस्तु भी शामिल है। यह माल भंडार कुल बिक्री का केवल 1.31 % हैं। आवेदक इस सूचना को, इसे गोपनीय बनाकर छिपाने की कोशिश कर रहा है।
- कक) माल भंडार की प्रवृत्ति में 100 से 593 तक की वृद्धि का कारण यह है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान टीसीआईएल टाटा स्टील के लिए जॉब-वर्क किया करता था और इस कारण से 2015-2016 में तैयार माल-भंडार 833.90 करोड़ रु. के प्रचालन से राजस्व के साथ 0.76 लाख रु. का है। उन्होंने कभी भी किसी स्टॉक को नहीं रखा था। आवेदकों ने आधार-वर्ष में केवल कम माल-भंडार का लाभ उठाने की कोशिश की है और वे बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाकर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
- खख) टीसीआईएल 1400 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है और यह संख्या जांच की अवधि के दौरान वही रही है तथा कर्मचारियों की संख्या में कोई गिरावट नहीं देखी जा सकती है।
- गग) आवेदकों का यह दावा है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात बहुत अधिक है और यही घरेलू उद्योग की क्षति का एकमात्र कारण है जिसे जीपीटी और सेल का उदाहरण देकर बताया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

- I. पृष्ठ 10 और 28 पर टीसीआईएल के वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 में यह नोट किया है कि टीसीआईएल की लाभप्रदता में कच्चे माल की अपेक्षाकृत अधिक लागतों के कारण गिरावट आई।
 - II. क्रिसिल के अनुसार, जेएसडब्ल्यू की लाभप्रदता पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को वसूले जाने में विलंब के कारण हुई है। इसके साथ ही अस्थायी रूप से संयंत्र के बंद होने और विमुद्रीकरण ने भी जेएसडब्ल्यू के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव डाला है।
 - III. जेएसडब्ल्यू की पृष्ठ सं. 25 पर वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, कंपनी के राजस्व में सरकार द्वारा घोषित कुछ नियामक उपायों के कारण गिरावट आई।
 - IV. सेल और जीपीटी लिमिटेड द्वारा संबद्ध देशों से आयातों के कारण अपने उत्पादन को बंद करने के संबंध में, आवेदकों ने कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार वह केवल एक अनुमान है और उसकी पुष्टि नहीं की गई है।
- घघ) आवेदकों ने यह उल्लेख किया है कि यदि पाटन जारी रहता है तब वे ऋणों का पुनर्भुतान शीघ्र नहीं कर पाएंगे। हालांकि, टीसीआईएल ऋण मुक्त है। टीसीआईएल और जेएसडब्ल्यू स्टील का तुलन-पत्र बहुत अधिक मजबूत है।
- ड.ड.) घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में कोई प्रभावी सूचना का दावा टाटा स्टील के संबंध में सूचना न होने की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। इस नियमावली के नियम 11 और अनुबंध II के संबंध में, घरेलू उद्योग की क्षति के निर्धारण में सकारात्मक साक्ष्य और समान उत्पादों तथा ऐसे उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की वस्तुपरक जांच शामिल है।
- चच) यह अनुरोध किया जाता है कि वास्तविक क्षति के खतरे का दावा खोखला मात्र है क्योंकि नियम 1995 का अनुबंध II के अंतर्गत अनिवार्य आधारों को पूरा नहीं किया गया है:
- i. पाटित आयातों की वृद्धि की अत्यधिक दर
 - ii. आयातों का न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव
 - iii. किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से निशुल्क बिक्री योग्य, अथवा आसन्न, वास्तविक वृद्धि
 - iv. इस वस्तु के माल भंडार की जांच की जा रही है
- छछ) यह स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड टीसीआईएल के साथ क्षति की अधिकांश अवधि (अर्थात् जून, 2017 तक) पीयूसी के उत्पादन में शामिल रहा है। जून, 2017 के पूर्व, विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन क्रियाकलाप टाटा और टीसीआईएल के बीच बंटा हुआ था (यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन टाटा के बुक में दर्ज कर लिया गया है) जिसके द्वारा दोनों संयुक्त रूप से विचाराधीन उत्पादन के उत्पादक थे। इसकी आगे वर्ष 2016-17 के लिए टीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है जिसमें टीसीआईएल का उल्लेख इलैक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट के एक निर्माता के रूप में किया गया है।
- जज) टाटा स्टील लिमिटेड लागत और बिक्री संबंधी आंकड़े इन आवेदकों द्वारा टाटा और टीसीआईएल के संबंधित प्रतिष्ठान होने के बावजूद जुलाई, 2017 से पहले की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- झझ) आवेदकों ने सार्थक टिप्पणियां करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को समर्थ बनाने के उद्देश्य टाटा और टीसीआईएल के बीच मौजूद जॉब-वर्क संबंध की पुष्टि करने के लिए अगोपनीय रूप में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- यय) पीयूसी में एचआर की लागत पीयूसी की लागतों का कम-से-कम 60 % है (ग्रेड और फिनिश के आधार पर) वह कीमत जिस पर कच्चा माल टाटा से टीसीआईएल को हस्तान्तरित किया जाता है, का आंकलन अवश्य किया

जाना चाहिए। यह भी अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के लिए विचार की गई एचआर लागत संगत अवधि के दौरान बाजार कीमत का द्योतक है और यह कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा टीसीआईएल के रिकॉर्ड में अपेक्षाकृत अधिक क्षति दर्शाने के उद्देश्य से टाटा पर नहीं डाला जाए।

- टट) इन पक्षकारों के बीच अंतरण कीमत करार संभवतः न्यूनतम कीमत के लिए आरंभिक सीमा तय करेगा जिसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ध्यानपूर्वक अंतरण कीमत का आंकलन करें और इन दोनों प्रतिष्ठानों के बीच एचआर अंतरण कीमत को बहुत अधिक होने की अनुमति नहीं है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

67. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत् विचार करने के बाद इस नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की है।
68. हितबद्ध पक्षकारों ने टीसीआईएल और टाटा स्टील के बीच हॉट-राल्ड इस्पातों का अंतरण कीमत निर्धारण की निकट जांच की आवश्यकता के संबंध में अनुरोध किया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने जेएसडब्ल्यू वल्लभ और टीसीआईएल दोनों के लिए हॉट-राल्ड इस्पात उत्पादों की अंतरण कीमत निर्धारण की विधिवत् विस्तार पूर्वक जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टाटा स्टील और टीसीआईएल के बीच तथा जेएसडब्ल्यू वल्लभ के बीच भी हॉट-राल्ड इस्पात उत्पादों का कीमत निर्धारण उपयुक्त रूप से किया गया है और कीमत निर्धारण को दूर रखा गया है।
69. हितबद्ध पक्षकारों ने जुलाई 2017 के पहले टाटा स्टील की लागत कीमत निर्धारण संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता के संबंध में अनुरोध भी किया है। वर्तमान जांच में आवेदक जेएसडब्ल्यू वल्लभ और टीसीआईएल हैं। दोनों ने संयुक्त रूप से आवेदन किया है और निर्धारित प्रपत्रों में सभी आवश्यक सूचना दी है। दोनों आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का पूर्ण रूप से सत्यापन किया गया और सत्यापित सूचना पर विचार इस जांच के उद्देश्य से किया गया है। प्राधिकारी को जुलाई 2017 के पहले टाटा स्टील की लागत और कीमत निर्धारण संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों में कोई दम नजर नहीं आता है क्योंकि टाटा स्टील वर्तमान मामले में आवेदक नहीं है। आवेदक ने टाटा स्टील और टीसीआईएल के बीच हॉट-राल्ड इस्पात उत्पादों के कीमत निर्धारण के संबंध में उपयुक्त उचित जांच और सत्यापन किया है तथा हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं पर विचार करने के लिए इस प्रकार की कीमत निर्धारण की सत्यता के संबंध में अपने आप को संतुष्ट किया है।

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (iii) में निम्नानुसार कहा गया है :

“(iii) यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।”

71. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क) विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन की मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख) संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

- ग) इस प्रकार से आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
72. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आंकलन करने के लिए उपयुक्त होगा।
73. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए" ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनमें घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कि कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।
74. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

ज.4.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

75. प्राधिकारी वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत पर विचार किया है। इस प्रकार से आकलित मांग यह दर्शाती है कि यह क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान हालांकि आंशिक रूप से बढ़ा है।

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------|
| जेएसडब्ल्यू वल्लभ की बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| टीसीआईएल की बिक्री | मी.टन | - | - | *** | *** |
| आवेदकों की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 474 | 512 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | - |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 0.31 | - |
| सभी भारतीय उत्पादकों की कुल घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| संबद्ध देशों से आयात | मी.टन | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| अन्य आयात | मी.टन | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| मांग/ स्पष्ट खपत | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 102 | 106 |

ख. संबद्ध देशों से स्वतंत्र रूप में आयात संबंधी मात्रा

76. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| यूरोपियन यूनियन | मी.टन | 89,502 | 98,823 | 1,05,419 | 1,15,681 |
| जापान | मी.टन | 47,292 | 52,594 | 45,504 | 41,017 |
| यूएसए | मी.टन | 35,017 | 36,164 | 47,253 | 36,805 |
| कोरिया गणराज्य | मी.टन | 16,212 | 24,193 | 17,913 | 18,995 |
| संबद्ध देशों से पाटित आयात | मी.टन | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| अन्य देश | मी.टन | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |
| कुल आयात | मी.टन | 2,45,366 | 2,72,274 | 2,66,817 | 2,62,766 |

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से वृद्धि हुई है।

ग. सापेक्ष रूप में संबद्ध देश से आयात

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | पीओ आई |
|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 110 | 104 | 100 |
| भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 112 | 112 | 106 |

78. यह देखा गया है कि भारतीय उत्पादों और मांग की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली अथवा बिना किसी परिवर्तन के कम ज्यादा होता रहा है।

घ. बाजार हिस्सा

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष (2015-16) की तुलना में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई।

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 474 | 512 |
| अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | - |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 0 | - |
| भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 98 | 106 |
| संबद्ध देशों से आयात | मी.टन | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 113 | 115 | 113 |
| अन्य देशों से आयात | मी.टन | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 88 | 88 |
| मांग | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 102 | 106 |
| <u>बाजार हिस्सा</u> | | | | | |
| याचिकाकर्ताओं का हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 462 | 481 |
| अन्य उत्पादकों का हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 0 | - |
| सभी भारतीय उत्पादकों का हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 96 | 100 |
| संबद्ध देशों का हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच की अवधि |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 112 | 112 | 106 |
| अन्य देशों का हिस्सा | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 86 | 82 |

ज.4.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

80. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस बात का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्यथा कीमतें कम होती अथवा कीमतों में वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

81. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय, सभी करों, छूट, बट्टा और कमीशन की कटौती की गई है और एक्स-वर्क्स स्तर पर बिक्री की प्राप्ति का निर्धारण पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से तुलना के लिए की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कीमत में कटौती संबंधी प्रभाव निम्नलिखित होता है:

| विवरण | यूओएम | यूएसए | कोरिया गणराज्य | जापान | ईयू |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------------|---------|--------|
| आयातों की पहुंच कीमत | रु./मी.टन. | 44,299 | 50,069 | 55,771 | 45,973 |
| भाड़े को छोड़कर घरेलू बिक्री कीमत | रु./मी.टन. | *** | *** | *** | |
| कीमत में कटौती | रु./मी.टन.अ | *** | *** | *** | |
| | % | *** | *** | *** | |
| रेंज | | 35 – 55 | 15 – 35 | 10 – 30 | |

82. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत में कटौती न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। यह घरेलू उद्योग पर पर्याप्त कीमत दबाव बना रहा है।

ख. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

83. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमतों में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दिए अनुसार की गई थी:

| विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| बिक्री की लागत | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | रु./मी.टन | 100 | 112 | 112 | 125 |
| बिक्री कीमत | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | रु./मी.टन | 100 | 107 | 111 | 121 |
| पहुंच मूल्य | रु./मी.टन | 42,960 | 42,063 | 42,367 | 47,942 |
| प्रवृत्ति | रु./मी.टन | 100 | 98 | 99 | 112 |

84. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिक्री की लागत में 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 25 सूचीबद्ध अंक तक वृद्धि हुई है परन्तु बिक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान 21 सूचीबद्ध अंकों तक वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाना है कि पाटित आयातों की पहुंच मूल्य क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की तुलना में कम रही है और उससे घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव पड़ा है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

85. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की पहुंच मूल्य से की गई है। विचाराधीन उत्पादन का एनआईपी इस नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम थी जिसे सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

| विवरण | यूनिट | जांच अवधि (रु./मी.टन) | जांच अवधि (अम.डा./मी.टन) |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| ईयू | | | |
| पहुंच कीमत | प्रति मी.टन | 45,973 | 666 |
| क्षति रहित कीमत (एनआईपी) | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % रेंज | 35 – 55 | 35 – 55 |

| जापान | | | |
|--------------------------|-------------|---------|---------|
| पहुंच कीमत | प्रति मी.टन | 55,771 | 808 |
| क्षति रहित कीमत (एनआईपी) | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % सीमा | 10-30 | 10-30 |
| कोरिया गणराज्य | | | |
| पहुंच कीमत | प्रति मी.टन | 50,069 | 725 |
| क्षति रहित कीमत (एनआईपी) | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % रेंज | 25-45 | 25-45 |
| यू एस ए | | | |
| पहुंच कीमत | प्रति मी.टन | 44,299 | 642 |
| क्षति रहित कीमत (एनआईपी) | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | प्रति मी.टन | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री | % रेंज | 40 – 60 | 40 – 60 |

एच.4.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
87. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंड की जांच की है। यह नोट किया जाना है कि जून, 2017 तक, टाटा स्टील लिमिटेड ने टीसीआईएल को हॉट-रोलड कॉयल और टिन की आपूर्ति की जिसने उसे टाटा स्टील लिमिटेड के लिए जॉब-वर्क आधार पर टिनप्लेट में प्रोसेस किया। 1 जुलाई, 2017 से, टीसीआईएल ने हॉट-रोलड कॉयल्स की खरीद टाटा स्टील लिमिटेड से करना शुरू किया है और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करना और बिक्री करना अपने खाते से शुरू किया। तदनुसार टाटा स्टील लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान

विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नहीं लगा हुआ है। जांच की अवधि के दौरान, भारत में विचाराधीन उत्पादों के केवल दो उत्पादक अर्थात् टीसीआईएल और जेएसडब्ल्यू वल्लभ थे जो वास्तव में पीयूसी का उत्पादन कर रहे थे।

88. इस आवेदन में, टीसीआईएल की सूचना 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। 9 महीने की अवधि (1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018) की अवधि के लिए आंकड़े/सूचना का अन्य वर्षों के साथ उचित तुलना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए जहां भी आवश्यक हुआ, वार्षिकीकृत किया गया है।
89. इस मामले के असामान्य तथ्यों को देखते हुए, घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:
- वर्ष 2017-18 और जांच की अवधि के बीच की तुलना ही की गई है क्योंकि टीसीआईएल ने वर्ष 2017 में अपने खाते से उत्पादन और बिक्री शुरू किया और/अथवा;
 - जेएसडब्ल्यू वल्लभ और टीसीआईएल के लिए पृथक आंकलन किया गया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री

90. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| घरेलू उद्योग की क्षमता | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 445 | 445 |
| जेएसडब्ल्यू वल्लभ की क्षमता | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 100 |
| टीसीआईएल की क्षमता | मी.टन | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | 100 | 100 |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 566 | 581 |
| जेएसडब्ल्यू वल्लभ का उत्पादन | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 112 | 112 |
| टीसीआईएल का उत्पादन | मी.टन | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | 100 | 103 |
| घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 127 | 131 |
| जेएसडब्ल्यू वल्लभ का क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** |

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 112 | 112 |
| टीसीआईएल की क्षमता उपयोग | % | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | 100 | 103 |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 474 | 512 |
| जेएसडब्ल्यू वल्लभ की घरेलू बिक्री | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 112 | 110 |
| टीसीआईएल की घरेलू बिक्री | मी.टन | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | 100 | 111 |

ख. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

91. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| लाभ/(हानि) – आवेदक | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 5 | 92 | 52 |
| लाभ/(हानि) – जेएसडब्ल्यू वल्लभ | रु./मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 5 | (47) | (66) |
| लाभ/(हानि) – टीसीआईएल | रु./मी.टन | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | | | 100 | 62 |
| लाभ/(हानि) – आवेदक | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 5 | 434 | 265 |
| लाभ/(हानि) – जेएसडब्ल्यू वल्लभ | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 5 | (52) | (73) |
| लाभ/(हानि) – टीसीआईएल | लाख रु. | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | | | 100 | 69 |

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| नकद लाभ—आवेदक | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 38 | 399 | 318 |
| नकद लाभ—जेएसडब्ल्यू वल्ल | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 38 | 7 | (7) |
| नकद लाभ—टीसीआईएल | लाख रु. | - | - | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | | | 100 | 83 |
| आरओसीई-आवेदक | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 48 | 71 | 44 |
| आरओसीई-जेएसडब्ल्यू वल्लभ | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 48 | 23 | 8 |
| आरओसीई - टीसीआईएल | % | | | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | | | 100 | 62 |

92. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

- क) वर्ष 2017-18 से जांच की अवधि तक के आंकड़ों की तुलना करने पर, यह देखा जा सकता है कि आवेदकों की प्रति यूनिट लाभ और कुल लाभ लगभग आधी हो गई है।
- ख) जेएसडब्ल्यू वल्लभ के मामले में यह देखा जा सकता है कि कंपनी 2016-17 तक लाभ कमा रही थी। हालांकि, 2017-18 से यह भारी घाटा उठाती रही है। टीसीआईएल के लाभ भी 2017-18 की तुलना में कम हो गए हैं।
- ग) लाभप्रदता की समान प्रवृत्ति के बाद, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में बहुत अधिक गिरावट आई है और यह 2017-18 में 399 सूचीबद्ध इकाई से घटकर जांच की अवधि में 318 सूचीबद्ध इकाई हो गई है।
- घ) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की आरओसीई में 2017-18 से जांच की अवधि तक 27 सूचीबद्ध इकाई तक कमी आई है। इसी प्रकार से यदि जेएसडब्ल्यू वल्लभ और टीसीआईएल के लिए अलग-अलग देखा जाए तब आरओसीई में भी गिरावट आई है।

ग. रोजगार, उत्पादकता और वेतन

93 क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और वेतन नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| रोजगार-घरेलू उद्योग | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 569 | 563 |
| वेतन | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 1,086 | 1,174 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | मी.टन/सं. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 99 | 103 |
| प्रतिदिन उत्पादकता | मी.टन/दिन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 566 | 581 |

94. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता क्षति की जांच की अवधि और जांच की पूरी अवधि में मामूली परिवर्तन के साथ स्थिर रही है:

घ. मालसूची

95. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| औसत भंडार | मी.टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सरणीकृत | 100 | 85 | 179 | 593 |

96. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची में कमी आई है

ड. वृद्धि

97. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओसीई 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान और खराब हो गई है।

| विवरण | यूओएम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | जांच अवधि |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) | | | | | |
| उत्पादन | वर्ष/वर्ष % | - | 2% | 452% | 3% |
| क्षमता उपयोग | वर्ष /वर्ष % | - | 2% | 24% | 3% |
| घरेलू बिक्री | वर्ष /वर्ष % | - | 5% | 351% | 8% |
| बिक्री की लागत | वर्ष /वर्ष % | - | 12% | 1% | 11% |
| बिक्री कीमत | वर्ष /वर्ष % | - | 7% | 4% | 9% |
| लाभ/हानि | वर्ष /वर्ष % | - | -95% | 1679% | -44% |
| निवेश पर आय | वर्ष /वर्ष % | - | -52% | 46% | -38% |

च. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

98. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि इसकी वित्तीय स्थिति की वर्तमान हालत उन्हें नए निवेश के लिए पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं देता है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

99. घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों को बढ़ाने तथा संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा बनाए गए कीमत दबाव में अपने निवेशों पर अच्छी आय अर्जित करने के लिए अनुमति न देने वाला प्राथमिक कारक संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा लगाया गया कीमत दबाव है।

ज. 4.4 क्षति का आकार और क्षति मार्जिन

100. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योगों के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग का एनआईपी तय किया गया है और इस पर क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए की गई है तथा वही उत्पादन इसी उत्पादन पर विचार प्रति इकाई निर्धारित लागत तय करने के लिए किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च नहीं वसूला गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित लाभ (कर-पूर्व 22% की दर से) की अनुमति अनुबंध III में यथा-निर्धारित तथा यथा-अपनाए जा रहे एनआईपी को तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जित का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

| उद्गम का देश/निर्यात | उत्पादक | एनआईपी (अम.डा./ मी.टन) | पहुंच मूल्य (अम. डा./मी. टन) | क्षति मार्जिन (अम.डा./ मी.टन) | क्षति मार्जिन % | रेंज |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|-------|
| जापान | निप्पन स्टील कारपोरेशन, जापान | *** | *** | शून्य | शून्य | शून्य |
| जापान | निप्पन स्टील कारपोरेशन से इतर | *** | *** | *** | *** | 20-40 |
| यूएसए | अन्य कोई | *** | 642 | *** | *** | 40-60 |
| ईयू | अन्य कोई | *** | 666 | *** | *** | 40-60 |
| कोरिया गणराज्य | अन्य कोई | *** | 725 | *** | *** | 25-45 |

ज. 5. क्षति संबंधी निष्कर्ष

101. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों में जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इन आयातों के कारण भारत में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव भी पड़ रहा है।

102. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव के कारण क्षति हुई है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और लाभ में जांच की अवधि के दौरान काफी हद तक गिरावट आई है। उपर्युक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भारत में पी यू सी के पाटित आयातों में वृद्धि होने के कारण वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और कारण न बतलाने संबंधी विश्लेषण

103. इस नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर ना बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा उनकी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियों, प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात कार्य-निष्पादन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात अधिक मात्रा में नहीं हुआ है।

(ख) निर्यात कार्य निष्पादन

105. प्राधिकारी ने आवेदकों के घरेलू प्रचालनों के लिए इसके क्षति विश्लेषण हेतु आंकड़ों पर विचार किया।

(ग) प्रौद्योगिकी का विकास

106. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कोई मुद्दा उठाया है।

(घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन आवेदकों द्वारा उत्पादन की जा रही और बेची जा रही अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण होता हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ङ.) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति

108. विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और उसका स्वतंत्र रूप में आयात देश में किया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

(च) मांग में संकुचन और उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन

109. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

झ.1 कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

110. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी इस प्रकार से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :

क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की समग्र अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों में स्वतंत्र रूप में 2015-16 में 1,88,023 मी.टन से जांच की अवधि में 2,12,498 मी.टन तक वृद्धि हुई है।

- ख) भारत में हो रहे कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती/कम कीमत पर बिक्री हुई है।
- ग) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। 2017-18 में 434 सूचीबद्ध इकाईयों के कुल लाभ से, जांच की अवधि में लाभ में 265 सूचीबद्ध इकाईयों तक बहुत अधिक कमी आई है।
- घ) वर्ष 2017-18 में 399 सूचीबद्ध इकाईयों के नकद लाभ से, नकद लाभ बहुत अधिक गिरकर जांच की अवधि में 318 सूचीबद्ध इकाई हो गई है।
- ङ.) घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) 2017-18 में 71 सूचीबद्ध इकाई से घटकर जांच की अवधि के दौरान 44 सूचीबद्ध इकाई हो गई है।
- च) ऐसा कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति, प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे, निर्यात कार्य-निष्पादन से संबंधित मुद्दे, उत्पादकता से संबंधित मुद्दे अथवा कोई अन्य कारक नहीं हैं जिसे घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति का कारण माना जा सकता है।
- छ) विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में आधार-वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार मांग में गिरावट को घरेलू उद्योग की क्षति के लिए कारण नहीं माना जा सकता है।
- ज) संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रा के मामले में बहुत अधिक नहीं हुआ है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति होती हो अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता हो। इसके अलावा, वह कीमत जिस पर ये वस्तु अन्य देशों से आ रही हैं, उस कीमत से बहुत अधिक है जिस पर ये वस्तु संबद्ध देशों से आ रही हैं।

ख. प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

ख. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

111. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- क) घरेलू उद्योग ने अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र, घरेलू उद्योग का आधार, पाटन विश्लेषण और क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रकटन विवरण में किये गये अपने प्रस्तावों की पुष्टि करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है।
- ख) घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि क्रोमियम-रहित कोटिंग टीन प्लेट पर केवल एक अन्य प्रकार की निष्क्रियता है और इसे अभी ठोस साक्ष्यों के अभाव में विभिन्न टिन मिलों द्वारा वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाना है। इस उत्पाद का अनुमोदन इंटरनेशनल टिन प्लेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लंदन द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण से इस उत्पाद की कोई मांग नहीं है। जब और जैसे ही मांग होती है, भारतीय टिन मिल उसका उत्पादन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।
- ग) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि बिसफेनोल ए रहित उत्पादन टिन मुक्त इस्पात पर पोलिमेर कोटिंग के अलावा कुछ नहीं है, जो विचाराधीन उत्पाद का भाग है। इस प्रकार के उत्पादों की भारत में न तो कोई मांग है और न ही विभिन्न केन निर्माता उपयोगों विशेषकर वेल्डिंग तक इसकी सीमाओं के कारण विश्व भर में मांग की जा रही है। भारत में मौजूदा टीन मिल उत्पाद बिसफेनोल ए मुक्त लेकरों की किस्मों का उपयोग करते हैं। इसे ग्राहकों और गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है।
- घ) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे इस बात का सत्यापन करें कि क्या निप्पोन स्टील कारपोरेशन के लिए पहुंच मूल्य और परिणामी क्षति गणना करने के लिए किसी गैर पी यू सी उत्पाद को शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन शून्य हुआ हो। निप्पोन स्टील कारपोरेशन भारत को “इकोकोट” नामक उत्पाद का निर्यात करता है, जिसमें जिंक और टिन

को मिलाकर कोटिंग अथवा प्लेटिंग किया जाता है। निप्पोन स्टील कारपोरेशन द्वारा निर्मित एक अन्य ऐसा उत्पाद “इकोट्रियो” है जो जिंक, निकल और टिन का मिश्रण है। ये उत्पाद वर्तमान जांच की पी यू सी की तुलना में बहुत अधिक महंगी है और यदि इस प्रकार के उत्पादों को पहुंच मूल्य की गणना में शामिल किया जाता है तब यह निश्चित रूप से पर्याप्त पाटन मार्जिन के होने के बावजूद क्षति मार्जिन को बहुत अधिक सीमा तक कम करेगा।

- ड) इण्डिया जापान सी ई पी ए के अनुसरण में, जापान से पी यू सी के आयातों पर मूल सीमा शुल्क शून्य है। इस कारण से, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को जापान से होने वाले आयातों के पहुंच मूल्य की गणना करते समय सतर्क होना ही चाहिए। किसी मूल सीमा शुल्क को जापानी आयातों की पहुंच मूल्य की गणना करते समय जोड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि जापान से आयातों के पहुंच मूल्य की गणना करते समय मूल सीमा शुल्क को जोड़ा गया हो तब पहुंच मूल्य अधिक हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप क्षति का मार्जिन कमतर होगा।

ख. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

मैसर्स ओहमि इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा किया गया अनुरोध

- क) टिन मुक्त इस्पात के ग्राहक क्राउन केप का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक उत्पादकता और शिथिल गुणवत्ता के लिए जापान के मूल की सामग्री का उपयोग करते हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क को जे एफ ई/ टोयो कोहान का टी एफ एस सामग्री पर जोड़ा जाता है तब अंतिम उपभोक्ता को इस भार का वहन करना होगा।

मैसर्स निप्पोन स्टील कारपोरेशन, जे एफ ई स्टील कारपोरेशन, टोयो कोहान कं. लिमि., जापानी मिलों की ओर से आर्थिक कानून कार्यपद्धतियों द्वारा किया गया अनुरोध

- ख) निप्पोन स्टील कारपोरेशन ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच परिणामों में इसके लिए निर्धारित क्षति मार्जिन की पुष्टि करें। भारत में पाटनरोधी जांचों के लिए लागू कमतर शुल्क नियम के अनुरूप, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त नियम का पालन करें और अंतिम जांच परिणामों में निप्पोन स्टील कारपोरेशन पर शून्य शुल्क लगायें।
- ग) प्राधिकारी ने सत्यापित आंकड़ों पर विचार नहीं किया है कि निप्पोन स्टील कारपोरेशन और उसके सदृश्य व्यापारियों/ निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंतर कोआ कंपनी लिमि. जिसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, से बने एक चैनल के लिए पहुंच कीमत की गणना के कारण प्रमुख रूप से बढ़ गया है। क्षति मार्जिन की गणना बिक्री के सभी चैनलों (कोआ सहित) के लिए की गई है। यद्यपि इस कंपनी ने इस जांच में भाग नहीं लिया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे तदनुसार क्षति के मार्जिन की गणना से कोआ के लिए बिक्री के चैनल को समाप्त कर दें।
- घ) निप्पोन स्टील कारपोरेशन के लिए एक संदर्भ कीमत के फॉर्म के बजाय शुल्क के एक निर्धारित फॉर्म (अर्थात् एन एस सी के लिए शून्य यू एस डॉलर/ प्रति मी. ट.) की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- ड) (i) पोलिमर लेमिनेटिड टिन प्लेट जो विसफेनोल-ए/ बी पी ए रहित है और (ii) पोलिमर लेमिनेटिड टिन मुक्त इस्पात जो विसफेनोल-ए/ बी पी ए मुक्त (सामूहिक रूप से “पी एल टी” के रूप में संदर्भित) है, ये उत्पाद फिल्म लेमिनेटिड उत्पाद हैं और यह पी यू सी की परिभाषा के अंतर्गत दिये गये मानदंडों “चाहे लेकर किया हुआ और/ अथवा प्रिंट किया हुआ अथवा नहीं” को पूरा नहीं करता है। प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियों को “पोलिमर लेमिनेटिड टिन प्लेट जो विसफेनोल-ए/ बी पी ए मुक्त है” तक सीमित रखा गया है।
- च) पी एल टी तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से अलग अलग हैं और इसे घरेलू उद्योग के उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

- छ) पी एल टी की मांग, उत्पाद अथवा आयात का निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता है। प्राधिकारी को केवल इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि उपर्युक्त लक्षणों के कारण पी एल टी उत्पाद की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं।
- ज) जे एफ ई स्टील कोरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान पी एल टी से बने आयात प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी के विपरीत हुई है।
- झ) घरेलू उद्योग पी एल टी का वाणिज्यिक रूप से निर्माण अथवा उत्पादन नहीं करता है। इसके अलावा, केवल घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता, यदि आकलन भी किया जाए तो वर्तमान जांच के क्षेत्र के भीतर इस गैर पी यू सी को शामिल करने के औचित्य को नहीं ठहराता है।
- ञ) घरेलू उत्पादकों जो बाहर किये जाने के लिए अनुरोध का विरोध कर रहे हैं से यह अपेक्षित है कि वह दर्शाये कि वे वाणिज्यिक रूप से इन उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, जिसके संबंध में संबद्ध देशों/ प्रयोक्ताओं से इन उत्पादकों के द्वारा बाहर करने की मांग की जाती है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए रिकार्ड पर कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं कि उन्होंने भारत में पी एल टी का वाणिज्यिक रूप से निर्माण और बिक्री की है।
- ट) निपपोन स्टील कोरपोरेशन ने यह अनुरोध किया है कि इसके द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्यात कीमत और उस निर्यात कीमत जिस पर प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए विचार किया जा रहा है, में अंतर है क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। अतः प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटन मार्जिन की गणना के लिए इसके आंकड़ों पर विचार करें।
- ठ) घरेलू उद्योग जे एस डब्ल्यू वल्लभ और जे एस डब्ल्यू स्टील तथा टी सी आई एल और टाटा स्टील के बीच व्यवस्था का ब्यौरा उपलब्ध कराने में असफल रहा है। साथ ही यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने अगोपनीय रूप में उसके संबंध में अपने निष्कर्षों का आधार उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से हितबद्ध पक्षकार इस मुद्दे पर सार्थक टिप्पणियां करने में सक्षम नहीं हैं।

मैसर्स हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमि., मैसर्स ओरिकॉन इंटरप्राइजेज लिमि., मैसर्स कैरा केन कं. लिमि., मैसर्स एशियन कन्टेनर्स, मैसर्स शेड्रॉन लिमि., मेटल कन्टेनर्स मैनिफेक्चर्स एसो. की ओर से एपीजे एसएलजे द्वारा किया गया अनुरोध

- ड) प्राधिकारी ने (i) प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों की उत्पाद के उपयोग, तकनीकी और वाणिज्यिक गैर प्रतिस्थापनीयता; (ii) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तय करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की प्राथमिक सामग्री और गैर प्राथमिक सामग्री की अलग अलग तुलना; (iii) प्राधिकारी की सतत कार्यपद्धति और उचित क्षति विश्लेषण के संदर्भ में टाटा स्टील लिमि. से सूचना की आवश्यकता; (iv) घरेलू उद्योग द्वारा व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के स्पष्ट उल्लंघन से संबंधित अनुरोधों की विवेचना नहीं की है।
- ढ) आवेदक उद्योग द्वारा गोपनीयता का दावा अत्यधिक है और व्यापार नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन है।
- ण) प्रकटन विवरण में यह उल्लेख है कि टाटा स्टील का अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में कुछ दस्तावेज घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये हैं। हालांकि, ऐसी कोई सूचना हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रतिवादियों का यह अनुरोध है कि नियम 7 के संबंध में कोई भी दस्तावेज जिसे प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है, अगोपनीय पाठ में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह अनुरोध किया जाता है कि नियम 7 के अनुसार यदि इस प्रकार के दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों को

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब प्राधिकारी अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस प्रकार दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

- त) निरमा लिमि. बनाम भारत सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, वे सभी सूचनाएं जिसका उपयोग प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में किया गया है, उनकी टिप्पणियों के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- थ) टाटा स्टील को टी सी आई एल द्वारा जुलाई 2017 के पूर्व वसूले गये जॉब कार्य और जुलाई 2017 के बाद क्षति का दावा करते समय टी सी आई एल द्वारा दावा किये गये परिवर्तन शुल्कों का प्राधिकारी के विश्लेषण का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों को अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- द) इस मामले की शुरुआत 28 जून, 2019 को की गई थी और 12 महीने की सांविधिक समय सीमा 27 जून, 2020 को समाप्त हो रही है। इस कारण से, प्राधिकारी के पास टाटा स्टील से लागत संबंधी आंकड़े मंगाने के लिए और उचित विश्लेषण करने के लिए 36 दिन हैं। यहां यह भी उल्लेख करना संगत है कि पिछले वर्षों के लिए टाटा स्टील की लागत का उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी हमेशा 27 जून, 2020 के बाद सांविधिक रूप से अनुमति दी गई समय विस्तार की मांग कर सकते हैं।
- ध) प्राधिकारी ने सतत् रूप से निर्यातकों के उत्तरों को अस्वीकार कर दिया है, जहां भी संबंधित पक्षकारों के संबंध में सूचना नहीं दी गई है। इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल” से संबंधित जांच के संबंध में दिनांक 11.01.2015 का फाइल सं. 14/1/20123 – डी ए ए डी संगत है।
- न) प्राधिकारी ने विगत में इस आधार पर निर्यातक के समग्र उत्तर को अस्वीकार कर दिया है कि एक मध्यवर्ती यद्यपि वह संबंधित नहीं है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। प्राधिकारी कृपया इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “कोड न किया हुआ कोपियर पेपर” की जांच का संदर्भ कृपया दिनांक 30.10.2018 की फाइल सं. 6/32/2017 – डी जी ए डी के संबंध में लें।
- प) प्रकटन विवरण में इस बात का भी उल्लेख नहीं था कि किस प्रकार से वर्तमान मामला आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल” से संबंधित जांच और इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “कोड न किये हुए कोपियर पेपर” की जांच से अलग है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि ऊपर में उल्लेख किये गये मामलों के ली जा रही भिन्नता के अभाव में, निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य थे।
- फ) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 के प्रावधान के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की प्रवृत्ति पर नजर डालें। हालांकि, चूंकि टाटा स्टील से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है, अतः घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन के संबंध में प्रवृत्ति गलत तरीके से देखी जा सकती है।
- ब) यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि टाटा स्टील (टी सी आई एल का संबंधित पक्षकार) जून 2017 के पहले एक घरेलू उत्पादक था। इसके अलावा, जी एस टी लागू होने के बाद, संबंधित पक्षकारों (टी सी आई एल और टाटा स्टील) के बीच एक समझौता टी सी आई एल को घरेलू उत्पादक के रूप में दर्शाने के लिए किया गया था। हालांकि, खरीद और बिक्री की व्यवस्था के अलावा दोनों संबंधित पक्षकारों के कार्यकलाप बिलकुल एक जैसे रहे। इस कारण से जून 2017 से पहले की अवधि में टाटा स्टील का कार्यनिष्पादन उचित क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से महत्व प्राप्त करता है।

- भ) आयातों अथवा उत्पाद के आदेशों का न होना किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद से बाहर करने से वंचित करने के लिए मानदंड नहीं है। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कृपया बिसफेनोल-ए/ बी पी ए मुक्त और क्रोमियम मुक्त टिन प्लेट को बाहर करें।
- म) यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय निर्माताओं में से कोई भी निर्माता 600 एमएम से कम चौड़ी टिन प्लेट, टी1 टेम्पर और ब्राइट फिनिश का उत्पादन नहीं करता है।
- य) गैर प्राथमिक सामग्री का उपयोग निम्न अंतिम उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए प्राथमिक टिन प्लेट का उपयोग आवश्यक नहीं है। अंतिम वस्तु हैं, जिनके लिए प्राथमिक टिन प्लेट का उपयोग किया जाना अर्थात् खाद्य से संबंधित मदों के लिए अपेक्षित है और ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए प्राथमिक टिन प्लेट के उपयोग अर्थात् जेमोट्रिक बॉक्स, लेम्प, हेयर क्लिप, करटेन रिंग, पेपर क्लिप आदि के उपयोग की अपेक्षा नहीं है।
- कक) प्राथमिक टिन प्लेट भारतीय मानक 2018 का 1993 की शर्त 6 और आई एस ओ 11949: 2016 के अनुसार आदेश देते समय आपूर्तिकर्ता को क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये जाने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। भारतीय मानक अंतिम उपयोग की व्यवस्था करने के लिए शर्त 6.2(जी) के अंतर्गत इसे अनिवार्य बनाता है। शर्त 6.2 की टिप्पणी में यह उल्लेख है कि उपयुक्त इस्पात का चयन आकार बनाने संबंधी क्रियाकलापों जैसे स्ट्रॉमिंग, ड्राइंग, फोल्डिंग, बीडिंग और बेंडिंग तथा एसेम्बली वर्क जैसे ज्वाइन फार्मिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग पर निर्भर है।
- खख) भारतीय मानक के शर्त 6.3 के अंतर्गत, निर्माता को सूचना दी जानी होती है जो आदेश की आवश्यकता को इस उत्पाद के अंतिम उपयोग के अनुरूप बना देता है। फेब्रिकेशन से संबंधित क्रियाकलाप को महत्व दिया जाता है क्योंकि वे परिष्कृत निर्माण क्रियाकलापों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- गग) भारत में टिन प्लेट की आधी खपत गैर महत्वपूर्ण उपयोग का होता है जो किसी अन्य इस्पात उत्पादों के मामले में नहीं है। इस प्रकार का गैर महत्वपूर्ण उत्पाद जिसका मुख्य रूप से उत्पादन लघु और कुटिल उद्योगों द्वारा किया जाता है, भारत में हर जगह पाया जाता है और उसके लिए इच्छित अंतिम उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए प्राथमिक टिन प्लेट अपेक्षित नहीं होता है।
- घघ) प्राधिकारी ने गैर प्राथमिक उत्पादों के साथ प्राथमिक उत्पादों की वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के महत्वपूर्ण पहलू की भी उपेक्षा की है। प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेटों की वाणिज्यिक कीमतों के बीच लगभग 30 प्रतिशत का अंतर है।
- डड) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने भौतिक विशेषताओं तथा प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेटों की कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर को उचित महत्व नहीं दिया।
- चच) यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय भौतिक विशेषताओं और कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्य अंतरों में अंतर को उचित महत्व दें। यह एक मानी हुई स्थिति है कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेट की कीमतें बहुत अधिक अलग अलग हैं।
- छछ) घरेलू उद्योग ने विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के अंतर को स्वीकार किया है और वर्ष 2018-19 के लिए टी सी आई एल की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि इसका 68 प्रतिशत प्राथमिक टिन प्लेट घरेलू बाजार हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय मानक भी प्राथमिक टिन प्लेटों और गैर प्राथमिक टिन प्लेटों में अंतर स्थापित करते हैं।
- जज) यह निर्दिष्ट प्राधिकारी और पूरे विश्व के प्राधिकारियों की सतत कार्यपद्धति रही है कि वे अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग रूप में तय किये गये पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करें।

- झ) क्षति मार्जिन तय करते समय प्राधिकारी को घरेलू प्राथमिक उत्पादों के साथ प्राथमिक उत्पाद और घरेलू गैर प्राथमिक उत्पादों के साथ गैर प्राथमिक उत्पाद की पहुंच कीमत की तुलना करनी चाहिए। क्षति मार्जिन तय करते समय प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गये प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेटों का भारित औसत लेकर आयातों के पहुंच मूल्य की गणना करनी चाहिए। यह इस कारण से है कि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गये उत्पादों का भारित औसत घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति को समाप्त करने के लिए क्षति रहित कीमत तथा पहुंच मूल्य के सही स्तर को दर्शाता है।
- ञ) यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने इन आयातों द्वारा हुई क्षति का विश्लेषण करते समय अनुबंध II(iv) की अनिवार्य आवश्यकता की उपेक्षा की है।
- ट) भारत में उत्पादन की तुलना में पाटित आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, भारत में उत्पादन की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। उसी प्रकार से, भारत में खपत की तुलना में पाटित आयातों में भी 2016-17 और 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई। वैसी ही प्रवृत्ति स्वतंत्र रूप में कथित रूप से पाटित आयातों के संबंध में स्पष्ट है, जहां जांच की अवधि में आयातों की संपूर्ण मात्रा ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ठ) कीमत में कटौती और कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण के संबंध में, प्रतिवादी कोई प्रभावी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकटन विवरण में प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेटों के संबंध में पृथक रूप से कोई विश्लेषण शामिल नहीं है।
- ड) घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष में 100 प्रवृत्ति प्वाइंट से बढ़कर जांच की अवधि में 512 प्रवृत्ति हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में, घरेलू उद्योग की बिक्री में 2017-18 में 474 से जांच की अवधि में 512 तक वृद्धि हुई है।
- ढ) टी सी आई एल भी लगभग 900 यू एस डॉलर प्रति मी. ट. की कीमतों पर पर्याप्त मात्राओं में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, जबकि उनकी घरेलू बिक्री कीमत लगभग 1000 यू एस डॉलर प्रति मी. ट. है। यह अनुरोध किया जाता है कि भारत में आयात भी लगभग 900 यू एस डॉलर प्रति मी. ट. पर हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारत में आयात अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानक कीमतों पर हो रहा है।
- ण) संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों में तत्काल पूर्व के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। घरेलू बिक्री में भी तत्काल पूर्व के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि तत्काल पूर्व के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान माल भंडार में इतनी अधिक वृद्धि विशेषकर जब मांग में वृद्धि हुई है, हो सकती है।
- त) 2015-16 और 2016-17 में, टी सी आई एल संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन (यद्यपि टाटा स्टील के लिए जॉब वर्क आधार पर) कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से प्राधिकारी इस तथ्य की उपेक्षा कर सकते हैं और क्षमता, उत्पादन और क्षमता के उपयोग पर 2015-16 और 2016-17 में टी सी आई एल के लिए “शून्य” के रूप में विचार कर सकते हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टी सी आई एल के परिवर्तन क्रियाकलापों जुलाई 2017 के पहले और उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों अवधियों में वे हॉट रोल्ड क्वायल को संबद्ध वस्तुओं में परिणत कर रहे थे।
- थ) प्रकटन विवरण के खंड IV में इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि वास्तव में किस प्रकार से प्राधिकारी ने कच्चे माल की लागत, उपयोगिता की लागत, लागत को सामान्य बनाने के लिए क्षमता का उपयोग की गणना की है।

टिन प्लेट प्रयोक्ता संघ द्वारा किया गया अनुरोध

- दद) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 23 मई, 2020 तक अनुरोध प्रस्तुत करने का प्राधिकारी का निदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, विशेषकर जब विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने सूचित किया था कि उनका कार्यालय मुम्बई एवं इस देश के अन्य भागों में लॉकडाउन के कारण बंद है। प्राधिकारी से एक बार फिर यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दें।
- धध) आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के उद्देश्य से, संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक रुकावट/ वास्तविक क्षति अवश्य होनी चाहिए। हालांकि, घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में बहुत हद तक सुधार हुआ है।
- नन) कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और निश्चित रूप से संबद्ध देशों से आयातों को क्षति नहीं हुई है।
- पप) वर्ष 2015-16 के दौरान क्षमता में 100 प्रतिशत से जांच की अवधि के 445 तक वृद्धि हुई है। तदनुसार, उत्पादन में भी जांच की अवधि के दौरान 581 से आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 तक वृद्धि हुई है।
- फफ) यह स्पष्ट है कि बिक्री की मात्रा में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 से जांच की अवधि के दौरान 512 तक अर्थात् जांच की अवधि के दौरान 5 गुणा वृद्धि हुई है।
- बब) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 से जांच की अवधि के दौरान 481 तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में भी जांच की अवधि के दौरान 100 से शून्य तक गिरावट आई है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि के दौरान लगभग वही रही अर्थात् यह 30-35 प्रतिशत तक रही है। अन्य देशों से आयातों में भी गिरावट आई है। इस प्रकार से बाजार हिस्से का अधिकांश हिस्सा घरेलू उद्योग के पास ही है।
- भभ) कर्मचारियों की संख्या में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है अर्थात् यह आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 की तुलना में 563 हो गई है। इस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या में कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।
- मम) घरेलू उद्योग की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है अर्थात् यह आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान 581 हो गई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- यय) जी पी टी स्टील इंडस्ट्रीज लिमि. उच्च ऋण और कोल्ड रोल्ड शीट पब्लिक क्वाइल पर पाटनरोधी आदेश जिसने उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमत पर सबस्ट्रेट टिन मिल ब्लेक प्लेट का आयात करने की अनुमति नहीं दी, के कारण बंद हो गया।

तमिलनाडू आयातक संघ द्वारा किया गया अनुरोध

- ककक) घरेलू उद्योग संपूर्ण एम एस एम ई क्षेत्र की सेवा करने में सक्षम नहीं है।
- खखख) 12.5 प्रतिशत प्लस उपकर का वर्तमान सीमा शुल्क पहले से ही बहुत अधिक है और यह पहुंच कीमत को और अधिक बढ़ा रहा है। पाटनरोधी शुल्क लगाना एम एस एम ई क्षेत्र के लिए क्षतिकारक होगा।
- गगग) प्राथमिक उत्पादों का एक विशिष्ट उपयोग होता है और गैर प्राथमिक सामग्री का उपयोग इस प्रकार के विशिष्ट उपयोगों में नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक उत्पादों का उत्पादन अंतिम प्रयोक्ता विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और ये शेल्फ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। गैर प्राथमिक सामग्रियों का उपयोग एम एस एम ई द्वारा किया जाता है। वे गैर महत्वपूर्ण और लघु मदों का निर्माण करने के लिए कुछ मशीनों के बजाय कुशल कामगारों को नियुक्त करते हैं।

घघघ) पी यू सी का आयात एच एस कोड 72109090 (ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने वाले क्लेडेड प्लेट), 7107000 (पहले से पेंट किया हुआ गालवालयूम), 71203090 (इलेक्ट्रोलिटिक रूप में जिन के साथ प्लेट किया हुआ अथवा कोड किया हुआ), 72124000 (कलर से कोड किया हुआ स्टील) और 72259900 (विद्युतीय स्टील) के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। इन उत्पादों का पी यू सी की तुलना में अलग अलग उपयोग है। पी यू सी के अंतर्गत इन आयातों को शामिल करने के कारण आयातों की बड़ी हुई मात्रा दर्शायी गई है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुनरावृत्ति सहित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/ अनुरोधों की जांच की है जिसकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में समुचित रूप से समाधान किया गया है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/ अनुरोधों तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों में पहली बार के लिए उठाये गये मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
113. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनेक पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के जारी किये जाने के बाद पहली बार प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध किये हैं। दिनांक 10 सितंबर, 2018 के ट्रेड नोटिस संख्या 11/2018 में हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे जांच के शुरू होने के 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी के समक्ष अपने आपको पंजीकृत करें। ट्रेड नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि बाद के चरण में पंजीकरण के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पक्षकारों की ओर से जांच के अंतिम समय में नये मुद्दों को उठाने का ऐसा दृष्टिकोण और वह भी जांच के किसी चरण में भाग लिये बिना को बिलकुल नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्राधिकारी ऐसे मुद्दों का समाधान समयबद्ध जांच में कुछ सीमा तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा, यह ऐसे अपंजीकृत पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर टिप्पणी करने से अन्य पक्षकारों को रोकता भी है। हालांकि, ऐसे तर्कों को भी रिकार्ड कर लिया गया है और उसका विधिवत समाधान प्राधिकारी द्वारा संभव सीमा तक किया गया है।
114. यह अनुरोध किया गया है कि पोलिमेर लेमिनेटिड टिन प्लेट जो बिसफेनोल-ए/ बी पी ए मुक्त है और पोलिमेर लेमिनेटिड टिन फ्री स्टील जो बिसफेनोल-ए/ बी पी ए मुक्त (सामूहिक रूप से "पी एल टी" के रूप में संदर्भित) उत्पाद एक फिल्म लेमिनेटिड उत्पाद है और यह पी यू सी की परिभाषा के अंतर्गत दिये गये मानदंडों "चाहे लेकर किया हुआ और / अथवा प्रिंट किया हुआ अथवा नहीं" को पूरा नहीं करता है। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह अनुरोध प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के चलन में पहली बार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है। ऐसा कोई भी दावा विगत में इस पर लेमिनेशन के कारण पी यू सी के मानदंडों को पूरा नहीं करते हुए पी एल टी के संबंध में नहीं किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने शुरू से लेकर अंत तक यह माना है कि पी एल टी को अवश्य बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग उसका उत्पादन/ निर्माण वाणिज्यिक मात्राओं में नहीं करता है। किसी भी मामले में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों की जांच की है और यह नोट किया गया है कि पी एल टी टिन प्लेट और टिन मुक्त इस्पात उत्पाद है, जिस पर पोलिमेर कोटिंग लगाया हुआ है। पी यू सी पर अतिरिक्त कोटिंग पी यू सी को अपनी आवश्यक विशेषताओं से वंचित नहीं करता है और इस उत्पाद को पी यू सी के क्षेत्र से बाहर नहीं करता है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि पी एल टी वर्तमान जांच के उद्देश्य से पी यू सी का एक भाग है।
115. हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि पी एल टी का आयात जांच की अवधि के दौरान किया गया है हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए अपनी प्रश्नावली के उत्तर के एक भाग में केवल यह प्रस्तुत किया है कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को पी एल टी का निर्यात किया है और इसके संबंध में कोई सहयोगी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है कि लेनदेन वास्तव में पी एल टी के निर्यात से संबंधित है। हितबद्ध पक्षकार ने डी जी सी आई एंड एस आयात संबंधी लेन देन आंकड़ों में पी एल टी के लेन देन को दर्शाकर अपने दावे की पुष्टि भी नहीं की है। किसी भी मामले में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य की जांच की है और यह देखा गया है कि पी एल टी निर्यात जिसके संबंध में हितबद्ध पक्षकार

द्वारा दावा किया गया है। जांच की अवधि के दौरान भारत को हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये पी यू सी के निर्यात का *** मी. ट. में से *** मी. ट. है। यह दर्शाता है कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा पी एल टी के निर्यात के संबंध में किये गये दावे भारत को हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कुल पी यू सी के निर्यात का केवल 0.006 प्रतिशत होता है। जापान से भारत में जांच की अवधि के दौरान पी यू सी का कुल आयात 41,017 मी. ट. है। इसका अर्थ यह होता है कि पी एल टी निर्यात जिसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये जाने का दावा किया गया है जांच की अवधि के दौरान जापान से पी यू सी के कुल आयातों का केवल *** प्रतिशत है। यह मामूली मात्रा है और इस पर काल्पनिक आधार पर 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में भारत को पी एल टी के निर्यात के संबंध में हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया अनुरोध प्राधिकारी द्वारा लिये गये दृष्टिकोण कि भारत में इस उत्पाद के लिए वाणिज्य अर्थ में कोई वास्तविक मांग नहीं है, का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया है कि जैसे और जब भारत में इस उत्पाद की मांग उत्पन्न होती है, घरेलू उत्पादक उसका उत्पादन करने के लिए और प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

116. मैसर्स निप्पोन स्टील कोरपोरेशन ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत की तुलना में अलग अलग पहुंच मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार किया है। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार प्रावधान नोट करते हैं :

(क) नियमावली के नियम 6(8) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"(8) ऐसे मामले में, जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उसकी पहुँच आवश्यक सूचना तक न होने अथवा एक पर्याप्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराए अथवा जांच में काफी अड़चन डाले, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो।"

(ख) पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के अनुसरण में अनुबंध-2 के पैरा 7 में निम्नलिखित उल्लिखित है:

"..... तथापि, यह स्पष्ट है, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता, तथा इस प्रकार संगत सूचना प्राधिकारियों से रोकी जा रही है, तो ऐसी स्थिति वह परिणाम हो सकता है जो पक्षकार के लिए उससे कम अनुकूल होता है यदि पक्षकार ने सहयोग किया होता।"

117. अतः निर्यात की मात्रा का वह भाग जिसके लिए अपेक्षित सूचना सहित उत्तरों की पूर्ण श्रृंखला प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई है, के लिए ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए की गई है।

118. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने भारत को एन एस सी द्वारा निर्यात की गई मात्रा का केवल *** प्रतिशत के लिए अपेक्षित आंकड़े प्राधिकारी को प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने उत्पादक एन एस सी द्वारा भारत को निर्यात की गई मात्रा (*** मी. ट.) की शेष *** प्रतिशत के संबंध में मूल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों का उपयोग किया है। यह प्राधिकारी की सतत् कार्यपद्धति के अनुसार है।

119. हितबद्ध पक्षकारों ने टी सी आई एल और टाटा स्टील के बीच समझौते पर बल दिया है और विस्तृत अनुरोध किये हैं। इन चिंताओं में से प्रत्येक चिंता का समाधान नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

- I. घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जा रहे टाटा स्टील की अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कोई अगोपनीय पाठ उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी ब्यौरे प्राधिकारी को तब उपलब्ध कराये गये थे जब प्राधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य किया गया। प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति है कि घरेलू उद्योग और विदेशी निर्यातकों दोनों से सत्यापन संबंधी कार्य के दौरान संग्रह किये गये दस्तावेजों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं

कराया गया है। कोई भी अगोपनीय पाठ सत्यापन संबंधी कार्य के दौरान संग्रह किये गये गोपनीय दस्तावेजों के लिए तैयार नहीं किया गया है। यह कार्यपद्धति व्यापार उपचार जांचों में स्थापित वैश्विक कार्यपद्धतियों के अनुसार है।

- II. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने संबंधित और असंबंधित पक्षकारों द्वारा आपूर्ति की गई सूचना की कमी के कारण जहां भी मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं थी निर्यातकों के उत्तरों को सतत् से अस्वीकार किया है। उन्होंने आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोले" के संबंध में दिनांक 11.01.2015 की फाइल सं. 14/1/2013 – डी जी ए डी पर यह उल्लेख करने के लिए विश्वास किया है कि प्राधिकारी ने जहां भी संबंधित पक्षकारों के संबंध में सूचना नहीं दी गई है, विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के उत्तरों को सतत् रूप अस्वीकार किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने विगत में इस आधार पर विदेशी उत्पादक/ निर्यातक के संपूर्ण उत्तर को अस्वीकार कर दिया है कि एक मध्यवर्ती यद्यपि वह संबंधित नहीं था, में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और दिनांक 30.10.2018 के फाइल सं. 6/32/2017 – डी जी ए डी पर इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "कोट न किया हुआ कोपियर पेपर" के संबंध में पाटनरोधी जांच पर विश्वास किया है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्तर को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि टाटा स्टील जो टी सी आई एल का एक संबंधित पक्षकार है, की सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना इस आधार पर अस्वीकार की गई है कि घरेलू उद्योग की संबंधित कंपनी जो जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में नहीं शामिल है लेकिन उत्पादन में शामिल था और विगत में संबंधित वस्तुओं की बिक्री में शामिल था, हितबद्ध पक्षकारों ने एकमात्र मामले के रूप में भी उद्धृत किया है और घरेलू उद्योग के घटक से यथाअपेक्षित पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी मामले का भी उल्लेख नहीं किया है जहां प्राधिकारी द्वारा संबंधित कंपनी से पूर्ण ब्यौरा मांगा गया है और संग्रह किया गया है जो जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल नहीं है लेकिन विगत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल था। हितबद्ध पक्षकार उन जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात श्रृंखला में शामिल असंबंधित व्यापारियों अथवा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल संबंधित कंपनियों द्वारा भाग न लेने के कारण विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के उत्तरों को अस्वीकार करने के संबंध में कुछ मामलों का उल्लेख कर रहे हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा उल्लिखित मामले पूर्ण रूप से बिलकुल अलग तथ्य का उल्लेख करते हैं और वह वर्तमान मामले में बिलकुल लागू नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किये गये मामलों में, विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के उत्तर को (i) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल संबंधित कंपनियों द्वारा भाग न लेना जिसके कारण प्राधिकारी के पास संबंधित उत्पादक/ निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पूर्ण ब्यौरा नहीं था और (ii) जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में शामिल असंबंधित व्यापारियों द्वारा भाग न लेना जिसके कारण प्राधिकारी के पास संबंधित उत्पादक/ निर्यातक के लिए निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पूर्ण ब्यौरा नहीं था, के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की जांच की अवधि में टाटा स्टील न तो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है और न ही संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में शामिल है और इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित मामले वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

- III. हितबद्ध पक्षकारों में से एक पक्षकार ने यह उल्लेख किया है कि टाटा स्टील/ टी सी आई एल के लिए लागत में इन दोनों पक्षकारों की जुलाई 2017 के बाद की प्रचालन पद्धति जिसमें पी सी आई एल ने अपने खाते से टाटा स्टील से हॉट रोल्ड स्टील की खरीद करना और टिन प्लेट का उत्पादन करना

तथा उसकी बिक्री करना शुरू किया, में परिवर्तन के कारण जुलाई 2017 के पहले की स्थिति की तुलना में जुलाई 2017 के बाद लागत में वृद्धि हुई है। कार्यचालन पद्धति में इस परिवर्तन के कारण, टाटा स्टील/ टी सी आई एल जुलाई 2017 के पहले की स्थिति की तुलना में जुलाई 2017 के बाद की अवधि में लाभ में गिरावट दर्शा रहा है। हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में अपने दावे की पुष्टि करने के लिए एक उदाहरण भी दिया है। सर्वप्रथम प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा अपने अनुरोधों के भाग के रूप में दिया गया उदाहरण पुष्टि न किये गये मान्यताओं के आधार पर है और उदाहरण में उपयोग किये गये आंकड़े सही अथवा उपयुक्त सटीक नहीं होते हैं। दूसरा, किसी भी मामले में प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों के पैरा 89 में स्पष्ट किया है कि मामले के असामान्य तथ्यों को देखते हुए इस प्रवृत्ति का विश्लेषण 2017-18 से जांच की अवधि तक किया गया है और तुलना जुलाई 2017 के पहले और जुलाई 2017 के बाद के बीच की स्थिति में नहीं किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन किया जा सके। प्राधिकारी ने यह आकलन किया है कि किस प्रकार से टी सी आई एल के आर्थिक मानदंडों का व्यवहार टी सी आई एल द्वारा जुलाई 2017 से आगे अपने खाते से पी यू सी का उत्पादन और बिक्री शुरू करने के बाद व्यवहार किया है।

- IV. यह तर्क दिया गया है कि टी सी आई एल की क्षमता, उत्पादन और क्षमता का उपयोग 2015-16 और 2016-17 में शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वे उन वर्षों में टाटा स्टील के लिए परिवर्तन क्रियाकलाप कर रहे थे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टी सी आई एल ने जुलाई 2017 के बाद से अपने खाते से पी यू सी का उत्पादन और बिक्री करना शुरू किया और इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
120. इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई कारण उपलब्ध नहीं कराये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी सूचना के बारे में गोपनीय होने के दावे का प्रावधान डब्ल्यू टी ओ प्रावधानों के पूर्णरूप से अनुकूल है। ये प्रावधान समान रूप से सभी हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/ प्रयोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है। संगत नियमावली के अनुसार किसी सूचना के बारे में गोपनीय होने के दावे का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने के कार्य को कारगर बनाने के लिए प्राधिकारी ने दिनांक 7/9/2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 जारी किया है। प्राधिकारी ने विधिवत इस बात की जांच की है कि क्या विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत नियमावली और उपर्युक्त व्यापार नोटिस द्वारा अगोपनीय पाठ दायर किया गया है और जहां भी उपयुक्त पाया गया उनके दावे को स्वीकार किया है।
121. भारतीय निर्माताओं की 600 एमएम से कम चौड़ी टिन प्लेट, टी1 टेम्पर और ब्राइट फिनिश का उत्पादन करने के लिए भारतीय निर्माताओं की क्षमता के संबंध में दिये गये तर्क के बारे में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि यह एक नया दावा है जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लाया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान यह दावा किया था कि घरेलू उद्योग 700 एमएम से कम चौड़े टिन प्लेट का उत्पादन नहीं कर सकता है और इस पहलू का विधिवत जांच और सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था। हितबद्ध पक्षकार जांच के अंत में नये दावे नहीं ला सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अनेक अवसर दिये गये हैं और इस चरण में एक नया दावा जांच की प्रक्रिया को विलंब करने के लिए चाल के रूप में प्रतीत होता है। यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं कि यह 700 एमएम से कम चौड़े टिन प्लेट का उत्पादन करता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य प्रकार से इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
122. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों के बीच अंतिम उपयोग में अंतर के संबंध में अपनी चिंताओं को दोहराया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों के लिए अंतिम उपयोग अधिकांश अनुप्रयोगों में एक जैसा है। यह भी टिन प्लेट प्रयोक्ता संघ द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेट का उपयोग अधिकांश अनुप्रयोगों में एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसा कोई ठोस भौतिक गुण अथवा तकनीकी अंतर नहीं है जो प्राथमिक सामग्री को गैर प्राथमिक सामग्री से अलग कर सके। इस कारण से पी यू सी के क्षेत्र से गैर प्राथमिक टिन प्लेट को बाहर करना

प्रवंचना के लिए अनेक मार्ग खोल देगा। प्राथमिक उत्पादों को गैर प्राथमिक उत्पादों के रूप में कमतर कीमत पर बेचा जा सकता है और पाटनरोधी शुल्कों से आसानी से बचा जा सकता है और इसके कारण जांच करने की समग्र प्रक्रिया निरर्थक हो जायेगी। पी यू सी के प्राथमिक और गैर प्राथमिक ग्रेड के बीच अंतर एक ऐसा मुद्दा है जिसे प्राधिकारी को विभिन्न जांचों में समाधान करना पड़ा है और यह पी यू सी के क्षेत्र के भीतर प्राथमिक और गैर प्राथमिक दोनों ग्रेड के उत्पादों को शामिल करने के लिए प्राधिकारी की सतत कार्यपद्धति रही है। उसको देखते हुए, प्राधिकारी पी यू सी क्षेत्र से गैर प्राथमिक उत्पादों को बाहर करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हैं।

123. हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिन की गणना करते समय प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों के बीच भौतिक विशेषताओं में अंतर और कीमत में अंतर पर विचार नहीं किया है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन, यू एस ए और कोरिया गणराज्य से निर्यातकों/ उत्पादकों ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है और इस कारण से प्राधिकारी को इन देशों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय करना पड़ा। दूसरा, जापान के मामले में, केवल एक उत्पादक को सहयोगी माना गया है और प्राधिकारी ने असहयोग की कुछ सीमा जिसमें प्राधिकारी ने इस उत्पादक के लिए उपलब्ध तथ्यों का उपयोग किया है, को छोड़कर इस पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर इस सहयोगी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। जापान के उत्पादक ने वास्तव में पाटन और क्षति मार्जिन की गणना करते समय प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों के बीच कीमत में अंतर तथा भौतिक विशेषताओं में अंतर पर विचार करने के मुद्दे को भी नहीं उठाया है। तीसरा यह नोट किया जाता है कि पाटन और क्षति मार्जिन की गणना करते समय प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों के बीच कीमत में अंतर और भौतिक विशेषताओं में अंतर पर विचार करने के लिए अनुरोध भारत में आयातकों द्वारा किये गये हैं, जिनके पास सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए अपेक्षित उत्पादन की लागत और अन्य ब्याँरे के संबंध में कोई सूचना मिली है। प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे की विधिवत जांच की है और यह नोट किया है कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों का उत्पादन करने की लागत वही है। गैर प्राथमिक उत्पाद केवल वे उत्पाद हैं जो निर्माण की प्रक्रिया में ग्राहक की आवश्यकता को ग्राहक के अनुकूल बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं और इस कारण से विभिन्न नामावलियों जैसे अपशिष्ट, सेकण्डस, दोषपूर्ण, गलत छपाई, गैर प्राथमिक आदि में वर्गीकृत किया गया है चूंकि प्राथमिक और गैर प्राथमिक टिन प्लेट दोनों के उत्पादन की लागत एक जैसी है। अतः पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करते समय काल्पनिक समायोजनों जिसका दावा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया जा रहा है, करना संभव नहीं है। हितबद्ध पक्षकार आवश्यक रूप से उस स्थिति के बारे में तर्क दे रहे हैं जहां यह मान लिया गया है कि यदि प्राथमिक और गैर प्राथमिक उत्पादों का उत्पादन करने की लागत 1000 यू एस डॉलर है और प्राथमिक उत्पादों की बिक्री 1200 यू एस डॉलर पर और गैर प्राथमिक उत्पादों की बिक्री विनिर्देश संबंधी खामियों के कारण 800 यू एस डॉलर पर किया जा रहा है, प्राथमिक उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य/ एन आई पी की गणना 1200 यू एस डॉलर की कीमत पर और 800 यू एस डॉलर की कीमत के आधार पर गैर प्राथमिक उत्पादों के लिए किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण घाटा वाली बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना गया है। उसी प्रकार से क्षतिरहित कीमत को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है और गैर प्राथमिक उत्पादों की कमतर बिक्री कीमत के आधार पर उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुसार कोई काल्पनिक समायोजन नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी की स्थापित कार्यपद्धति के विरुद्ध है। इसके अलावा प्राधिकारी यह मानते हैं कि क्षति और पाटन मार्जिन की गणना पी यू सी के लिए समग्र रूप में की गई है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत स्थापित विश्व व्यापार संगठन के अधिकार क्षेत्र में निर्धारित किये जाने के लिए पी यू सी का समग्र मार्जिन अपेक्षित है।

124. इस तर्क के संबंध में की अनुबंध II (iv) का अनुपालन क्षति का विश्लेषण करते समय नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि (i) आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में स्वतंत्र रूप में पाटित आयातों में वृद्धि हुई है; (ii) संबद्ध पाटित आयातों के द्वारा कीमत में सकारात्मक कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है। (iii) घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में जांच की अवधि गिरावट आई है। अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में संपूर्ण विश्लेषण किया गया है।
125. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटन विवरण के खंड IV इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि किस प्रकार से वास्तव में प्राधिकारी ने कच्चे माल की लागत, उपयोगिता की लागत, लागत को सामान्य करने के लिए क्षमता के उपयोग की गणना की है, यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण के खंड IV में एन आई पी और सभी संगत लागतों की गणना करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।
126. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के बारे में, उसकी विस्तार के विवेचना अंतिम जांच परिणामों के संगत खंड में किया गया है।
127. प्राधिकारी और गैर प्राथमिक उत्पादों के लिए पृथक रूप से कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें अपनी सतत् कार्यपद्धति के अनुसार समग्र रूप में पी यू सी के लिए कीमत संबंधी प्रभाव का विश्लेषण किया है।
128. 900 यू एस डालर प्रति मी. ट. आयात की कीमत होने के संबंध में जिसका दावा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानक कीमत के रूप में किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। आयातों का पहुंच मूल्य मूल सीमा शुल्क को जोड़ने के बाद भी जांच की अवधि में 900 यू एस डॉलर प्रति मी. ट. से काफी कम है।

| देश | इकाई | पहुंच मूल्य (रु./ मी. ट.) | पहुंच मूल्य |
|----------------|--------------|---------------------------|-------------|
| ई यू | प्रति मी. ट. | 45,973 | 666 |
| जापान | प्रति मी. ट. | 55,771 | 808 |
| कोरिया गणराज्य | प्रति मी. ट. | 50,069 | 725 |
| यू एस एस | प्रति मी. ट. | 44,299 | 642 |

129. हितबद्ध पक्षकारों में से एक पक्षकार द्वारा दिये गये इस तर्क के संबंध में की प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां 23 मई, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी का निदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें हितबद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये हैं। प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अंतिम निर्धारित तारीख 15 मई, 2020 थी जिसे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर 23 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों के पास प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था। एक अर्धन्यायिक निकाय होने के कारण प्राधिकारी का यह सांविधिक दायित्व है कि वे 12 महीने की समय अवधि के भीतर पाटनरोधी जांच को पूरा करें।
130. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कुछ एच एस कोडों के अंतर्गत पी यू सी का आयात नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले, हितबद्ध पक्षकारों ने 8 अंक के एच एस कोड के बजाय कुछ 7 अंकों का एच एस कोड दिया है, जिससे एच एस कोड अस्पष्ट हो गया है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी की समझ के अनुसार यह नोट किया जाता है कि उक्त एच एस कोडों में से सबसे अधिक कोड 'अन्य' श्रेणी के हैं और डी जी सी आई एंड

एस के लेन-देन वार आयात संबंधी आंकड़ों से प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि आयात इन एच एस कोडों के अंतर्गत भी किया जाता है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि सीमा शुल्क वर्गीकरण बाध्यकारी नहीं है बल्कि केवल सांकेतिक प्रकृति का है और इस कारण से इस उत्पाद का विवरण सीमा शुल्क वर्गीकरण पर लागू होगा। इस तर्क के संबंध में की इन एच एस कोडों के अंतर्गत आयातों को शामिल करने के फलस्वरूप आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, यह नोट किया जाता है कि डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों से आयातों की मात्रा और मूल्य की जांच करते समय, आयात मद के विवरण का भी सत्यापन एच एस कोड के अलावा किया गया है और इस कारण से आयात की मात्रा के बढ़ जाने की कोई संभावना नहीं है।

131. घरेलू उद्योग द्वारा निष्पन्न स्टील कोरपोरेशन के लिए पहुंच मूल्य की गणना के संबंध में किये गये अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी ने कार्यचालन पर फिर से विचार किया है और यह नोट किया जाता है कि कोई भी गैर पी यू सी मद को निष्पन्न स्टील कोरपोरेशन के लिए पहुंच मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया गया है और इसके साथ यह भी कि मूल सीमा शुल्क के लिए कोई योग निष्पन्न स्टील कोरपोरेशन के लिए पहुंच मूल्य की गणना करते समय नहीं किया गया है।

132. जनहित के संबंध में चिंताओं का उपयुक्त रूप से समाधान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में किया गया है।

ट. भारतीय उद्योग हित एवं अन्य मुद्दे

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

134. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से विचाराधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करते हुए निर्माण की गई डाउनस्ट्रीम वस्तुओं की कीमत स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप इसका डाउनस्ट्रीम उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, चूंकि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क से कमी नहीं आयेगी। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेगा, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट रुक जायेगी और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।

ठ. निष्कर्ष

135. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों के संबंध में तथा उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर और इन जांच परिणामों में रिकार्ड किये गये अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

क. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात इसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है और इसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई है।

ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई है।

ड. सिफारिश

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश यहां नीचे दिये गये रूप में और तरीके से करते हैं।
137. इस नियमावली के नियम 4(घ) तथा नियम 17 (1) (b) में निहित प्रावधान के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाये जाने के लिए की जाती है।

शुल्क तालिका

| क्र. सं. | शीर्षक/ उप-शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | उत्पत्ति का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | शुल्क राशि | मुद्रा | इकाई |
|----------|---|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090 72259900, 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000* | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | जापान | जापान सहित कोई भी देश | निप्पोन स्टील कोरपोरेशन | NIL | अम. डालर | मी. ट. |
| 2. | उपरोक्त | टिन मिल | जापान | जापान | उपर्युक्त क्र. | 222 | अम. डालर | मी. ट. |

| क्र. सं. | शीर्षक/ उप-शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | उत्पत्ति का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | शुल्क राशि | मुद्रा | इकाई |
|----------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | | सहित कोई भी देश | सं. 1 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक | | | |
| 3 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | यूरोपीय यूनियन, यू एस ए, कोरिया गणराज्य और जापान को छोड़कर कोई भी देश | जापान | कोई भी | 222 | अम. डालर | मी. ट. |
| 4 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | ई यू | यूरोपीय यूनियन सहित कोई भी देश | कोई भी | 310 | अम. डालर | मी. ट. |
| 5 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | यूरोपीय यूनियन, यू एस ए, कोरिया गणराज्य और जापान को छोड़कर कोई भी देश | ई यू | कोई भी | 310 | अम. डालर | मी. ट. |
| 6 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील | यू एस ए | यू एस ए सहित कोई भी देश | कोई भी | 334 | अम. डालर | मी. ट. |

| क्र. सं. | शीर्षक/ उप-शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | उत्पत्ति का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | शुल्क राशि | मुद्रा | इकाई |
|----------|------------------|---|---|---|---------|------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | उत्पाद** | | | | | | |
| 7 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | यूरोपीय यूनियन, यू एस ए, कोरिया गणराज्य और जापान को छोड़कर कोई भी देश | यू एस ए | कोई भी | 334 | अम. डालर | मी. ट. |
| 8 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | कोरिया गणराज्य | कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश | कोई भी | 251 | अम. डालर | मी. ट. |
| 9 | उपरोक्त | टिन मिल फ्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद** | यूरोपीय यूनियन, यू एस ए, कोरिया गणराज्य और जापान को छोड़कर कोई भी देश | कोरिया गणराज्य | कोई भी | 251 | अम. डालर | मी. ट. |

***टिप्पण:** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पी यू सी के विवरण के अनुसार किया जायेगा।

****टिप्पण:** मिल प्लेट रोल्ड स्टील उत्पाद जो कोट किया हुआ अथवा टिन या क्रोमियम/ क्रोमियम ऑक्साइड से या तो एक तरफ अथवा दोनों तरफ प्लेट किया हुआ हो, चाहे लेकर किया हुआ हो और/ अथवा छपाई किया हुआ हो, अथवा नहीं। ये उत्पाद प्राथमिक और गैर प्राथमिक श्रेणी के तथा सभी आकारों में हैं।

न. आगे की प्रक्रिया

138. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

CASE NO: ADD-OI 7/2019

FINAL FINDINGS

Subject: Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP.

F. No. 6/9/2019-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof:

1. M/s. JSW Vallabh Tinplate Private Limited (hereinafter also referred to as “JSW Vallabh”) and M/s. The Tinplate Company of India Limited (hereinafter also referred to as “TCIL”) (hereinafter also collectively referred to as the “Domestic Industry” or “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Act and the Rules for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from European Union, Japan, USA and Korea RP (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/9/2019 -DGTR dated 28th June, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- a) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- b) The Authority issued a public notice dated 28th June 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject Countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

- e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f) The Authority sent Exporters questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

European Union

1. Arcelor Mittal Belgium
2. Arcelor Mittal France
3. Thyssen Krupp Rasselstein
4. Arcelor Mittal Spain
5. Nicomet Tinplate

USA

1. Ohio Coatings Company
2. US Steel
3. ArcelorMittal Weirton
4. USS Posco

Japan

1. JFE Steel Corporation
2. Nippon Steel Corporation
3. Toyo Kohan Co. Ltd.

Korea

1. Dongbu Steel Co. Ltd.
2. POSCO
3. TCC Steel

- g) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response:
1. JFE Steel Corporation, Japan
 2. JFE Shoji Trade Corporation, Japan
 3. Metal One Corporation, Japan
 4. Marubeni Itochu Steel (MI Steel), Japan
 5. Nippon Steel Corporation, Japan
 6. Nippon Steel Trading Corporation, Japan
 7. Ohmi Industries Limited, Japan
 8. Tetsusho Kayaba Corporation, Japan
 9. Toyto Tsusho Corporation, Japan
 10. American International Corporation, USA
 11. Ferreum NV, Belgium (EU)
- h) The Authority sent Importer's/User's Questionnaires to the following known importers/users of product under consideration in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. M/s. Shri Ram Impex (India) Pvt. Ltd.
 2. Zarhak Steels Pvt. Limited
 3. Shetron Limited

4. GP Global Energy Pvt. Limited
 5. M/s. New Gujarat Tin Circle Depot Pvt. Ltd.
 6. Oriental Containers Limited
 7. Modern Packaging
 8. Hi-Can Indsl. Pvt. Ltd.
 9. Hindustan Tin Works Ltd.
 10. Carter Containers Co. Pvt. Ltd.
 11. Bharat Containers Pvt. Ltd.
 12. Asian Containers
 13. Standard Retail Pvt. Ltd.
 14. Kaira Can Company Ltd.
 15. Cans Manufacturing Co.
 16. Shiriniwas Tin Industries
 17. Zenith Tins Pvt. Ltd.
 18. Petrox Packaging (I) Pvt. Ltd.
 19. Mamram Ltd.
- i) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response:
1. Hindustan Tin Works Limited
 2. Oricon Enterprises Limited
 3. Asian Containers
 4. Kaira Can Company Limited
 5. Mercury Industries Limited
- j) The Association of Tinsplate Users also made submissions during the course of the investigation which have been incorporated and duly addressed in these Final Findings.
- k) The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file for the inspection by interested parties.
- l) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of product under consideration for the past three years, and the period of investigation. The same was provided by DGCI&S to the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S transaction-wise data for computation of the volume of imports and other relevant analysis.
- m) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the product under consideration in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- n) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the Applicants, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.
- o) Verification of the information provided by the producers/exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present final findings.
- p) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st January 2018 to 31st December 2018 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.
- q) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 11th October 2019. Subsequently, another oral hearing was held on 6th December 2019 on account of change of the Designated Authority. All the parties who

had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

- r) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present Final Findings.
- s) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority in these Final Findings.
- t) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Findings on the basis of the facts available.
- v) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 8th May 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in the Final Findings. The original deadline for filing comments on the disclosure statement was 15th May 2020 which was extended till 23rd May 2020 on the request of the interested parties. The interested parties were granted 15 days to file comments on the disclosure statement. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- w) *** in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$ 1 = ₹69.02.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration ("PUC") in the present investigation is tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. Tin mill flat rolled steel products include Tinsplate as well as Tin-free steel, which is also known as Electrolytic Tin Plate (ETP) or Tin Free Steel (TFS) or Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). The product under consideration may be supplied in coil form or sheets / scrolls. The sheets / scrolls may be supplied in various shapes including, but not limited to, square, rectangle, circle or any other shape, with or without blanking.

5. The product under consideration is generally used for versatile packaging solutions including, but not limited to food packaging, i.e. edible oil, processed food, fruits, vegetables, beverages, etc. as well as used for non-food packaging, i.e. paints, chemicals, non-edible oil, geometry/compass box, shoe polish, aerosol sprays, batteries, etc

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- a) The PUC in the present investigation is *"Tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. Tin mill flat rolled steel products include Tinsplate as well as Tin-free steel, which is also known as Electrolytic Tin Plate (ETP), Tin Free Steel (TFS), Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). The product under consideration may be supplied in coil form or sheets / scrolls. The sheets / scrolls may be supplied in various shapes including, but not limited to, square, rectangle, circle or any other shape, with or without blanking."*
- b) The product under consideration is classified under tariff item 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090 and 72259900 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the PUC have also been observed in certain other HS codes viz. 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 of the Act.

- c) It has been the consistent practice of the Authority to include both prime and non-prime goods in the scope of the product under consideration, particularly in investigations covering steel products, and not make any distinction between them based on their quality.
- d) There are a number of findings of the authority wherein both prime and non-prime products have been covered within the scope of PUC. In the following investigations, both prime and non-prime quality goods were included within the scope of the PUC:

| Investigation | PUC Defined |
|--|--|
| Anti-dumping investigation concerning imports of “Cold-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP and Ukraine-reg | <i>“The PUC includes cold rolled / cold reduced flat steel products in coils or not in coils including slit coils or sheets, blanks whether or not annealed or box annealed or batch annealed or continuously annealed or any other annealing process or full hard or partially hard. The product concerned covers cold-rolled / cold-reduced flat steel products conforming to prime or non-prime quality whether or not rolled [..]”</i> |
| Anti-dumping investigation concerning imports of “Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel” originating in or exported from China PR-reg. | <i>“The product under consideration in the present investigation is bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel (commonly known as “Wire Rods”). These products are of prime and non-prime category and are in all sizes. These products conform to various qualities of steels including but not limited to electrode, free cutting, forging, cold heading, low / medium / high carbon steels, drawing, ball bearing steel, case hardening steel, spring steel, corrosion resistant steel, weathering steel, structural steel and many more qualities of steel. [...]”</i> |
| Anti-Dumping Investigation concerning import of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series from the People’s Republic of China, the Republic of Korea, and Malaysia. | <i>“Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled Annealed and pickled or Black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or Black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm(width tolerance of + 20mm for mill edge and + 5mm for trim edge).”</i> |

- e) In fact, in the *Anti-Dumping Investigation concerning import of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series from the People’s Republic of China, the Republic of Korea, and Malaysia*, the Authority observed:

“The interested parties have argued that non-prime materials should be excluded from the PUC. The Authority notes that that in the production process both prime and non-prime materials are produced universally and are sold as such. They are used as substitutable products by users in many areas of usage. The cost of production of prime and non-prime goods is not different though the non-prime may be sold at a different price. All the previous investigations conducted, including the safeguard investigation, did not distinguish product on the basis of prime and non-prime nature of the products. Therefore, the Authority does not find any merit in the arguments of the interested parties in this regard.”

- f) Anti-dumping investigations concerning “Nylon Filament Yarn (Multi Filament) originating in or exported from European Union and Vietnam” and “PVC Suspensions Resin from European Union (EU) and Mexico” the Authority held that second-grade/off-grade products cannot be excluded from the scope

of the PUC since they are not different in terms of physical characteristics, manufacturing process, raw materials, functions, usage, cost of production, and tariff classification.

- g) The non-prime products imported into India are competing with the prime products offered by the domestic industry and are displacing the prime products offered by the domestic industry. It has been acknowledged by the Association of Tin-Plate Users in one of its submissions that both prime and non-prime products are substitutable for the same end use applications.
- h) Non-prime products are merely those products which have not been able to meet the customers' requirement in the manufacturing process and are therefore classified in various nomenclature such as waste, seconds, defective, non-prime. etc. Non-prime tin plates also comprise of prime overrun. In fact, it has been admitted in the submissions made by various interested parties that imported non-prime material is equally good in quality as the domestically supplied prime material.
- i) There is no difference in the physical and technical characteristics, manufacturing process, raw materials, functions, usage, cost of production, and tariff classification between prime and non-prime products of the subject goods. Exclusion of non-prime goods would not present the correct situation of the imports of product under consideration and consequent injury caused to the domestic injury.
- j) Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has mandated quality conformity for food packaging in Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018. Clause 7.5.1 of IS 1993:2018 and IS 12591:2018 allow supply of material with surface imperfections and even damage that renders the material unsuitable for intended use subject to a special agreement between the users and producers. Given this exception, even non-prime PUC is being used even in food packaging applications.
- k) Importers/users using non-prime imported products are also buying prime products from the domestic industry. This further substantiates the fact that there is no tangible difference between prime and non-prime products and both of them are directly substitutable.
- l) Exclusions have also been requested of certain grades from the scope of PUC on the ground that the DI does not have the capacity to produce such grades and therefore the same should be excluded.
- m) For granting any exclusion from the scope of PUC, the Authority needs to verify the following:
 - i. Whether the product/grade for which exclusion is being sought has been imported into India in commercial quantities by the parties seeking exclusion;
 - ii. Whether there is any actual end use application of the product/grade for which exclusion is being sought or the exclusion is being sought only for creating a way for future circumvention; and
 - iii. Whether interested parties have placed any orders on the domestic industry for the products/grades for which exclusion is being sought and whether the domestic industry has shown inability to supply the same.
- n) The interested parties who are seeking exclusions from the scope of PUC have not satisfied any of the three standards and have provided no evidence for any of their claims.
- o) The product scope submitted in the Application only covers products that are either produced by the Applicants or can substitute their product range as a like product. It is submitted that all the exclusions from the PUC requested by the interested parties are either produced by the domestic industry or have not been produced merely because no orders have been placed due to lack of demand in the Indian market:

| Products/Grade Requested to be Excluded | DI's Status on the Production of the Grade |
|---|--|
| Double Reduced tinplate of thicknesses below 0.15 mm and above 0.21 mm | DI produces these grades. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Soft double reduced tinplate of thickness below 0.18 mm and above 0.23 mm | DI produces these grades. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Tinplate with bright finish surface | DI produces this grade. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Tinplate with coating exceeding 11.2 gm/Sqm | DI produces this grade. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Tinplate with width exceeding 1020 mm | DI produces this grade. Relevant documents have been submitted to the Authority. |

| | |
|--|---|
| Tinplate with width below 700 mm | DI produces this grade. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Tin-Free Steel/Electrolytic tinplate | DI produces this grade. Relevant documents have been submitted to the Authority. |
| Polymer Laminated tinplate that are Bisphenol-A / BPA Free | Neither have any orders have been placed for the same on DI, nor have any imports been made for the same. There is no demand in India for the same. |
| Chromium-free tinplate | Neither have any orders have been placed for the same on DI, nor have any imports been made for the same. There is no demand in India for the same. |

- p) Japanese producers have provided technical specifications in confidential version. Such specifications have not been provided in a non-confidential version in order to enable the domestic industry to comment on the same.
- q) The Authority must not exclude grades which may enable the importers to circumvent the duties in the future.
- r) It has been the consistent practice of the Authority not to grant an exclusion from the scope of the product under consideration unless it is demonstrated that the product for which exclusion is being sought has actually been imported by the person seeking exclusion. This position was taken in the final findings of the anti-dumping investigation concerning "*Aluminium Foil originating in or exported from China PR*". This was further affirmed by the Hon'ble CESTAT in the case of *G.M. Alloys Pvt. Ltd. & Ors. v. Union of India*, where the Hon'ble CESTAT did not find any reason to interfere with the findings of the Authority.
- s) Without any actual imports of materials for which exclusion requests are being made by importers, it is submitted that the said interested parties do not have any locus standi for making a request for exclusion of a given grade from the scope of the PUC.

C.2. Submissions made by the other interested parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- a) The product scope identified by the initiation notification is "tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not".
- b) It is an admitted fact that the prime and non-prime material of the product under consideration are commercially different products having different costs, selling price and applications. Therefore, the comparison of prime and non-prime product is not possible.
- c) The domestic industry has tried to mislead the authority by hiding the fact that the majority of imports happening in India are non-prime waste category which is supposed to be cheaper than regular grade subject goods. There are evidences which indicate that the import of the product under consideration from subject countries majorly comprises of non-prime/waste material. In such a scenario, the price comparison and subsequent injury information, cannot be considered as representative of true market condition in India.
- d) It is submitted that, there are two broad categories of products in the primary sector of the PUC: (i) Products manufactured to standard specifications, and (ii) tailor-made products manufactured to customer-specific requirements. The products exported to India fall under the second category i.e. tailor-made products. Some manufacturers in India specifically use said tailor-made products for export-oriented manufacturing. Domestic Industry's products fall under the first category i.e. products manufactured to general industry standards. Upon comparing the technical and commercial parameters concerning domestic and imported products, it is evident that there is a case for exclusion of certain grades in the present investigation.
- e) In the process of making tinplate for specific end uses, many a times products don't meet the stringent requirements of the customers. However, this material is perfectly suitable for other end uses, and are sold as 'Non- Prime' products. Such materials are in mixed specifications and have to be adapted to applications. Non-Prime products cater to users who can afford to be more flexible with the specifications of the product and are able to create the end-products based on the material available at their disposal.
- f) There is a perfect market for such non-prime materials to be sold through tenders or auctions regularly by the Mills. The buyers of such materials generally produce low volume products. These are generally niche

and less sophisticated products, which are very essential and support many other small industries. Such manufacturers are labour intensive and employ people with skills-sets suitable for producing products by using Non-prime Tinplate.

- g) Non-prime material is used to manufacture low end products such as calendar strips, geometric box, shoe polish box, kajal box, lantern, lamps, hair clips, stamp pads, curtain rings, file clips, metal cans and can components, auto ancillary parts, paper clips, agarbatti stands, Puja items, stencils, imitation jewellery, washers for various uses, etc.
- h) It may be noted that nearly half of the consumption of tinplate in India is of non- critical use which is not the case as of any other steel products. Such non-critical products which are mainly produced by the small and cottage industries, are found all over India and do not require Prime Tinplate for the desired end use and applications.
- i) These industries use the Non- Prime Grade Tin Mill Flat Rolled Steel which is produced during the manufacturing of prime grade Tin Mill Flat Rolled Steel. The steel being off grade are available in said countries to various suppliers, through bidding. These suppliers supply it to these small enterprises which is further supplied to small industries at competitive prices.
- j) The Applicants admit that there are two segments of product i.e. prime and non-prime. TCIL clearly states in its annual report for the year 2018-19 that it holds 68% prime tinplate domestic market share. If there were no difference between prime and non-prime products, there would be no requirement to make such a distinction in their Annual Report.
- k) The Chart provided as Attachment-II of the Written Submissions filed by the Association is merely a synopsis of the domestic user industry. However, the same has been incorrectly read by the Applicants to mean that both prime and non-prime products are used by the user industry and thereby both are imported. Applicants have ignored that the procurement is 'mostly indigenous' i.e. procured from the domestic industry and is not affected by imports.
- l) Non-prime products from Europe and USA, are not sold directly by the producers in the subject countries. They are sold in market on auction/tender basis. The exporters collect the winning from the mills in a warehouse and then sell in various markets including domestic markets. Hence, the exporters are unable to provide data of individual purchases for the material being supplied. They are breaking bulk (like wholesalers do while selling to retailers). Consolidated material won over the period of auctions are sold to the highest price paying buyer/ market. The price is comparatively lower than Prime because the specifications are different. The buyers are generally small units and have to compromise on size, thickness, specification, finish and have limited applications.
- m) China is not present in this anti-dumping investigation. This is because China rarely exports non-prime products as they are used within China especially in less developed provinces.
- n) There is no direct competition between the Applicants' products and a majority of Japanese exports – which, at the outset, should be a sufficient ground to establish that the products exported by the Japanese Mills cannot cause or threaten to cause injury to the Applicants.
- o) Prime and Non-prime products are completely different and cannot be used interchangeably. Prime Tinplate, when ordered as per clause 6 of IS 1993 of 2018 and ISO 11949: 2016, requires information to be provided by the purchaser to the supplier. The standard makes it mandatory under Clause 6.2(g) to provide the end use. Note to clause 6.2 mentions that the appropriate steel selection is dependent on the shaping operations such as stamping drawing, folding, beading and bending and assembly work such as joint forming, soldering or welding. Under clause 6.3, the manufacturer is to be provided with information, which makes the order requirement consistent with the end use of the product. Importance is given to the fabrication operation as these are becoming very critical with sophisticated manufacturing operations.
- p) More than 90% of the imports of the PUC are composed of Non- Prime tinplate and Tin free steel. Almost all imports from USA and EU are non- prime. So, a wrong comparison is being made between Prime products of domestic mills and imported non-prime prices.
- q) Prime tinplate is for food application and for use in high speed production lines.
- r) India is a natural choice of non-prime tinplate.
- s) Manufacturers of quality tin cans and components import 50% of their raw material prime tin plate from Nippon Steel in Japan. Despite the higher prices of Nippon Tin plate as compared to domestic prices, tin plate is imported from Japan, and not procured domestically, because of superior quality and timely delivery of goods.

- t) The Association of Tinsplate Users categorically supports FSSAI and BIS standards pertaining to tinsplate used for food, food additives and medicinal applications.
- u) The DGTR Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations notes that the PUC should include those products which are produced and commercially sold by the domestic industry. The Japanese Mills submit that the present product scope includes products which are not being commercially produced and manufactured by the Applicants. Accordingly, the said products not produced and commercially sold by the Applicants ought to be outside the scope of PUC.
- v) The Designated Authority in previous investigations has consistently relied upon certain critical parameters while determining likeness between the imported product from subject countries and the domestic industry's product. Such critical parameters are: Physical and chemical characteristics; Product specifications; Manufacturing process and production technology including plant and equipment; Functions and End-uses; End-user requirement; End-user perception; Distribution and marketing; Technical and commercial substitutability.
- w) Particularly, in one of the past investigations, the Designated Authority has, in fact, specifically excluded certain grades from the scope of investigation as the domestic industry did not show sufficient evidence to prove that they supplied such grades in the period of investigation and did not show equivalence of its grades with the grades that were sought to be excluded by the exporters therein. Further, in another investigation, the Designated Authority has excluded certain products from the scope of PUC as it was not produced by the domestic industry.
- x) Tin free steel should be excluded from the scope of product under consideration in the present investigation.
- y) The characteristics of the Japanese products set them apart on technical grounds:
 - i. For example, one of the grades exported by one of the Japanese Mills is a polymer laminated steel product – the product is Bisphenol-A / BPA free, that is much better suited to food packaging. It is relevant to note that BPA content in food packaging has been banned in many countries worldwide, and some of the Indian customers specifically use Japanese products which are BPA free for their export manufacturing.
 - ii. One of the Japanese Mills also offers Chromium Free products to their customers in India, which have similar safety concerns as authorities across the world are starting to regulate / restrict Cr content in products.
 - iii. The Applicants cannot manufacture BPA-free or Cr-free product or provide a technically/commercially viable substitute to the other Japanese products. Indeed, this is why Indian buyers are willing to pay a higher price for Japanese products – a fact clearly apparent in the landed price calculations provided by the Applicants.
 - iv. There are many other bespoke products like this, in respect of which the Japanese Mills charge premium. Japanese Mills have sought exclusion of such products, specifically by way of their Questionnaire responses filed on September 21, 2019.
- z) The domestic industry is admittedly not producing or has not sold several grades or sizes of the product during the period of investigation. It is submitted that the same are required to be excluded from scope of investigations as per the practice of Authority:
 - i. Double reduced tinsplate of thickness below 0.15MM and above 0.21 MM
 - ii. Soft double reduced tinsplate of thickness below 0.18MM and above 0.23MM
 - iii. Tinsplate with bright finished surface
 - iv. Tinsplate with coating exceeding 11.2 gm/SqM
 - v. Tinsplate with width exceeding 1020 MM
 - vi. Tinsplate with width below 700 MM
- aa) These products are not produced by the domestic producers and therefore, Authority must exclude them from the ambit of product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

8. The PUC in the present investigation is Tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. Tin mill flat rolled steel products include Tinsplate as well as Tin-free steel, which is also known as Electrolytic Tin Plate

(ETP), Tin Free Steel (TFS), Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). The product under consideration may be supplied in coil form or sheets / scrolls. The sheets/ scrolls may be supplied in various shapes including, but not limited to, square, rectangle, circle or any other shape, with or without blanking.

9. The product under consideration imported into India has come either as a prime product or as non-prime product. It is understood that Tinplate requires customization as per the requirement/demand of the customer. During the manufacturing process, if there is any non-conformity with the requirement of the customer such as surface finishing, printing, thickness, coating etc. then such products are sold as non-prime at a lower price since they do not meet the requirement of the originally intended customers. In other words, non-prime products are merely products which have not been able to meet the customization requirement in the manufacturing process and are, therefore, classified in various nomenclatures such as waste, seconds, defective, misprint, non-prime, etc. Non-prime tin plates also comprise of prime overruns.

10. Some interested parties have made submissions that non-prime goods should be excluded from the scope of the PUC on account of following broad reasons:

- a) The imported non-prime and domestic produced prime products are not like articles
- b) Prime goods are not substitutable by non-prime goods due to low quality and cheaper price. Non-prime products are used for low end items.
- c) Prime and non-prime goods are used in different industries and for different end-use application.
- d) There is no direct competition between prime and non-prime products.

11. With regard to like articles, Rule 2(d) of the Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

12. As per the consistent practice of the Authority, non-prime products are considered as part of product under consideration as long as they meet the criteria specified for product under consideration. There is no reason to exclude them from the scope of product under consideration and to place them on different footing in view of the fact that basic manufacturing process, the applications and uses of the imported product (in both prime and non-prime grades) and that manufactured by the Applicants are the same. The cost of manufacture also remains the same for both prime and non-prime products and it does not change with the resultant type manufactured.

13. After considering the information on record, the Authority notes that the basic manufacturing process, the applications, uses and cost of manufacture of the imported product (for both prime and non-prime grades) and that manufactured by the Applicants are the same. The Authority further notes that there are no firm physical attributes or technical distinctions that differentiate the prime material from the non-prime or secondary qualities of the subject goods. Exclusion of such products from the scope of the product under consideration would give rise to the scope for circumvention by the exporters and foreign producers. Therefore, the Authority includes both prime and non-prime under the product under consideration and not make any distinction between them based on their quality.

14. Some interested parties have sought exclusion of certain specialized grades/ categories with specific technical parameters from the purview of product under consideration

- Double Reduced tinplate of thicknesses below 0.15 mm and above 0.21 mm
- Soft double reduced tinplate of thickness below 0.18 mm and above 0.23 mm
- Tinplate with bright finish surface
- Tinplate with coating exceeding 11.2 gm/Sqm
- Tinplate with width exceeding 1020 mm
- Tinplate with width below 700 mm
- Tin-Free Steel or Electrolytic tinplate
- Polymer Laminated tinplate that are Bisphenol-A / BPA Free
- Chromium-free tinplate

15. The submissions made by these interested parties and the technical details provided by the domestic industry in this regard have been examined. The domestic industry has established that it produces Double Reduced tinplate of thicknesses below 0.15 mm and above 0.21 mm, Soft double reduced tinplate of thickness below 0.18

mm and above 0.23 mm, Tinplate with bright finish surface, Tinplate with coating exceeding 11.2 gm/Sqm, Tinplate with width exceeding 1020 mm, Tinplate with width below 700 mm, and Tin-Free Steel. Therefore, no exclusions are required for these products. With regard to Polymer Laminated tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free and Chromium-free tinplate, the Authority notes as follows:

- a) The domestic industry has submitted that there are no imports of these two types of products into India during the POI and there is no demand for these two types of products in India. On the basis of the examination carried out during the course of the investigation, the Authority prima facie agrees with the submissions made by the domestic industry.
- b) The request for exclusion of these two types of products has been made by the Japanese exporters and not by any Indian users. No evidence has been placed before the Authority by any Indian user establishing the fact that orders have been placed on the domestic industry for these two types of products and the domestic industry has shown its inability to produce and supply these two types of products.

16. In view of the above, the Authority concludes not to exclude Polymer Laminated tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free and Chromium-free tinplate from the scope of product under consideration. The Authority also notes that unwarranted exclusions from the scope of product under consideration may lead to circumvention of the measures.

17. On the basis of submissions made by various interested parties and the information on record, the Authority holds that the product under consideration be described as under:

“Tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. These products are of prime and non-prime category and in all sizes. Tin mill flat rolled steel products include Tinplate as well as Tin-free steel. The product under consideration, depending on coating/plating material used is known as Electrolytic Tin Plate (ETP) or Tin Free Steel (TFS) or Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). The product under consideration may be supplied in coil form or sheets / scrolls. The sheets / scrolls may be supplied in various shapes including, but not limited to, square, rectangle, circle or any other shape, with or without blanking.

18. The product under consideration is classified under tariff headings 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090 and 72259900 of the Customs Tariff Act, 1975. Imports of the PUC have also been observed in certain other HS codes viz. 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the classification is indicative only and not binding.

19. With regard to like article, Rule 2(d) of the Rules provides that "like article " means *an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation.* After considering the information on record, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry is comparable to the product under consideration exported from subject countries in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods and that the two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the Applicant domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

20. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

- a) There are only four known producers of the product under consideration in India. The status of these four known producers during POI is given below:

| | |
|---|------------------------|
| JSW Vallabh Tinplate Private Limited: | Applicant (Active) |
| The Tinplate Company of India Limited (TCIL): | Applicant (Active) |
| Steel Authority of India Limited (SAIL): | Did not produce in POI |
| GPT Limited: | Did not produce in POI |

- b) The Tinplate Company of India Limited (TCIL) is a related company of Tata Steel Ltd. Till June 2017, Tata Steel Ltd. supplied hot rolled coils and tin to TCIL which was processed by TCIL into tinplate on job-work basis for Tata Steel Ltd. For this, Tata Steel Ltd. paid processing/job work charges to TCIL. The

production as well as sales of Tinplate were accounted for in the books of Tata Steel Ltd.

- c) With effect from 1st July 2017, TCIL has started buying Hot Rolled Coils from Tata Steel Ltd. and producing and selling the product under consideration on its own account. Accordingly, Tata Steel Ltd. is not engaged in the production of the product under consideration during the POI.
- d) In the application, TCIL's information has been provided for the period starting from 1st July, 2017 onwards. The data/information for the period of 9 months (1st July, 2017 to 31st March 2018) has been annualized, wherever necessary for the year 2017-18 for appropriate comparison with other years.
- e) During the POI, there were only two producers of the products under consideration in India who were actually producing the PUC and both of them are before the Authority. Applicants' share in total eligible Indian production of PUC is 100% during the POI. Accordingly, Applicants clearly satisfy the requirement of standing and constitute 'domestic industry' in India for the product concerned in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules and submit that they are fully competent to bring this petition for imposition of anti-dumping duty on subject goods.
- f) The Designated Authority has correctly found that the Applicants have standing under Rule 2(b) read with Rule 5(3)(a) of the Rules. However, some interested parties have contended that since the Applicants have not supplied information relating to M/s Tata Steel Ltd., the investigation stands vitiated. The domestic industry completely denies and objects to these contentions.
- g) There is no requirement under the Rules for providing information from a party who is not a producer of the PUC during the POI but was a producer of the PUC in the past. The Domestic Industry must only satisfy the 'major proportion' of the total domestic production standard. For a meaningful analysis, it is important to refer to Rule 2(b) of the Rules, which is extracted in relevant part below:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.2. Submission of other interested parties

21. The submissions made by various interested parties with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

- a) It is evident that Tata Steel Ltd has been involved in the production of the PUC in most of the injury period (i.e. up to June 2017) along with TCIL.
- b) Prior to June 2017, the production activities for the product under consideration were split between Tata and TCIL. Even though production seems to have been recorded in the books of Tata, both of them jointly constituted a "producer" of the product under consideration. This is further corroborated by the Annual Report of TCIL for the year 2016-17, wherein TCIL is mentioned as a manufacturer of Electrolytic Tinplate.
- c) The cost and sales data of Tata Steel Ltd has not been provided by the Applicants for the period prior to July 2017, despite Tata and TCIL being related entities.
- d) Applicants have not provided any verifiable evidence in the non-confidential form to substantiate the job-work relationship that existed between Tata and TCIL for the purpose of enabling the interested parties to make meaningful comments.
- e) Since non-provision of data for the entire injury period by TCIL and Tata Steel Ltd will affect the initiation and injury determination and render TCIL and Tata Steel Ltd non-cooperative, the current investigation should be terminated.
- f) Pursuant to rendering TCIL and Tata non-cooperative, JSW Vallabh will no longer have the requisite standing for the purposes of present investigation. Therefore, for all purposes, the present investigation ought to be terminated.
- g) The cost of HR in the PUC is at least 60% of the cost of PUC (depending on the grade and finish). The price at which the raw material is transferred from Tata to TCIL must be assessed. It must be ensured that the HR cost considered for the domestic industry is reflective of the market price during the relevant period and that a bulk of the profit is not loaded on Tata in order to reflect greater injury in TCIL's records.

- h) A transfer pricing agreement between the parties would probably set the threshold for a minimum price, whereby the Designated Authority must carefully assess the transfer price and not allow the HR transfer cost between the two entities to be too high.

D.3. Examination by the Authority

22. The application for imposition of anti-dumping duty has been filed by M/s. JSW Vallabh Tinplate Private Limited and M/s. The Tin Plate Company of India Limited. In the application, it has been stated that there are two more known domestic producers of the product under consideration, namely, Steel Authority of India Limited and GPT Limited. However, these two companies have not produced the product under consideration during the POI. In fact, Steel Authority of India Limited has not produced the subject goods during the entire injury period.

23. Up to June 2017, M/s Tata Steel Ltd supplied HR Coils to M/s. The Tin Plate Company of India Limited which was processed into Tinplate by M/s. The Tin Plate Company of India Limited on job-work basis for M/s Tata Steel Ltd. For this, Tata Steel Ltd. paid processing/job work charges to M/s. The Tin Plate Company of India Limited. The production as well as sales of Tinplate were accounted for in the books of Tata Steel Ltd. Since July 2017, M/s. The Tin Plate Company of India Limited started buying Hot Rolled Coils from Tata Steel Ltd. and producing and selling the product under consideration on its own account.

24. During the POI, there were only two companies, namely M/s. JSW Vallabh Tinplate Private Limited and M/s. The Tinplate Company of India Limited which produced the product under consideration in India, and therefore Applicants together account for 100% of the Indian production. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

25. In view of the above, it is obvious that the Applicants constitute a major proportion of the total domestic production, and therefore have a clear standing for the purposes of this investigation. They have not imported the product under consideration and have claimed not to be related to any of the importers and exporters.

26. Accordingly, the Authority holds that the Applicants constitute ‘a major proportion’ of total Indian production of the like product and that the Applicants satisfy the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the Rules and constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the Rules.

27. As regards the submission that a holistic injury assessment cannot be made without the information of Tata Steel Ltd., it is noted that this issue has been examined in detail under the ‘Injury and Causal Link’ section of these Final Findings. Similarly, the issue of whether or not Hot Rolled Coil has been transferred to M/s. JSW Vallabh Tinplate Private Limited and M/s The Tinplate Company of India Limited by their related parties at an arm’s length price has been also dealt with under the ‘Injury and Causal Link’ section of these Final Findings.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- a) Detailed submissions have been filed wherein the deficiencies in the responses filed by various interested parties have been highlighted and it has also demonstrated how the non-confidential version of the responses fail to disclose even the bare minimum information in the garb of confidentiality.
- b) It is submitted that various interested parties have committed gross breach of the guidelines issued by the Authority with reference to confidentiality requirements vide Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018.
- c) Applicants have disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of Rules and Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018.

E.2. Submissions by other interested parties

29. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a) Submissions of the interested parties are in consonance with the Trade Notice No. 10/2018.
- b) The Applicants have alleged that several Japanese Mills have not provided the channel of sales to India, citing this as an instance of excessive confidentiality. However, Trade Notice 10/2018 does not require

- parties to provide channels of trade in non-confidential form in the first place, since it is sensitive commercial information.
- c) Annexure I of the said notice specifically illustrates how the information should be provided by the domestic industry in non-confidential version of their application/response.
 - d) The Applicants have not complied with the trade notice, and this has impaired the respondents' ability to defend their interest.
 - e) The information of transfer price of Hot Rolled Coil from both Tata Steel & JSW to their associate companies has been concealed as confidential. It has been observed from the attached audited balance sheet of Tata Steel that they enjoy EBITDA margin of 29% which is an abnormally high margin.
 - f) Applicants have kept certain economic parameters as confidential and without such information a meaningful examination of injury parameters of the domestic industry is not possible.
 - g) The claim of confidentiality by Applicants is excessive with respect to following factors:
 - i. Information relating to the individual production and sales of both the Applicants
 - ii. The information in format L
 - iii. Sales realization in format H
 - h) The decision of Supreme Court in *Sterlite industries (India) LTD. v. Designated Authority* is relevant for the present case. The Hon'ble Supreme Court in Sterlite Industries case has held that confidentiality under Rule 7 cannot be "automatically assumed". Under Rule 7, the Designated Authority has to be satisfied regarding the confidentiality of the material. Even if the material is confidential, the Designated Authority has to ask the parties providing the information, on confidential basis, to furnish a non-confidential summary thereof. Under Rule 7(3), Designated Authority can also come to the conclusion that confidentiality is not warranted and it may, in certain cases, disregard that information.
 - i) A statement of reasoning with regard to the same is to be submitted. A mere statement which states "summarization of legal documents is not possible" cannot fulfil the legal requirement.
 - j) It is a requirement under the trade notice and Rule 7 of the Rules that the non-confidential version of the Application is required to have confidential data indexed and summarized.
 - k) The non-confidential summary is supposed to give details to permit a reasonable understanding of the substance of information furnished on confidential basis. Paragraph (vi) of Trade notice explicitly states that any submission made without a meaningful non-confidential version of confidential version shall not be taken on record by the Authority.

E.3. Examination by the Authority

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

31. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties

32. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority has also duly noted the submissions made by interested parties citing the decision of the Hon'ble

Supreme Court of India in the Sterlite Industries case and emphasizing the point that confidentiality under the Rules cannot be automatically assumed. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by domestic industry

33. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a) The Respondents have submitted that levy of anti-dumping duty will create a monopoly for the Applicants and will not be in public interest. The Applicants do not want to create any kind of monopoly in India. The imposition of anti-dumping duty would allow the domestic producers to survive which would ultimately be in the interest of Indian users as they would not be left at the mercy of imports. A healthy and thriving domestic industry in India would be in everybody's interest. The imposition of anti-dumping duty would therefore be in public interest.
- b) On 31st May 2019, the Pakistani National Tariff Commission imposed a definitive anti-dumping duty on imports of tinplate from China, EU, South Africa, and USA to protect their domestic industry from the dumped imports.
- c) The Indonesian authorities have also extended a definitive anti-dumping duty on imports of tinplate coil/sheet from China, Chinese Taipei and Korea RP.
- d) The US Department of Commerce imposed anti-dumping duties on imports of certain tin mill products from Japan in the year of 2000 and the same is continuing even after the third sunset review investigation conducted by US Department of Commerce recently in 2017.
- e) It is clear that the subject countries are export oriented and have been dumping their products into many countries including India.

F.2. Submissions made by other interested parties

34. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a) There are more than 7000 units across India which use non-prime tinplate. These units create employment for around 2 lakh people. There are customers who buy daily/weekly and are walk-in customers whose businesses survive because of the accessibility to non-prime tinplate products.
- b) FSSAI Guidelines prohibit 15-liter edible oil cans from being reused. Effective enforcement will increase the requirement by about 200,000 MT of tinplate.
- c) Plastic is being replaced by tinplate. Lube oil and enamel paint manufacturers are in discussion with the Association for assisting them in replacing plastic with tinplate. This requirement will be about 100,000 MT. There is a natural growth in consumption in existing sectors of about 10% which is about 75,000 MT per annum. There is an untapped market for food cans, crowns for glass bottles, closures, decorative cans and increasing use in Aerosol cans. Accordingly, the demand for PUC is going to increase significantly in the coming years. The domestic industry does not have the capability of meeting this increase in demand.
- d) Tinplate is a key packaging material for paints, insecticides and many other products, which cannot be stocked and must be immediately packed and sent to the market. Any anti-dumping duty will break this supply chain.
- e) The imposition of anti-dumping will disproportionately hurt the large number of people employed in the small and micro segment who will not have alternative employment opportunities.
- f) The tinplate user industry has suffered from high tinplate prices and is not able to face competition from substitute materials. This has resulted in leaders like Poysha, Metal Box shutting operations.
- g) The tinplate user industry is suffering in terms of capacity utilization, profitability and are struggling to survive. Customs duties must be reduced so that tinplate is available at more competitive price to be an effective and environment friendly packaging material.
- h) Levy of duty will establish monopoly of Applicants and will not be in public interest.

- i) In case an anti-dumping duty is imposed, it will increase the input and final cost of products, making them unviable and uncompetitive in comparison to other countries such as China, Bangladesh and ASEAN nations. This will result in the closure of thousands of small-scale units manufacturing products using non-prime material in India.
- j) It will further result in sharp increase in direct import of final products from China, Bangladesh, Pakistan, etc.
- k) Europe and USA should be excluded from the scope of subject countries. Europe has 12.5% import duty plus cess, plus bank charges, plus clearing charges, plus bank finance, plus inland cost. Similarly, USA has a punitive import duty of 27.5% plus cess, plus bank charges, plus clearing charges, plus bank finance, plus inland cost. Also, the figures of imports have not gone up significantly in the years of investigation. Therefore, USA and Europe should be excluded.
- l) Indian mills are already protected by an import duty of 12.5% plus cess plus clearing charges, plus local port charges, plus domestic inland transport. There is a minimum additional cost of 25%. Many countries have zero percent import duty even with local production because tinplate is considered packaging material and not regular steel. Tinplate is niche product with limited production across the world.
- m) The duties that USA has imposed on Japanese tin mill products have been in existence from around the year 2000. However, there has been no change in the volume of Japanese exports of tin mill products to the USA despite the existence of anti-dumping duties. Accordingly, it can be reasonably deduced that there could be no trade diversion of Japanese exports to India due to the existence of duties in the USA on Japan.

F.3. Examination by the Authority.

35. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty will not be in public interest, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

36. Fair competition in the Indian market will not be adversely impacted by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply. Monopoly cannot be created, since there are already two producers of the product under consideration in the country.

37. With regard to exclusion of USA and EU from the investigation, it is noted that the Authority examines whether the imports are coming into India at dumped prices and whether these dumped imports are causing injury to the domestic industry. Merely because imports from USA and EU are subjected to higher duty as compared to other subject countries, it cannot be a ground to exclude USA and EU from the scope of the investigation.

38. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

39. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

40. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

- (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions by the Domestic Industry

41. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a) Since no producer/exporter from Korea RP, USA and EU has filed the questionnaire response and no information has been provided by them, it is clear that producer/exporter of the product under consideration from Korea RP, USA and EU have accepted that they are dumping the product under consideration into India.
- b) It is submitted that the Authority should calculate the dumping margin for Korea RP, USA and EU based on the information provided by the Applicants.
- c) Significant dumping margin exists in respect of imports of product under consideration from each subject country.
- d) Dumping margin for the producers/exporters from Japan shall be calculated based on the exporters' questionnaire response filed by them provided their response is complete and satisfies the requirement of the Authority.
- e) The cost for producing prime and non-prime products is the same and does not affect the calculation of normal value and/or dumping margin.

G.1. Submissions by the other interested parties

42. The following submissions have been made by other interested parties:

- a) Participation of a producer/exporter is a solely commercial decision and the same cannot be used against them. The submission that non-participation amounts to dumping is flawed.
- b) The Japanese Mills submit that some of the major producers from Japan have filed their questionnaire responses in prescribed format within prescribed timelines and the same may be taken into consideration by the Designated Authority for the purposes of calculating the normal value and export price. Accordingly, the averment of the Applicants that the dumping margin is significant ought to be rejected.
- c) Dumping occurs when the export price of goods imported into India is less than the normal value of goods sold in the domestic market of the exporter. The Applicants have not given the domestic price of materials sold in the domestic market abroad. This is surprising because TATA Steel has its own sister company in Europe.
- d) Imports at cheap or low price does not per se indicate dumping. The imported materials are 'waste' products since they are not in the desired specification of the customer. Non-prime materials imported are compromised materials available in all kinds of specification which cater to the requirements of small and micro industry.
- e) Producers/ exporters are not exporting the products at low prices. They sell the products through auctions. Normal bidding procedure is followed, and the products are sold at "normal values". These products are also available to domestic users.
- f) Interested parties disagree with the computation of "normal value." These goods are sold in open auctions and tenders and are available at same prices to domestic customers of exporting country. The method, which is used by the Applicants, will result in the price of prime tinplate. However, 95% of the material used by India is non-prime which is not comparable with prime tinplate.
- g) It is submitted that it is not possible for TCIL to have no access to prevailing prices in Europe when Tata Group is producing tinplate in Europe also. The Applicants have calculated the normal value of the goods by taking the pricing of Prime HRC in subject countries and adding utilities and cost of conversion and a

decent profit of margin as per their initial petition. There is no detailed information available as to how the Applicants have computed the normal value.

- h) The non-prime products are sold on auction or tender basis and participants include domestic service centres and local Can companies, international traders. The winners of auction or tender are free to sell within their domestic market. The auctions and tenders are highly competitive and products are sold at the highest price. Non-Prime material sold to other countries is at prices similar to the prices to India.
- i) The Prime prices from EU, USA, Korea and Japan are higher than domestic prime prices of the Applicants.

G.3. Examination by the Authority

43. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring the following producers and exporters, none of the other producers/ exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. JFE Steel Corporation, Japan
- ii. JFE Shoji Trade Corporation, Japan
- iii. Metal One Corporation, Japan
- iv. Marubeni Itochu Steel (MI Steel), Japan
- v. Nippon Steel Corporation, Japan
- vi. Nippon Steel Trading Corporation, Japan
- vii. Ohmi Industries Limited, Japan
- viii. Tetsusho Kayaba Corporation, Japan
- ix. Toyto Tsusho Corporation, Japan
- x. American International Corporation, USA
- xi. Ferreum NV, Belgium (EU)

G.3.1. Determination of Normal Value and Export Price for producers and exporters in EU

44. The Authority notes that none of the producers/exporters of the product under consideration from the European Union have participated in the subject investigation. Since none of the producers and exporters in EU has submitted any evidence with regard to the normal value and export price of the subject goods, the dumping margin is proposed to be determined based on best facts available.

G.3.2. Determination of Normal Value and Export Price for producers and exporters in Korea RP

45. The Authority notes that none of the producers/exporters of the product under consideration from Korea RP have participated in the subject investigation. Since none of the producers and exporters in Korea RP has submitted any evidence with regard to the normal value and export price of the subject goods, the dumping margin is determined based on best facts available.

G.3.3. Determination of Normal Value and Export price for producers and exporters in USA

46. The Authority notes that none of the producers/exporters of the product under consideration from the USA have participated in the subject investigation. Since none of the producers and exporters in the USA has submitted any evidence with regard to the normal value and export price of the subject goods, the dumping margin is determined based on best facts available.

Methodology for determination of normal value for producers and exporters in EU, Korea RP and USA

47. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in subject countries, the Designated Authority has constructed the normal value for EU, Korea RP and USA by taking into account the HR prices prevailing in each subject country and adopting consumption norms, other raw material cost, conversion cost, primary packing cost, selling, general & administrative cost of the most efficient constituent of the domestic industry. A reasonable profit margin has been added for constructing the normal value. Accordingly, the Normal Value for all the producers/exporters from EU, Korea RP and USA for the subject goods has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Methodology for determination of export price for producers and exporters in EU, Korea RP and USA

48. In the absence of co-operation by any producer from EU, Korea RP and USA, the authority has determined the net export price based on official transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments for ocean freight, insurance, inland freight, bank charges and commission and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

G.3.4. Determination of Normal Value and Export Price for producers and exporters in Japan

JFE Steel Corporation, Japan

49. JFE Steel Corporation filed its exporter's questionnaire response on September 21, 2019 and upon perusal of the same, it was found that the response filed by them was not in line with the prescribed questionnaire format. The Authority also issued a deficiency letter to JFE Steel Corporation citing the discrepancies in the response filed by them. However, JFE Steel Corporation did not respond to the deficiency letter issued by the Authority and did not provide the complete information. In fact, they have not provided any information relating to their cost of production of the product under consideration.

50. In the absence of information relating to cost of production, it would not be possible for the Authority to examine whether or not the domestic selling price is in the ordinary course of trade for JFE Steel Corporation.

51. Therefore, in the absence of complete information from JFE Steel Corporation, the exporters questionnaire response submitted by them is rejected and no individual dumping margin and injury margin is determined for JFE Steel Corporation.

Nippon Steel Corporation ("NSC")

Normal Value

52. During the POI, NSC has sold the subject goods in the domestic market to related and unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.

53. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since the profit-making transactions were more than 80%, the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

54. NSC has claimed adjustments on account of inland freight, insurance, credit cost, storage and other expenses. The authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for NSC has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

55. NSC has filed a questionnaire response along with its related/unrelated trading companies, namely, Nippon Steel Trading Corporation ("NSTC"), MI Steel, Metal One Corporation ("Metal One"), Toyota Tshusho Corporation ("TTC") and Tetsusho Kayaba Corporation ("TKC"). The Authority notes that one of the related trader, NSTC has exported directly to Indian customers and also through other unrelated traders, namely, TKC and Kowa Company Ltd ("Kowa"). NSC has submitted that during POI, it has exported *** MT to India through above mentioned related/unrelated traders. The traders have reported that they have exported *** MT to India during the POI (the difference being on account of timing difference). The quantity reported by traders has been adopted by the Authority as exports to India by NSC for determining the dumping and injury margin.

56. The various channels of exports to India and the quantity exported through these channels is shown in the table below:

| Export Channel | Exports to India (MT) | Quantity% | Cooperating (Yes/No) |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| NSC-NSTC-India | *** | *** | Yes |
| NSC-NSTC-TKC-India | *** | *** | Yes |
| NSC-Metal One-India | *** | *** | Yes |
| NSC-MI Steel-India | *** | *** | Yes |
| NSC-TTC-India | *** | *** | Yes |
| NSC-NSTC-Kowa-India | *** | *** | No |
| Total | *** | *** | |

57. The Authority notes that one of the traders, namely, Kowa has not submitted the exporters questionnaire response containing the requisite information for the said *** MT quantity exported to India.

58. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered verified actual data of the producer NSC for *** of the quantity (*** MT) shipped to India by NSC for which complete chain of responses has been submitted with the Authority. NSC has claimed adjustment on account of shipping, storage, credit cost and insurance and the same have been allowed. The authority notes that some of the traders have exported the subject goods to India at a price which does not cover for traders' expenses. The authority has, therefore, made appropriate adjustments on account of traders' expenses also.

59. With respect to the determination of export price, the Authority notes the provisions enshrined in Explanation (b) to sub-section (1) and sub-section (6A) of Section 9A of the Act which read as follows:

“(1) Explanation (b) “export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

(6A) The margin of dumping in relation to an article, exported by an exporter or producer, under enquiry under sub-section (6) shall be determined on the basis of records concerning normal value and export price maintained, and information provided by such producer or exporter:

Provided that where an exporter or producer fails to provide such records or information, the margin of dumping for such exporter or producer shall be determined on the basis of facts available.”

60. Further, Rule 6(8) of the Rules provides as under in this regard:

“(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.”

61. In view of the above provisions, as regards the export price for *** of the export quantity (*** MT) for which complete chain of responses containing the requisite necessary information have not been submitted to the Authority, export price of this quantity has been calculated based on the facts available, in terms of Rule 6(8) of the Rules and in terms of Section 9A (6A) of the Act. The Authority has used adverse facts available for determination of net export price and landed value with respect to *** of the quantity (*** MT) exported to India by the producer NSC.

62. Accordingly, the export price for NSC, the Japanese producer has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided and exports to India for which complete chain of information has not been provided. The export price so determined for the producer NSC is shown in the Dumping Margin Table below.

G.3.5. Dumping Margin Table

63. The dumping margin during the POI for all producers/exporters from the respective subject countries is given in the table below:

| Country of Origin and/or Export | Producer | Normal Value/ CNV (USD) | Net Export Price | Dumping Margin (USD) | Dumping Margin | Dumping Margin % Range |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Japan | Nippon Steel Corporation, Japan | *** | *** | *** | *** | 30-50 |
| Japan | Other than Nippon Steel Corporation | *** | *** | *** | *** | 80-100 |
| USA | Any | *** | *** | *** | *** | 140-160 |
| EU | Any | *** | *** | *** | *** | 110-130 |

| Country of Origin and/or Export | Producer | Normal Value/ CNV (USD) | Net Export Price | Dumping Margin (USD) | Dumping Margin | Dumping Margin % Range |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Korea RP | Any | *** | *** | *** | *** | 40-60 |

64. The Authority notes that the dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant for all the subject countries.

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

65. The domestic industry has made the following submissions in this regard:

- a) Rule 11 of the Rules read with Annexure II pertain to the principles governing the determination of injury during an anti-dumping investigation. Paragraph (i) & (ii) of Annexure II read as follows:

“(i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic like article and (b) consequent impact of these imports on domestic producers of such products”

“(ii) While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the designated authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.”

- b) The domestic industry has already supplied all the relevant data/information to the Designated Authority establishing dumping, injury and causal link between dumping and injury. The evidence provided by the Domestic Industry was, thus, sufficient to justify commencement of the present investigation. Further, the Authority, in the initiation notification dated 28th June 2019, has duly noted that sufficient evidence of dumping, injury and causal link between dumping and injury exists to justify initiation of the present investigation.
- c) The interested parties' contention that the domestic sales of the Applicants have moved up from 100 to 512 indexed points from the base year to the POI is flawed, since TCIL only commenced sales w.e.f. July 2017. For an accurate analysis of sales, the trend of domestic sales of all Indian Producers must be taken into account. If seen in that context, the rise in sales during POI has only been by 6 indexed points from the base year.
- d) There is no requirement under law to examine the rise in imports vis-a-vis the rise in demand. The law requires examination of imports in absolute and relative terms, which has clearly been done in this case. The subject imports have increased by 13 indexed points in absolute terms and by 6 indexed points in relation to consumption.
- e) Even though the domestic sales have increased, the market share of the domestic industry has remained flat in the POI, while the share of imports has risen by 12 points in 2016-17 and 2017-18, and by 6 indexed points in the POI as compared to the base year. A rise in demand has not benefitted the Domestic Industry in any manner, as the additional demand has been captured by low-priced dumped imports.
- f) Applicants submit that the dumped imports coming from subject countries in significant volumes is the only cause of injury being suffered by them and there exists a causal link as between the injury suffered by the domestic industry and increasing low priced dumped imports coming into India.
- g) Domestic Industry has demonstrated that the imports coming into India from all the subject countries are above de-minimis level. Producers from USA, EU, and Korea have not even participated in the said investigation and have not rebutted any of the claims made by the Applicants. The claims made by Japan for an individual assessment are invalid for the following reasons:
- i. Japan has not refuted dumping by its producers/exporters into India. Applicants have made detailed submissions regarding dumping being done by Japanese producers/exporters, which are above the de-minimis mark.

- ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the product under consideration offered by the domestic industry in the Indian market. Japan's imports of the PUC are competing with the like articles of the domestic industry as well as other imported goods. In fact, significant portion of the Japanese imports consist of non-prime goods.
- h) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the like article offered by the domestic industry in the Indian market.

H.2. Submission by other interested parties

66. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, considered relevant by the Authority, are as follows:

- a) Applicants have averred that cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as per Article 3.3 of the AD Agreement and Rule 11 read with Annexure II (iii) of Rules.
- b) Applicants have completely disregarded the fact that the DGTR manual as well as the AD Agreement specify that conditions of competition between imported products should be considered while determining whether cumulation is appropriate.
- c) The Applicants have failed to provide any reliable evidence to show that it is appropriate to conduct a cumulative assessment of the effect of subject imports despite the differences between import behaviour and product categorization between subject countries.
- d) The factual matrix of the present case justifies a de-cumulated assessment of injury for the imports from Japan. The price movement is completely different w.r.t. Japanese imports. As compared to imports from other subject countries, Japan's price declined while price from the other subject countries increased. On the other hand, in 2017-18, price from other subject countries declined while the price from Japan increased. In the period of investigation, the price from the other subject countries increased slightly while the price from Japan increased notably.
- e) As per Article 3.3 of the AD Agreement and Rule 11 read with Annexure II (iii) of Rules, the Designated Authority may conduct a cumulative assessment of the effect of imports if the following conditions are satisfied:
 - i. The margin of dumping from each of subject countries is above de minimis;
 - ii. The volume of imports from subject countries is above the prescribed limits; and
 - iii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of conditions of competition between imported products inter-se and also between the like domestic article and the imported articles.
- f) It is submitted that with the existence of the word "and" in the above provision, it becomes necessary that all the above elements co-exist to justify the determination of cumulative assessment of effect of subject imports on domestic industry.
- g) Further, according to the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, various other parameters are relevant for determining if it is appropriate to cumulatively assess the effect of imports in light of conditions of competition.
- h) The Japanese Mills submit that the imports in the present investigation have not increased in either absolute or relative terms. It is specifically submitted that the imports from the Subject Countries have decreased in the POI in comparison to the previous year. Moreover, when there was an alleged increase in imports from the Subject Countries in the POI in comparison to the base year, there was a significant improvement in the Applicants performance. The improvement can be evidenced from the data provided by the Applicants. Increase in imports can be attributed to increase in demand.
- i) The Applicants may aver that the increase in sales is on account of the absence of Tata Steel Ltd.'s data in their injury statement – however, the Japanese Mills submit that the Applicants cannot be allowed to have it both ways. Either the data for Tata Steel Ltd should be filed for the first two years of the injury period, or the absence of the data should not be used as an excuse for the improvement in the Applicants' performance.
- j) The analysis conducted by the Applicants is inconsistent for each parameter. The Applicants have considered the trend between the POI and base year to represent injury, whereas, in other instances, they have conveniently assessed the trend between the POI and previous year to represent injury. It is

respectfully submitted that this is a transparent attempt by the Applicants to manipulate figures to maximize their depiction of injury.

- k) The profits have been fluctuating even though the price undercutting has been stable in most of the injury period. Applicants have been making profits in the years where there was alleged price undercutting, indicating that there is no correlation between the alleged imports and the performance or prices of the Applicants.
- l) The disparity between undercutting and profitability is even greater for Japan. The profitability of the Applicants appears to have moved erratically and in complete dissonance with imports from Japan.
- m) It is further submitted that the landed price of the subject imports has not impacted the sales realization or the prices of the Applicants, thus not causing any price suppression/depression in the present investigation.
- n) It is submitted that the Non-injurious price must be determined in accordance with the Rules and the consistent practice.
- o) The Applicants have failed to prove the threat of material injury to Domestic Industry on account of alleged dumped imports from the Subject Countries, specifically, Japan.
- p) The imports as presented by the Applicants have been steady in quantity, with marginal change in trend in line with the growing consumption in India. The Applicants have had a higher Y-O-Y growth compared to the imports in the period of investigation. Thus, there is no volume effect.
- q) The Applicants have been able to increase their price during the period of investigation and there is no sign of depression/ suppression. In TCIL annual statement, they have mentioned about rise in cost of raw material and they have been able to pass on the higher cost to their customers. Prices of the imported goods have also spiked during the POI in line with the global trends.
- r) Imports of non-prime products did not affect the domestic prices of the mills as Non-Prime is a separate market segment. Import of prime is negligible and at higher price than domestic producers.
- s) There has been no decline in output for the Indian producers. On the contrary, best ever production figures for TCIL have been achieved.
- t) There is no loss of sales for the domestic producers. The sales of domestic industry have increased substantially from 100 in the base year to 512 during the period of investigation. Thus, imports from subject country are not causing any harm to domestic industry.
- u) The capacity of the Applicants has also increased every year during the injury period. Applicants are operating at more than 100% capacity utilization which clearly shows no injury. Sales in domestic market have also increased from base year to the POI and so has the market share. Additionally, the overall performance of domestic industry has improved significantly. No negative impact has been shown on employees and the productivity has increased too.
- v) There is no loss of market share. On the contrary, there is an increase in the market share of the local producers. TCIL sells 68% of the Prime Tinplate consumed in India.
- w) There is a very slight decline in cash profits of the producers. The PAT has declined mainly due to the increase in depreciation charge. TCIL in its report for of 2018-2019 has itself mentioned that company's profitability has declined due to a higher raw material cost. Tata steel, which is a raw material supplier to TCIL as well as a majority shareholder in TCIL, is enjoying gross profit margins of 29% in 2018-2019. The Applicants have tried to mislead the Authority by blaming imports as a reason for reduction in profits.
- x) There is no decline in productivity. As stated above, both the Applicants are selling almost everything they can produce as per their capacity. TCIL produced *** MT in 2018-2019 having a capacity of *** MT. JSW Vallabh Tinplate Co. Pvt. Ltd. produced *** MT in 2018-2019 having a capacity of *** MT.
- y) Both producers are enjoying the increase in consumption of Prime tinplate in India. In fact, because of the new FSSAI enforcement for non-reuse of 15 litres oil cans, it is estimated that another 200,000 MT of Prime tinplate will be required by edible oil companies. Both the Applicants, TCIL and JSW Vallabh Tinplate Pvt Ltd (through its parent company JSW steel), are on expansion mode and increasing capacity.
- z) The Applicants have mentioned that the domestic industry is facing significant accumulated inventories. The Authority should consider and evaluate the amount of inventory in comparison to the company's revenue. TCIL's revenues from operations in 2017-2018 were Rs. 1918.69 crores whereas their finished good inventory was only Rs. 45.28 crores as of 31st March 2018 which includes goods in transit. This is just 2.35% of their overall sales. Also, it may be noted that during the last financial year 2018-2019, the

sales were Rs. 2584.50 crores and the inventory for finished goods is Rs. 33.96 crores which also includes goods in transit. This inventory accounts for a mere 1.31% of the entire sales. The Applicants are trying to hide this information by making it confidential.

- aa) The reason for increase in trend of inventory from 100 to 593 is that during the year 2015-2016, TCIL used to do job work for Tata Steel and hence, has 0.76 lacs worth of finished goods inventory in 2015-2016 with revenues from operations Rs. 833.90 Crores. They never used to keep any stock. The Applicants have just tried to take benefit of low inventory in the base year and are trying to mislead the Authority by showing a rising trend.
- bb) TCIL is employing more than 1400 employees and the number has remained the same over the POI and no decline in number of employees can be seen.
- cc) Applicants claim that dumped imports from subject countries is significant and is the only cause of injury to domestic industry by giving examples of GPT and SAIL. It is submitted there exists no causal link between subject imports and injury:
 - i. The Annual Report 2018-2019 of TCIL at page 10 and 28 has noted that the profitability of TCIL declined because of higher raw material costs.
 - ii. According to CRISIL, JSW's profitability was impacted due to delay in passing on the increase in raw material prices. Also, temporary plant shutdown and demonetization have impacted the performance of JSW.
 - iii. According to the Annual Report 2016-17 of JSW at page 25, the revenue of the company dropped due to certain regulatory measures announced by the government.
 - iv. In respect of SAIL and GPT Limited ceasing their production because of imports from the Subject Countries, the Applicants have not provided any evidence whatsoever. Accordingly, the same is a mere conjecture and unsubstantiated.
- dd) Applicants have mentioned that they will soon not be able to repay debts if dumping continues. However, TCIL is debt free. Balance sheets of TCIL and JSW STEEL are extremely healthy.
- ee) No effective information on injury to the domestic industry can be claimed in absence of information regarding Tata Steel. In terms of Rule 11 and Annexure II of Rules, the determination of injury to the domestic industry involves positive evidence and objective examination of the dumped imports in the domestic market for like products and consequent impact of these imports on the domestic producers of such product. In present case, no dumping or consequent injury has been shown.
- ff) It is submitted that the claim of threat of material injury is merely hollow as mandatory grounds under Annexure II of Rules have not been satisfied:
 - i. Significant rate of increase of dumped imports
 - ii. Depressing or suppressing effects of imports
 - iii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports
 - iv. Inventories of the article being investigated
- gg) It is evident that Tata Steel Ltd has been involved in the production of the PUC in most of the injury period (i.e. up to June 2017) along with TCIL. Prior to June 2017, the production activities for the product under consideration were split between Tata and TCIL (though production seems to have been recorded in the books of Tata), whereby both of them jointly constituted a "producer" of the product under consideration. This is further corroborated by the Annual Report of TCIL for the year 2016-17, wherein TCIL is mentioned as a manufacturer of Electrolytic Tinplate.
- hh) The cost and sales data of Tata Steel Ltd have not been provided by the Applicants for the period prior to July 2017, despite Tata and TCIL being related entities.
- ii) Applicants have not provided any verifiable evidence in the non-confidential form to substantiate the job-work relationship that existed between Tata and TCIL for the purpose of enabling the interested parties to make meaningful comments.
- jj) The cost of HR in the PUC is at least 60% of costs of PUC (depending on the grade and finish). The price at which the raw material is transferred from Tata to TCIL must be assessed. It must be ensured that the HR cost considered for the domestic industry is reflective of the market price during the relevant period and that a bulk of the profit is not loaded on Tata in order to reflect greater injury in TCIL's records.

- kk) A transfer pricing agreement between the parties would probably set the threshold for a minimum price, whereby the Designated Authority must carefully assess the transfer price and not allow the HR transfer cost between the two entities to be too high.

H.3. Examination by the Authority

67. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined the various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.

68. The interested parties have made submissions concerning the requirement of a closer examination of the transfer pricing of hot-rolled steel products between TCIL and Tata Steel. In this regard, the Authority has duly examined the transfer pricing of hot-rolled steel products for both JSW Vallabh and TCIL in detail. The authority notes that the pricing of hot-rolled steel products between Tata Steel and TCIL and also between JSW Steel and JSW Vallabh has been done appropriately and at arm's length pricing.

69. Interested parties have also made submissions concerning the requirement of cost and pricing data of Tata Steel, prior to July 2017. The Applicants in the present investigation are JSW Vallabh and TCIL. Both of them have jointly made the application and have submitted all the required information in the prescribed formats. The information provided by both the applicants has been thoroughly verified and the verified information has been considered for the purposes of this investigation. The Authority does not find any merit in the submissions made by interested parties concerning the requirement of cost and pricing data of Tata Steel prior to July 2017 as Tata Steel is not the applicant in the present case. The Authority has exercised appropriate due diligence and verification concerning the pricing of hot-rolled steel products between Tata Steel and TCIL and satisfied itself regarding the correctness of such pricing to take care of the concerns of interested parties.

70. Para (iii) of Annexure II of the Rules states the following:

“(iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of the like article, and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.”

71. The Authority notes that:

- a) The product under consideration is being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effects of imports is thus appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

72. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the product under consideration from the subject countries.

73. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

74. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

H.4.1. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

75. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed shows that it has increased throughout during the injury investigation period and the POI, albeit marginally.

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sales of JSW Vallabh | MT | *** | *** | *** | *** |
| Sales of TCIL | MT | - | - | *** | *** |
| Domestic Sales of Applicants | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 474 | 512 |
| Sales of Other Indian Producers | MT | *** | *** | *** | - |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 0.31 | - |
| Total Domestic Sales of all Indian Producers | MT | *** | *** | *** | *** |
| Imports from subject countries | MT | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| Other imports | MT | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |
| Demand/Apparent Consumption | MT | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | 100 | 100 | 102 | 106 |

b. Import Volumes from subject countries in Absolute Terms

76. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EU | MT | 89,502 | 98,823 | 1,05,419 | 1,15,681 |
| Japan | MT | 47,292 | 52,594 | 45,504 | 41,017 |
| USA | MT | 35,017 | 36,164 | 47,253 | 36,805 |
| Korea RP | MT | 16,212 | 24,193 | 17,913 | 18,995 |
| Dumped imports from subject countries | MT | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| Other Countries | MT | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |
| Total Imports | MT | 2,45,366 | 2,72,274 | 2,66,817 | 2,62,766 |

77. The Authority notes that dumped imports of the product under consideration from the subject countries have increased in absolute terms during the POI as compared to the base year.

c. Subject Country Imports in relative terms

| Particular | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|--|---------|---------|---------|---------|-----|
| Dumped imports from subject Countries in relation to Production in India | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 110 | 104 | 100 |
| Dumped imports from subject Countries in relation to Demand in | % | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|
| India | | | | | |
| Trend | Indexed | 100 | 112 | 112 | 106 |

78. It is seen that the volume of dumped imports in relation to Indian production and demand has kept fluctuating during injury investigation period and POI, with insignificant or no change in the POI as compared to the base year.

d. Market Share

79. The Authority notes that the market share of the subject imports increased in the POI as compared to base year (2015-16).

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Domestic sales of Petitioners | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 474 | 512 |
| Domestic Sales of other producers | MT | *** | *** | *** | - |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 0 | - |
| Domestic sales of Indian producers | MT | *** | *** | *** | **** |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 98 | 106 |
| Import from Subject Countries | MT | 1,88,023 | 2,11,775 | 2,16,089 | 2,12,498 |
| Trend | Indexed | 100 | 113 | 115 | 113 |
| Import from Other Countries | MT | 57,343 | 60,500 | 50,728 | 50,267 |
| Trend | Indexed | 100 | 106 | 88 | 88 |
| Demand | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 102 | 106 |
| <u>Market Share</u> | | | | | |
| Share of Petitioners | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 462 | 481 |
| Share of other Producers | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 0 | - |
| Share of all Indian producers | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 96 | 100 |
| Share of Subject countries | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 112 | 112 | 106 |
| Share of Other countries | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 86 | 82 |

H.4.2 Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

80. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purposes of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the product under consideration from the subject countries.

a. Price Undercutting

81. For the purposes of the price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the price undercutting effect of the dumped imports from the subject countries works out as follows:

| Particulars | UOM | USA | Korea RP | Japan | EU |
|--|-------|---------|----------|---------|---------|
| Landed price of imports | Rs/MT | 44,299 | 50,069 | 55,771 | 45,973 |
| Domestic Selling price excluding freight | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Price Undercutting | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| | % | *** | *** | *** | *** |
| Range | | 35 – 55 | 15 – 35 | 10 – 30 | 30 – 50 |

82. From the aforesaid table, it can be seen that the price undercutting from the subject countries during POI is not only positive but significant. This is creating significant price pressure on the domestic industry.

b. Price Suppression and Depression

83. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

| Particulars | Unit | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Cost of Sales | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 112 | 112 | 125 |
| Selling price | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 107 | 111 | 121 |
| Landed Value | Rs./MT | 42,960 | 42,063 | 42,367 | 47,942 |
| Trend | Indexed | 100 | 98 | 99 | 112 |

84. From the above table, it can be seen that the cost of sales has increased by 25 indexed points during POI as compared to 2015 – 16 but selling price has just increased by 21 indexed points during the same period. It is to be noted that landed value of dumped imports has been lower than cost of sales of domestic industry throughout the injury investigation period thereby exerting price pressure on the domestic industry.

c. Price Underselling

85. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the product under consideration to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

| Particulars | Unit | POI (Rs/MT) | POI (USD/MT) |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| <u>EU</u> | | | |
| Landed Price | Per MT | 45,973 | 666 |
| Non-Injurious Price (NIP) | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | % | *** | *** |
| Price underselling | % Range | 35 – 55 | 35 – 55 |
| <u>Japan</u> | | | |
| Landed Price | Per MT | 55,771 | 808 |
| Non-Injurious Price (NIP) | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | % | *** | *** |
| Price underselling | % Range | 10-30 | 10-30 |
| <u>Korea RP</u> | | | |
| Landed Price | Per MT | 50,069 | 725 |
| Non-Injurious Price (NIP) | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | % | *** | *** |
| Price underselling | % Range | 25-45 | 25-45 |
| <u>USA</u> | | | |
| Landed Price | Per MT | 44,299 | 642 |
| Non-Injurious Price (NIP) | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | Per MT | *** | *** |
| Price underselling | % | *** | *** |
| Price underselling | % Range | 40 – 60 | 40 – 60 |

H.4.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

86. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

87. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions. It is to be noted that up to June 2017, Tata Steel Ltd. supplied hot rolled coils and tin to TCIL which processed them into tinplate on job-work basis for Tata Steel Ltd. With effect from 1st July 2017, TCIL has started buying Hot Rolled Coils from Tata Steel Ltd. and producing and selling the product under consideration on its own account. Accordingly, Tata Steel Ltd. is not engaged in the production of the product under consideration during the POI. During the POI, there were only two producers of the products under consideration in India, namely, TCIL and JSW Vallabh, who were actually producing the PUC.

88. In the application, TCIL's information has been provided for the period starting from 1st July, 2017 onwards. The data/information for the period of 9 months (1st July, 2017 to 31st March 2018) has been annualized wherever necessary for the year 2017-18 for appropriate comparison with other years.

89. Given the peculiar facts of the case, the economic parameters of the domestic industry have been analysed in the following manner:

- A comparison has been done only between 2017-18 and the POI because TCIL started production and sales on its own account in July 2017; and/or
- Separate assessment has been done for JSW Vallabh and TCIL.

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

90. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---|---------|---------|---------|---------|-----|
| Capacity of Domestic Industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 445 | 445 |
| Capacity of JSW Vallabh | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Capacity of TCIL | MT | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 100 |
| Production of Domestic Industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 566 | 581 |
| Production of JSW Vallabh | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 112 | 112 |
| Production of TCIL | MT | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 103 |
| Capacity Utilisation of Domestic Industry | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 127 | 131 |
| Capacity utilization of JSW Vallabh | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 112 | 112 |
| Capacity utilization of TCIL | % | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 103 |
| Domestic Sales of Domestic Industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 474 | 512 |
| Domestic Sales of JSW Vallabh | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 112 | 110 |
| Domestic Sales of TCIL | MT | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 111 |

b. Profitability, return on investment and cash profits

91. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Profit/(Loss) – Applicants | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 5 | 92 | 52 |
| Profit/(Loss) - JSW Vallabh | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 5 | (47) | (66) |
| Profit/(Loss) – TCIL | Rs/MT | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | | | 100 | 62 |
| Profit/(Loss) – Applicants | Rs lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 5 | 434 | 265 |
| Profit/(Loss) - JSW Vallabh | Rs lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 5 | (52) | (73) |
| Profit/(Loss) – TCIL | Rs lacs | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 69 |
| Cash Profits – Applicants | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 38 | 399 | 318 |
| Cash Profits- JSW Vallabh | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 38 | 7 | (7) |
| Cash Profits – TCIL | Rs Lacs | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 83 |
| ROCE – Applicants | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 48 | 71 | 44 |
| ROCE - JSW Vallabh | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 48 | 23 | 8 |
| ROCE – TCIL | % | - | - | *** | *** |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 62 |

92. From the above table, it is noted that:

- On a comparison of the figures from 2017-18 to the POI, it can be seen that the profit per unit as well of total profit of the Applicants has reduced to almost half.
- In the case of JSW Vallabh, it can be seen that the company was making profits till 2016-17. However, since 2017-18, it has been making huge losses. TCIL's profits have also reduced as compared to 2017-18.
- Following a similar trend as that of profitability, cash profits of the domestic industry have reduced significantly from 399 indexed units in 2017-18 to 318 indexed units in the POI.
- It can be seen that the ROCE of the domestic industry has dropped by 27 indexed units from 2017-18 to the POI. Similarly, ROCE has also reduced if seen individually for JSW Vallabh and TCIL.

c. Employment, productivity and wages

93. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| Employment - DI | Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 569 | 563 |
| Wages | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Trend | Indexed | 100 | 106 | 1,086 | 1,174 |
| Productivity per employee | MT/Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Productivity per day | MT/Day | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 566 | 581 |

94. It is noted that the productivity per employee of the domestic industry has remained constant with negligible change through-out the injury investigation period and the POI.

d. Inventories

95. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|-----|
| Average stock | MT | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | 100 | 85 | 179 | 593 |

96. It is noted that the inventories with the domestic industry have increased during the POI.

e. Growth

97. Profitability and ROCE of the domestic industry has deteriorated during the POI, as compared to 2017-18.

| Particulars | UOM | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | POI |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|------|
| Growth (year to year) | | | | | |
| Production | Y/Y % | - | 2% | 452% | 3% |
| Capacity Utilization | Y/Y % | - | 2% | 24% | 3% |
| Domestic Sales | Y/Y % | - | 5% | 351% | 8% |
| Cost of Sales | Y/Y % | - | 12% | 1% | 11% |
| Selling Price | Y/Y % | - | 7% | 4% | 9% |
| Profit/ Loss | Y/Y % | - | -95% | 1679% | -44% |
| Return on investment | Y/Y % | - | -52% | 46% | -38% |

f. Ability to Raise Capital Investments

98. Domestic Industry has claimed that the current state of its financial position does not allow them to raise capital for fresh investment.

g. Factors affecting domestic prices

99. The domestic industry is able to maintain its selling price in a range. The primary factor not allowing the domestic industry to increase its prices in consonance with the increase in cost and earn a decent return on its investments is the price pressure exerted by dumped imports from subject countries.

H.4.4. Magnitude of Injury and Injury Margin

100. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was

allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows:

| Country of Origin/ Export | Producer | NIP (USD/MT) | Landed Value (USD/MT) | Injury Margin (USD/MT) | Injury Margin % | Range |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| Japan | Nippon Steel Corporation, Japan | *** | *** | NIL | NIL | NIL |
| Japan | Other than Nippon Steel Corporation | *** | *** | *** | *** | 20-40 |
| USA | Any | *** | 642 | *** | *** | 40-60 |
| EU | Any | *** | 666 | *** | *** | 40-60 |
| Korea RP | Any | *** | 725 | *** | *** | 25-45 |

H.5. Conclusion on Injury

101. Based on the above, the Authority notes that the dumped imports of the product under consideration from the subject countries have increased in absolute terms during the POI. Imports of the product under consideration are undercutting the prices of the domestic industry. The imports are also suppressing the prices of the domestic industry in India.

102. The Authority notes that the domestic industry has suffered injury on account of volume as well as price effect of imports, as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. Return on capital employed, cash profits and profits deteriorated significantly during the POI. The above analysis overwhelmingly indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India. Thus, the Authority holds that the domestic industry has suffered material injury.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTUON ANALYSIS

103. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

(a) Volume of imports from third countries

104. The Authority notes that the imports of the product under consideration from non-subject countries are not in significant quantity.

(b) Export Performance

105. The Authority has considered the data for domestic operations of the Applicants for its injury analysis.

(c) Development of Technology

106. None of the interested parties has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

(d) Performance of other products of the company

107. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Applicants does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

(e) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

108. The import of the product under consideration is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(f) Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

109. It is noted that the demand for the product under consideration has increased in the period of investigation as compared to the base year.

I.1. Conclusion on causal link

110. Based on the above, the Authority, thus, concluded as under:

- a) Imports of the product under consideration have increased in absolute terms during the period of investigation. Imports of PUC from subject countries have increased in absolute terms from 1,88,023 MT in 2015-16 to 2,12,498 MT in POI.
- b) There is significant price undercutting/underselling due to low priced dumped imports coming into India. There is price suppression due to low priced dumped imports coming into India.
- c) The Domestic Industry's profitability has been affected. From a total profit of 434 indexed units in 2017-18, profits have reduced significantly to 265 indexed units in the POI.
- d) From cash profit of 399 indexed units in 2017-18, cash profits have reduced significantly to 318 indexed units in the POI.
- e) The return on capital employed (ROCE) of the domestic industry has declined from 71 indexed units in 2017-18 to 44 indexed units during the POI.
- f) There are no trade restrictive practices, technology issues, export performance issues, productivity issues or any other factor which can be attributed to the injury being suffered by the domestic industry.
- g) The demand for the product under consideration has increased during the POI as compared to base year. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry.
- h) The imports from countries other than subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Moreover, the price at which goods are coming from other countries is much higher than the price at which goods are coming from subject countries.

J. POST-DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS

J.1. Submissions by Domestic Industry

111. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows:

- a) The Domestic Industry has requested the Authority to confirm its proposals made in the disclosure statement regarding the scope of product under consideration, standing of domestic industry, dumping analysis and injury analysis in the final findings.
- b) The Domestic Industry has submitted that Chromium-free coatings is just another type of passivation on tinplate and are yet to be accepted universally by various tin-mills in absence of sound credentials. The product has also not been approved by International Tinplate Research Institute, London. Therefore, there is no demand for the product. As and when demand comes in, Indian tin-mills are well placed to produce the same.
- c) The Domestic Industry has also submitted that Bisphenol A free products are nothing but a polymer coating on Tin Free Steel which is part of PUC. Such products are neither in demand in India nor being demanded world over due to its limitations to various can making applications, welding in particular. Existing tin-mill products in India use varieties of Bisphenol A free lacquers. This is well accepted by customers and quality assurance bodies.
- d) The Domestic Industry has requested the Authority to verify if any non-PUC product has been included for the calculation of the landed value and consequent injury margin for Nippon Steel Corporation, resulting in a NIL injury margin. Nippon Steel Corporation exports a product called "Ecokote" to India in which coating or plating is done with a mix of zinc and tin. Another such product manufactured by Nippon Steel Corporation is "Ecotrio" which is a mix of zinc, nickel and tin. These products are quite expensive as compared to the PUC of the present investigation and if such products are included in landed value calculation, it will certainly bring down the injury margin significantly, despite existence of a significant dumping margin.
- e) Pursuant to the India-Japan CEPA, basic customs duty on the imports of PUC from Japan is NIL. Therefore, the Domestic Industry has submitted that the Authority must be cautious while calculating the

landed value of imports coming in from Japan. No basic customs duty should be added while calculating the landed value of Japanese imports. If basic customs duty has been added while calculating the landed value of imports from Japan, the landed value will be inflated, and consequently the injury margin will be lower.

J.2. Submissions by other Interested Parties

Submissions by M/s. Ohmi Industries Ltd.

- a) Tin Free Steel customers use Japanese origin material for keeping high productivity and stable quality for making crown caps. If anti-dumping duty is added on JFE/Toyo Kohan's TFS material, end-consumers will have to bear the burden.

Submissions by Economic Law Practices on behalf of M/s. Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Toyo Kohan Co. Ltd., Japanese Mills

- b) Nippon Steel Corporation has requested the Authority to confirm the injury margin determined for it in the Final Findings. In line with the lesser duty rule applicable to the anti-dumping investigations in India, the Authority is requested to abide by the said rule and accord NIL duty to Nippon Steel Corporation in the final findings.
- c) The Authority has not considered the verified figures that Nippon Steel Corporation and its corresponding traders / exporters have filed. The difference appears to arise predominantly due to the calculation of landed price for a channel comprising of Kowa Company Ltd. which has not participated in the present investigation. The injury margin has been calculated for all channels of sales (including Kowa), even though this company has not participated in the investigation. The Designated Authority is requested to accordingly remove the channel of sales for Kowa from the injury margin calculation.
- d) Request has been made to recommend a fixed form of duty (i.e. NIL USD/MT for NSC) rather than a reference price form for Nippon Steel Corporation.
- e) (i) Polymer Laminated Tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free and (ii) Polymer Laminated Tin Free Steel that are Bisphenol-A/BPA Free (collectively, referred to as "PLT") products are a film laminated product and does not fulfill the criteria "whether lacquered and / or printed or not" provided under the definition of PUC. The observations made by the Authority in its Disclosure Statement have been limited to "Polymer Laminated Tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free".
- f) PLT is technically and commercially different and not substitutable with Domestic industry's products.
- g) The question of determining the demand, production or importation of PLT does not arise. The Authority merely needs to confirm that the above characteristics cause PLT products to fall outside the product scope definition.
- h) As per the questionnaire response submitted by JFE Steel Corporation, there have been imports made of PLT during the POI, contrary to the observation made by the Authority.
- i) The Domestic Industry does not commercially manufacture or produce PLT. Furthermore, the capability to produce this product by the Domestic Industry alone, even if assessed, does not justify the inclusion of this non-PUC within the scope of present investigation.
- j) The Domestic producers, who are opposing the request for exclusions, are required to show that they are commercially producing and selling the products in respect of which an exclusion is sought by the producers from subject countries / users. The Domestic Industry has placed no verifiable evidence on record to show that they have commercially manufactured and sold PLT in India.
- k) Nippon Steel Corporation has submitted that there is a difference in the export price submitted by it and the export price that is being considered by the Authority to calculate the dumping margin. Since the data submitted by it has been verified, the Authority is requested to consider its data for the dumping margin calculation.
- l) The Domestic industry has failed to provide the details of the arrangement between JSW Vallabh and JSW Steel and TCIL and Tata Steel. At the same time, it is observed that the Authority has not provided the basis of its conclusion regarding the same in non-confidential form. Therefore, the interested parties are unable to make meaningful comments on the issue.

Submissions by APJ SLJ on behalf of M/s. Hindustan Tin Works Ltd., M/s. Oricon Enterprises Ltd., M/s. Kaira Can Company Ltd., M/s. Asian Containers, M/s. Shetron Ltd., Metal Containers Manufacturers Association

- m) The Authority has not dealt with submissions relating to (i) product usage, technical and commercial non-substitutability of Prime and Non-Prime products; (ii) separate comparison of the prime material and the non-prime material of the Product under Consideration to arrive at the dumping margin and injury margin; (iii) requirement of information from Tata Steel Ltd. in context of the consistent practice of the Authority and proper injury analysis; (iv) Submissions relating to clear violation of the Trade Notice No. 10/2018 by the Domestic Industry.
- n) The claim of confidentiality by applicant industry is excessive and in violation of Trade Notice No. 10/2018.
- o) The disclosure statement mentions that some documents with respect to transfer pricing of Tata Steel have been provided to the Authority by the Domestic Industry post public hearing. However, no such information has been provided to the interested parties. The respondents submit that in terms of Rule 7, any document that has been filed with the Authority is required to be provided to the interested parties in a non-confidential version. It is submitted that as per Rule 7, unless a non-confidential version of such documents is provided to the interested parties, the Authority cannot rely upon such documents in its decision-making process.
- p) As per the Gujarat High Court judgement in Nirma Ltd.vs.Union of India, all that information which has been used by the Authority in its decision-making process, must be provided to the interested parties for their comments.
- q) A non-confidential summary of the Authority's analysis of Job work charges charged by TCIL to Tata Steel pre-July 2017 and conversion charges claimed by TCIL while claiming injury post July 2017 must be provided to the interested parties.
- r) The case was initiated on June 28, 2019 and statutory time limit of 12 months is coming to an end on June 27, 2020. Therefore, the Authority still has 36 days to call for costing data from Tata Steel and do a proper analysis. It is also pertinent to mention that to properly evaluate the costing of Tata Steel for previous years, the Authority can always seek statutorily allowed extension of time post June 27, 2020.
- s) The Authority has consistently rejected the responses of the exporters wherever information relating to related parties has not been supplied. In this context, the investigation concerning "Flexible Slabstock Polyol" originating in or exported from Australia, EU and Singapore, F.No.14/1/2013-DGAD, dated 11.01.2015 is relevant.
- t) The Authority has in the past rejected the entire response of the exporter on the ground that one of the intermediary, even though unrelated, did not file the questionnaire response. The Authority may kindly refer to the investigation of "Uncoated Copier Paper" originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore, F. No.6/32/2017-DGAD, dated 30.10.2018.
- u) The disclosure statement did not even explain as to how the present case is distinct from the investigation of "Uncoated Copier Paper" originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore and the investigation concerning "Flexible Slabstock Polyol", originating in or exported from Australia, EU and Singapore. The respondents submit that in absence of distinction being drawn from the cases mentioned above, the Designated Authority was bound to follow the principles laid down in the above-mentioned cases.
- v) In terms of the provisions of Annexure II of AD Rules, the Designated Authority is required to look at the trend of the performance of the Domestic Industry. However, since the information pertaining to Tata Steel is not available, the trend regarding the performance of the Domestic Industry is bound to look distorted.
- w) It is important to note that Tata Steel (related party of TCIL) was a domestic producer before June 2017. Further, post introduction of GST, an arrangement was made between the related parties (TCIL and Tata Steel) to show TCIL as the domestic producer. However, apart from the buy-sell arrangement, the operations of both the related parties remained exactly the same. Therefore, the performance of Tata Steel in the period preceding June 2017 assumes relevance for the purpose of a proper injury analysis.
- x) The absence of imports or orders of a product is not a criterion to deny exclusion of a product from Product under Consideration. The Authority is requested to kindly exclude Bisphenol-A/BPA Free and Chromium-free tinplate from the scope of the Product under Consideration.
- y) It is submitted that none of the Indian manufacturers produce Tinplate of width lower than 600mm, T1 temper and bright finish.
- z) Non-prime material is used to manufacture low end products for which the usage of prime tin plates is not necessary. There are final goods for which prime tin plates are required to be used e.g., food items and

there are products for which there is no requirement of usage of prime tin plates e.g., geometric box, lamps, hair clips, curtain rings, paper clips, etc.

- aa) Prime Tinplate requires information to be provided by the purchaser to the supplier when making an order as per clause 6 of Indian Standards 1993 of 2018 and ISO 11949: 2016. The Indian Standards makes it mandatory under Clause 6.2(g) to provide the end use. Note to clause 6.2 mentions that the appropriate steel selection is dependent on the shaping operations such as stamping, drawing, folding, beading and bending and assembly work such as joint forming, soldering or welding.
- bb) Under clause 6.3 of the Indian Standards, the manufacturer is to be provided with information, which makes the order requirement consistent with the end use of the product. Importance is given to the fabrication operation as they are very critical with sophisticated manufacturing operations.
- cc) Half of the consumption of tinplate in India is of non- critical use which is not the case as of any other steel products. Such non-critical products which are mainly produced by the small and cottage industries, are found all over India and do not require Prime Tinplate for the desired end use and applications.
- dd) The Authority also overlooked the important aspect of commercial substitutability of the prime products with non-prime products. There is a difference of around 30% between the commercial prices of the prime and non-prime tin plates.
- ee) While determining the dumping margin as well as the injury margin the Authority has not given due regard to the difference in the physical characteristics as well as the factors affecting price comparability of the prime and non-prime tin plates.
- ff) It is clear that as per Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement, the Authority while determining the normal value is required to give due regard to the difference in physical characteristics and other differences affecting the price comparability. It is an admitted position that the prices of the prime and non-prime tin plates vary significantly.
- gg) The Domestic Industry has admitted to such distinction at various junctures and the Annual Report of TCIL for the year 2018-19 clearly mentions that that it holds 68% prime tinplate domestic market share. Further, Indian Standards also distinguish the prime tin plates with non-prime tin plates.
- hh) It has been the consistent practice of the Designated Authority and the Authorities worldwide to compute dumping margin and injury margin on the basis of the weighted average of individually worked out dumping margin and injury margin for different grades.
- ii) While working out the injury margin the Authority should compare the landed price of prime products with domestic prime products, and non-prime products with domestic non-prime products. While working out the injury margin the Authority should compute the landed value of the imports taking the weighted average of the prime and non-prime tin plates sold by the Domestic Industry. This is for the reason that for determining injury to the Domestic Industry, the weighted average of the products sold by the Domestic Industry represents the correct level of the non-injurious price as well as the landed value sufficient to remove any injury caused to the Domestic Industry.
- jj) It is absolutely clear that the Authority has overlooked the mandatory requirement of Annexure II(iv) while analyzing the injury caused by the imports.
- kk) There is no increase in dumped imports in relation to production in India. In fact, the volume of dumped imports in relation to production in India has declined in the POI as compared to the previous year. Similarly, dumped imports in relation to consumption in India also declined in the POI as compared to 2016-17 and 2017-18. Similar trend is apparent with respect to the allegedly dumped imports in absolute terms where the absolute quantity of imports in POI has declined in the POI as compared to the previous year.
- ll) As regards price undercutting and price/suppression depression, the respondents cannot make any effective comments since the disclosure statement does not contain any analysis pertaining to prime and non-prime tin plates separately.
- mm) The sales of the Domestic Industry have increased from 100 trend points in the base year to 512 trend points in the POI. As compared to the previous year, the sales of the Domestic Industry have increased from 474 in 2017-18 to 512 in the POI.
- nn) TCIL is also exporting the subject goods in significant quantities at prices around USD 900/MT while their domestic selling price is around USD 1000/MT. It is submitted that the imports in India are also happening around 900 USD/MT. This demonstrates that the imports in India are happening at the internationally standard prices.

- oo) Imports from subject countries and other countries declined during the POI as compared to the immediately preceding year. Domestic sales also increased during the POI as compared to the immediately preceding year. It is unclear how inventory can increase so substantially during POI as compared to the immediately preceding year, particularly when demand has increased.
- pp) In 2015-16 and 2016-17, TCIL was producing subject goods (though on job work basis for Tata Steel). It is unclear how the Authority can ignore this fact and consider capacity, production and capacity utilization as “-” (nil) for TCIL in 2015-16 and 2016-17. Here, it is important to mention that conversion activities of TCIL do not change in post and pre-July 2017. In both the periods they were converting Hot Rolled coils into subject goods.
- qq) There is no information in Section IV of the disclosure statement as to how actually the Authority has computed raw material cost, cost of utility, capacity utilization for normation of the cost.

Submissions by Association of Tin-Plate Users

- rr) The Authority’s direction to file submissions by 23rd May 2020 by various interested parties is in violation of the order of the Hon’ble Supreme Court, especially when various interested parties had informed that their offices are closed due to lockdown in Mumbai and other parts of the country. The Authority is once again requested to reconsider its decision and give reasonable time to file comments on the Disclosure Statement.
- ss) In order to impose an anti-dumping duty on the imports, there must be material retardation/material injury to the domestic industry due to the subject imports. However, the economic parameters of the domestic industry have improved significantly.
- tt) Increase in cost of raw material has caused injury to the domestic industry and certainly not the imports from subject countries.
- uu) Capacity has increased from 100 during the year 2015-16 to 445 during the period of investigation. Accordingly, production has also increased sharply during the period of investigation to 581 from 100 during the base year 2015-16.
- vv) It is clear that the sales quantity has increased 5 times during the period of investigation from 100 during the base year 2015-16 to 512 during the period of investigation.
- ww) Market share of domestic industry has increased substantially from 100 during the base year 2015-16 to 481 during the period of investigation. Sales of other Indian producers have also declined significantly from 100 to NIL during the period of investigation. On the contrary, market share of imports from subject countries has remained almost same during the injury period i.e. 30-35%. Imports from other countries have also declined. Thus, the major proportion of market share is held by the domestic industry only.
- xx) No. of employees have increased significantly during the period of investigation to 563 as compared to 100 during the base year 2015-16. Thus, there is no negative trend shown in no. of employees.
- yy) Productivity of the domestic industry has increased substantially during the injury period to 581 as compared to 100 during the base year 2015-16. Thus, there is no injury to the domestic industry.
- zz) GPT Steel Industries Limited closed down because of high debts and an anti-dumping order on Cold rolled sheet/coils which did not allow them to import their substrate tin mill black plate at a competitive price.

Submissions by Tamil Nadu Importers Association

- aaa) The domestic industry is unable to service the entire MSME sector.
- bbb) The Present customs duty of 12.5% plus cess is already very high and is making the landed cost must higher. An imposition of anti-dumping duty will be injurious to the MSME sector.
- ccc) Prime products have a specific usage and non-prime material cannot be used in such specific usages. Prime products are produced as per end-user specific requirements and these are not available on the shelf. Non-prime materials are used by MSMEs. They employ skilled workers instead of high end machines to manufacture non-critical and small items.
- ddd) PUC is not being imported under HS Code 72109090 (Cladded plates used by automobile industry), 7107000 (Pre-painted Galvalume), 72103090 (Electrolytically Plated or coated with Zn), 72124000 (Color coated Steel) and 72259900 (Electrical Steel). These products have a different usage than the PUC. The inclusion of these imports under the PUC has shown an inflated quantity of imports.

J.3. Examination by the Authority

112. The Authority has examined the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

113. The Authority notes that many parties have made submissions before the Authority for the first time after the issue of the Disclosure Statement. Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September 2018 requires interested parties to register themselves with the Authority within 40 days of initiation of investigation. The Trade Notice clarifies that any request for registration at a later stage shall not be entertained. The Authority however notes that such an approach on the part of parties to raise fresh set of issues at the fag-end of the investigation, that too without having participated at any stage of the investigation is not at all appreciated, since the Authority can only address such issues to a certain extent in a time-bound investigation. Further, it also prevents other parties from commenting on the submissions made by such unregistered parties. However, even such arguments have been taken on record and have been duly addressed to the extent possible by the Authority.

114. It has been submitted that Polymer Laminated Tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free and Polymer Laminated Tin Free Steel that are Bisphenol-A/BPA Free (collectively, referred to as “PLT”) products are a film laminated product and does not fulfill the criteria “*whether lacquered and / or printed or not*” provided under the definition of PUC. In this regard, the Authority notes that this submission has been made by the interested parties for the first time at the stage of the post-disclosure comments. No such claim had been made in the past regarding PLT not fulfilling the criteria of the PUC due to the lamination on it. Interested parties have maintained throughout that PLT must be excluded since the domestic industry does not produce/manufacture the same in commercial quantities. In any case, the Authority has examined the submissions made by the interested parties, and it has been noted the PLT are tin plate and tin free steel products with a polymer coating on them. An additional coating on the PUC does not deprive the PUC of its essential characteristics and does not render the product to be beyond the scope of the PUC. Therefore, the Authority holds that PLT is a part of the PUC for the purpose of present investigation.

115. It has also been submitted by an interested party that imports of PLT have been made during the POI. The interested party has provided no credible evidence to substantiate its claim. The interested party has merely produced a section of its questionnaire response to show that it has exported PLT to India during the POI, without providing any supporting documents that the transaction actually pertains to export of PLT. The interested party has also not substantiated its claim by showing the transaction of PLT in the DGCI&S imports transaction data. In any case, the Authority has examined the evidence provided by the interested party, and it has been observed that PLT exports claimed to have been made by the interested party are of *** MT out of *** MT of exports of PUC made by the interested party to India during the POI. This shows that PLT exports claimed to have been made by the interested party constitutes merely 0.006% of the total PUC exports made by the interested party to India. The total imports of PUC from Japan into India during the POI are of 41,017 MT. This means that PLT exports claimed to have been made by the interested party constitutes merely ***% of the total imports of PUC from Japan during the POI. This is a negligible quantity and cannot be considered to be a ‘commercial quantity’ by any stretch of imagination. In fact, the submission made by the interested party concerning PLT exports to India fully supports the view taken by the Authority that there is no real demand in commercial sense for this product in India. The domestic industry has also submitted that as and when the demand for this product arises in India, the domestic producers are well placed to produce the same and meet the requirements of the users.

116. M/s. Nippon Steel Corporation has submitted that the Authority has taken into consideration a different landed value and export price than the one submitted by them for the calculation of dumping margin and injury margin. In this regard, the Authority notes the following provisions in this regard:

(a) Rule 6(8) of the Rules provides as under:

“(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.”

(b) Further, Paragraph 7 of Annex II pursuant to Article 6.8 of the WTO Anti-dumping Agreement provides as under:

“... ..It is clear, however, that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate.”

117. Hence, for the portion of export quantity for which complete chain of responses containing the requisite information have not been made available to the Authority, the individual dumping margin for such producers/exporters has been computed considering the above provisions.

118. In this regard, it is noted that the Authority received the required data only for *** % of the quantity exported by NSC to India. The Authority has used facts available for determination of net export price and landed value with respect to the balance ***% of the quantity (*** MT) exported to India by the producer NSC.

119. The interested parties have laid emphasis and made elaborate submissions on the arrangement between TCIL and Tata Steel. Each of the concerns is addressed as follows:

- i. With regard to the transfer pricing of Tata Steel being provided to the Authority by the Domestic Industry, some interested parties have submitted that no non-confidential version has been provided to them. In this regard, the Authority notes that the transfer pricing details were provided to the Authority during the verification exercise conducted by the Authority. It is the consistent practice of the Authority that the documents collected during the verification exercise from both the domestic industry as well as foreign exporters are not provided to other interested parties. No non-confidential version is prepared for the confidential documents collected during the verification exercise. This practice is in accordance with the established global practices in trade remedy investigations.
- ii. The interested parties have contended that the Authority has consistently rejected the responses of the exporters wherever the value chain was incomplete due to the lack of information supplied by related and unrelated parties. They have relied on the investigation concerning “Flexible Slabstock Polyol” originating in or exported from Australia, EU and Singapore, F.No.14/1/2013-DGAD, dated 11.01.2015 to state that the Authority has consistently rejected the responses of the foreign producers/exporters wherever information relating to related parties has not been supplied. They have also stated that the Authority has in the past rejected the entire response of the foreign producer/exporter on the ground that one of the intermediary, even though unrelated, did not file the questionnaire response, and have relied on the Anti-dumping investigation concerning “*Uncoated Copier Paper*” originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore, F. No.6/32/2017-DGAD, dated 30.10.2018. It has been argued that the response of the domestic industry should also be rejected, since the information of Tata Steel, which is a related party of TCIL, has not been provided. In this regard, the Authority notes that the interested parties have not cited even a single case where the information provided by the domestic industry has been rejected on the ground that the related entity of the domestic industry, which is not engaged in production or sales of the subject goods during the POI but was engaged in the production and sales of subject goods in the past, has not provided complete details as required from a constituent of domestic industry. The interested parties have also not cited any case where complete details have been called for and collected by the Authority from the related entity which is not engaged in production or sales of the subject goods during the POI but was engaged in the production and sales of subject goods in the past. The interested parties are merely citing some cases concerning rejection of responses of foreign producers/exporters due to non-participation by related entities involved in production or sales of subject goods during the POI or unrelated traders involved in export chain to India during the POI of those investigations. The cases cited by the interested parties relate to completely different set of facts and are not at all applicable to the present case. In the cases cited by the interested parties, the responses of foreign producers/exporters were rejected due to (i) non-participation by related entities involved in production or sales of subject goods during the POI because of which the Authority did not have complete details to determine the normal value and dumping margin for the concerned producer/exporter and (ii) non-participation by unrelated traders involved in exports of subject goods to India during the POI because of which the Authority did not have complete details to determine the export price, landed value, dumping margin and injury margin for the concerned producer/exporter. The Authority notes that in the POI of the present investigation, Tata Steel is neither engaged in production of subject goods nor engaged in sales of subject goods and therefore the cases cited by the interested parties are not applicable to the present case.
- iii. One of the interested parties has stated that there is an increase in cost for Tata Steel/TCIL post-July 2017 as compared to the situation prevailing pre-July 2017 due to the change in the operating methodology of both these parties post-July 2017 wherein TCIL started purchasing hot rolled steel from Tata Steel and started producing and selling tinplate on its own account. Due to this change in operating methodology, Tata Steel/TCIL is showing deterioration in profits in the period post-July 2017 as compared to the situation prevailing pre-July 2017. The interested party has also given an example to substantiate its claim in this regard. Firstly, the Authority notes that the example provided by the interested party as a part of its submissions is based on unsubstantiated assumptions, and the figures used in the example do not seem appropriate or accurate. Secondly, in any case, the Authority has clarified in Para 89 of these final findings, that given the peculiar facts of the case, the trend has been analyzed from 2017-18 to the POI, and comparison has not been done between pre-July 2017 and post-July 2017 situation to assess injury to the domestic industry. The Authority has assessed how the economic parameters of TCIL have behaved after TCIL started producing and selling the PUC on its own account from July 2017 onwards.
- iv. It has been contended that the capacity, production and capacity utilization of TCIL should not be NIL in 2015-16 and 2016-17, since they were performing conversion activities for Tata Steel in those years. The

Authority notes that TCIL started producing and selling the PUC on its own account from July 2017 onwards and therefore the contention raised by the interested parties cannot be accepted.

120. With regard to the submission that the Authority has not provided any reasons regarding claims of confidentiality by the domestic industry, it is clarified that the provisions of claiming an information as confidential by an interested party are fully compliant with the WTO provisions. These provisions apply equally to all interested parties i.e. domestic industry, exporters, importers/users. To streamline the filing of non-confidential version of an information claimed confidential in accordance with relevant Rules, the Authority has issued Trade Notice No. 10/2018 dated 7/9/2018. The Authority has duly examined whether the non-confidential versions have been filed by various interested parties in accordance with the relevant Rules and the above Trade Notice and has accepted their claims wherever found suitable.

121. With regard to the contention regarding capability of the Indian manufacturers to produce Tin-plate of width lower than 600 mm, T1 temper and bright finish, the Authority has noted that this is a new claim brought by the interested parties. The interested parties throughout the course of the investigation had claimed that the domestic industry cannot produce tinplate of width lower than 700 mm and this aspect was duly examined and verified by the Authority. The interested parties cannot bring new claims at the end of the investigation. Multiple chances have been provided to the interested parties to present their views, and a new claim at this stage seems to be a tactic to delay the investigation procedure. It reiterated that the domestic industry has provided evidence to show that it produces tin-plate of width lower than 700 mm. No evidence has been provided by the interested parties to prove otherwise.

122. Some interested parties have reiterated their concerns with regard to the difference in the end-use between prime and non-prime products. On the basis of the submissions made by various interested parties, the Authority notes that the end-use for prime and non-prime products is the same in most of the applications. It has also been duly admitted by the Association of Tinplate Users that prime and non-prime tinplate are being used interchangeably in most of the applications. The Authority also notes that there are no firm physical attributes or technical distinctions that differentiate the prime material from the non-prime one. Therefore, excluding non-prime tinplate from the scope of PUC would open floodgates for circumvention. Prime products could be sold as non-prime products at a lower price and could easily circumvent the anti-dumping measures and make the entire exercise of conducting this investigation meaningless. The distinction between prime and non-prime grade of PUC is an issue that Authority has had to address in several investigations, and it has been the consistent practice of the Authority to include both prime and non-prime grade products within the scope of the PUC. In light of the same, the Authority rejects the request made by the interested parties for exclusion of non-prime products from the scope of the PUC.

123. Interested parties have also raised the issue that the Authority has not taken into consideration the difference in physical characteristics and price difference between prime and non-prime products while calculating the dumping and injury margin. In this regard, firstly the Authority notes that exporters/producers from EU, USA and Korea RP have not participated in the subject investigation and therefore the Authority had to base its dumping margin and injury margin determination for these countries based on facts available. Secondly, in case of Japan, only one producer has been treated cooperative and the Authority has determined the dumping margin and injury margin for this co-operative producer based on the data submitted by this party except to the small extent of non-cooperation wherein the Authority has used facts available for this producer. The producer from Japan has in fact not even raised this issue of considering difference in physical characteristics and price difference between prime and non-prime products while calculating dumping and injury margin. Thirdly, it is noted that the request for considering difference in physical characteristics and price difference between prime and non-prime products while calculating dumping and injury margin has been made by importers in India who do not have any information regarding the cost of production and other details required for calculating the normal value, dumping margin, non-injurious price and injury margin. The Authority has duly examined the claims made by the interested parties and has noted that the cost of producing prime and non-prime products is the same. Non-prime products are merely products which have not been able to meet the customization requirement of the customer in the manufacturing process and are, therefore, classified in various nomenclatures such as waste, seconds, defective, misprint, non-prime, etc. Since the cost of production of both prime and non-prime tinplate is same, it is not possible to make hypothetical adjustments while calculating the dumping margin and injury margin as being claimed by the interested parties. The interested parties are essentially arguing for a situation where assuming if the cost of producing prime and non-prime products is USD 1000, and prime products are being sold at USD 1200 and non-prime at USD 800 due to a specification defect, the normal value/NIP for prime products should be calculated based on a price of USD 1200 and non-prime products based on a price of USD 800. Normal value cannot be determined based on loss making sales price because such sales are not deemed to be in the ordinary course of trade. Similarly, non-injurious price needs to be determined based on the actual cost of production in terms of Annexure III to the AD Rules and no hypothetical adjustments can be made to the actual cost of production based on lower selling price of non-prime products. Accordingly, this argument made by the interested parties is not acceptable as the same is against the legal provisions and established practice of the Authority.

Further, the Authority holds that the injury and dumping margin have been calculated for the PUC as a whole. The established WTO jurisprudence under Article 2 of the AD Agreement requires the overall margin of the PUC to be determined.

124. With regard to the contention that Annexure II (iv) has not been complied with while analyzing injury, it is noted that there has been (i) an increase in dumped imports in absolute terms in the POI as compared to the base year; (ii) there is positive price undercutting and price underselling caused by the subject dumped imports; (iii) the domestic industry's economic parameters have deteriorated in the POI. A complete analysis has been done in the relevant portion of the Final Findings.

125. With regard to the contention that no information has been provided in Section IV of the disclosure statement as to how actually the Authority has computed raw material cost, cost of utility, capacity utilization for normation of the cost, it is noted that Section IV of the Disclosure Statement clearly states the methodology adopted by the Authority to compute the NIP and all relevant costs.

126. With regard to the submissions made by the interested parties on the economic parameters of the domestic industry, the same have been elaborately dealt with in the relevant section of the Final Findings.

127. With regard to the contention of analyzing the price suppression/depression separately for prime and non-prime products, the Authority notes that it has analyzed price effect for the PUC as a whole, as per its consistent practice.

128. With regard to the import price being USD 900/MT, which is claimed to be the internationally standard price, the Authority notes that this claim is factually incorrect. The landed value of the imports is much lower than USD 900/MT in the POI, even with the addition of the basic customs duty:

| Country | Unit | Landed Value (Rs/MT) | Landed Value (USD/MT) |
|----------|--------|----------------------|-----------------------|
| EU | Per MT | 45,973 | 666 |
| Japan | Per MT | 55,771 | 808 |
| Korea RP | Per MT | 50,069 | 725 |
| USA | Per MT | 44,299 | 642 |

129. With regard to the contention raised by one of the interested party that the Authority's direction to file comments on disclosure statement by 23rd May 2020 is in violation of the order of the Hon'ble Supreme Court, the Authority notes that it has provided ample opportunity to the interested parties to present their views. The original deadline for filing comments on the disclosure statement was 15th May 2020 which was extended till 23rd May 2020 on the request of the interested parties. The interested parties had thus ample time to file comments on the disclosure statement. The Authority being a quasi-judicial body is under statutory obligation to complete the anti-dumping investigation within 12 months' time- period.

130. The interested parties have argued that PUC is not being imported under certain HS Codes. Firstly, the interested parties have given some 7-digit HS Codes instead of 8-digit HS Codes, making the HS Code unclear. In any case, as per the Authority's understanding, it is noted that most of the said HS Codes are of the 'Others' category and from the DGCI&S transaction-wise import data, the Authority has noted that imports are made under these HS Codes as well. The Authority further clarifies that customs classification is not binding but only indicative in nature, and therefore, the description of the product shall prevail over customs classification. In regard to the contention that inclusion of imports under these HS codes has resulted in inflated quantity of imports, it is noted that while examining volume and value of imports from DGCI&S data, the description of import item is also verified besides HS code and therefore there is no possibility of the import quantity getting inflated.

131. With regard to the submission made by the domestic industry regarding landed value calculation for Nippon Steel Corporation, the Authority has again revisited the workings and it is noted that no non-PUC item has been included in the landed value calculation for Nippon Steel Corporation and also that no addition for basic customs duty has been done while calculating the landed value for Nippon Steel Corporation.

132. Concerns regarding public interest have been adequately addressed in the relevant section of Final Findings.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES.

133. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping duty

would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

134. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product under consideration and downstream goods manufactured using the product under consideration. This might consequently have some effect on the relative competitiveness of the downstream products. However, since levy of an anti-dumping duty is restricted to the amount necessary to redress the injury to the domestic industry, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure. Imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the product under consideration.

L. CONCLUSION

135. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

- a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping.
- b. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- c. Material injury has been caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries.

M. RECOMMENDATION

136. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive antidumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

137. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

DUTY TABLE

| S. No. | Heading/Sub-Heading | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Duty Amount | Currency | Unit |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090 72259900, 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000* | Tin mill flat rolled steel products** | Japan | Any country including Japan | Nippon Steel Corporation | NIL | US\$ | MT |

| S. No. | Heading/Sub-Heading | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Duty Amount | Currency | Unit |
|--------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Japan | Any country including Japan | Any other producer other than S.No. 1 above | 222 | US\$ | MT |
| 3 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Any country other than EU, USA, Korea RP and Japan | Japan | Any | 222 | US\$ | MT |
| 4 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | EU | Any country including EU | Any | 310 | US\$ | MT |
| 5 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Any country other than EU, USA, Korea RP and Japan | EU | Any | 310 | US\$ | MT |
| 6 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | USA | Any country including USA | Any | 334 | US\$ | MT |
| 7 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Any country other than EU, USA, Korea RP and Japan | USA | Any | 334 | US\$ | MT |
| 8 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Korea RP | Any country including Korea RP | Any | 251 | US\$ | MT |
| 9 | -do- | Tin mill flat rolled steel products** | Any country other than EU, USA, Korea RP and Japan | Korea RP | Any | 251 | US\$ | MT |

***Note:** Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

****Note:** Tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. These products are of prime and non-prime category and in all sizes.

N. FURTHER PROCEDURE

138. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER SINGH BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority